राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 17 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

दही में जितना दूध डालते जाओगे वह दही बनता जाएगा वैसे ही जो लोग शंका करते हैं उनके दिल में हमेशा शंका उत्पन्न होती ही रहती है
-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

उम्मीदों भरी यात्रा

इटली के अपूलिया में संपन्न हुए जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आउटरीच सत्र में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस क्रम में तमाम वैश्विक राजनीतिक हस्तियों से उनका मिलना हुआ। इनमें पोप फ्रांसिस भी शामिल थे, जिन्होंने भरपूर गर्मजोशी से मोदी को गले लगाया और विचार-विमर्श किया। मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत में कैथोलिक इसाइयों की संख्या एशिया में दूसरे नंबर पर है। भारत के केरल जैसे राज्यों में ईसाइयों की संख्या खासी है, इसलिए इसे संकेत माना जा रहा है कि मोदी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाया है। जी-7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया के सबसे अमीर और खुद को अत्याधुनिक मानने वाले

मुल्कों की संस्था है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ये सात देश हैं। इनकी ग्लोबल ट्रेड और वैश्विक वित्त प्रणाली पर खासी पकड़ है। इस बार ये सब आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों को लेकर विमर्श कर रहे थे। चूंकि भारत विकसित होती अर्थव्यवस्था है, इसलिए वे उसके सहयोग और लाभ की साझेदारी पर काम करने को इच्छुक हैं। इस सम्मेलन में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र के बारह विकासशील देशों के नेताओं को इसी खास मकसद से आमंत्रित किया गया था। माना जा रहा है कि जी-7 देश चीन और रूस की बढ़ती आर्थिक ताकत को लेकर चिंतित हैं। इस मौके का फायदा उठाने में मोदी सफल होते नजर आ रहे हैं। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस मसले पर बनने वाले अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों द्वारा देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर सख्ती की जा सकेगी। हालांकि यह कहना गलत नहीं है कि इस गुट के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं, जिनके बल पर कोई भी निर्णय जबरन लागू कराया जा सके, मगर भारत को इन देशों से जो सहयोग और लाभ मिल सकते हैं, उनके प्रति यदि मोदी सफल होते नजर आते हैं तो यह देश के भविष्य के लिए बेहतर करने का घटनाक्रम ही कहा जाएगा। निःसंदेह इनसे जुड़े परिणामों के लिए अभी इंतजार करना होगा। मगर कुल मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा सकारात्मक कही जा सकती है, जिसके परिणाम आने वाले वर्षों में यकीनन नमूदार होंगे।

नकेल कसने की तैयारी

मोदी सरकार डीप फेक, गलत सूचनाएं फैलाने या भड़काऊ वीडियो बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दुरुपयोग रोकने के मद्देनजर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। हालांकि यह सब एकदम से नहीं होने जा रहा। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि सरकार जल्द से जल्द इस बाबत कानून बनाकर लागू करना चाहेगी। चुनाव से पहले भी सरकार ने डिजिटल इंडिया विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन उस दिशा में आगे काम न हो सका। गलत सूचनाएं फैलाने या लोगों

को भड़काने की नीयत से डाले गए वीडियो का असर लोक सभा चुनाव में भी देखने को मिला। चुनाव से पहले और चुनाव प्रक्रिया के दौरान इंफ्लूएंसर्स और सोशल मीडिया ने आम जन की इस कदर विश्वसनीयता हासिल कर ली थी कि लोग इस मीडिया पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे हैं। मान रहे हैं कि सोशल मीडिया उन्हें गुमराह नहीं होने देगा और जमीनी हकीकत से उनकी वाकफियत बनाए रख सकता है। भाजपा अपने तईं पूर्ण बहुमत पाने से चूक गई। उसने अपने सहयोगी दलों के साथ मिल कर गठबंधन सरकार तो बना ली है, लेकिन कहीं-न-कहीं उसे महसूस होता है कि सोशल मीडिया ने प्रोपगेंडा करके उसका खेल बिगाड़ दिया। हालांकि चुनाव से पहले ही वह महसूस करने लगी थी कि सोशल मीडिया लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार विरोधी एजेंडा चला रहा है। चुनाव परिणाम देखकर तो उसे तस्दीक ही हो गई कि सोशल मीडिया ने उसकी संभावनाओं पर खासा असर डाला। डीप फेक के मामले भी एक के बाद एक सामने आए हैं, जिनमें सिने तारिकाओं और अन्य हस्तियों की छवि बिगाड़ने के प्रयास हुए। डीप फेक और भड़काऊ वीडियो के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाना और एआई का दुरुपयोग से पूरी दुनिया त्रस्त है। अनेक देशों ने इस बाबत कानून भी बनाए हैं। सरकार चाहती है कि उन देशों के अनुभव से भी लाभ लिया जाए ताकि बनाया जाने वाला कानून ज्यादा-से-ज्यादा असरदार हो सके। सरकार को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी संबंधी प्रावधान को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि सोशल मीडिया और इंफ्लूएंसर इसको ढाल बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार इन माध्यमों पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून को लेकर संजीदा है।

परिधि/ राजीव मंडल

दलबदलुओ सावधान

सियासत के गलियारे से शनिवार को एक सुकूनदेह खबर आई। खबर उस राज्य से आई जहां राजनीतिक दलों के बीच अब तक की सबसे बड़ी टूट हुई। चाचा की राजनीतिक विरासत को एक झटके में हलाल कर दिया गया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अच्छी खबर का लब्बोलुआब यह है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें तीन पार्टियां-कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शामिल हैं, ने ऐलान किया कि जिन नेताओं ने हमारी पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टियों का दामन थामा है, अब उनकी वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तीनों दलों की इस घोषणा से दलबदलुओं को जरूर ठेस पहुंची होगी।

दलबदल को खत्म करने या उसे निष्प्रभावी करने को लेकर वर्षों से मंथन चल रहा है, मगर इसका कोई सर्वमान्य समाधान आज तलक नहीं निकल सका है। हां, जनता जरूर ऐसे दलबदलुओं की फितरत को जानती-समझती है, और उनका इलाज भी जनता ही अच्छे से करना जानती है। अभी संपन्न लोक सभा चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इस चुनाव में वोटर्स ने दलबदलु नेताओं को सिरे से नकार दिया है। आखिरी ओवर में अपनी टीम का साथ छोड़ने वाले नेताओं को जनता ने पांच साल के लिए सियासी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है।

चुनाव से ठीक पहले दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए 25 नेताओं में से 20 को जनता ने हार का उपहार थमाया है। भाजपा ही नहीं बल्कि लगभग सारे दलों के दलबदलुओं का जनता ने यही हाल किया है। चुनावी मैच के आखिरी ओवर में कांग्रेस पहुंचे नेताओं को भी जनता ने दरकिनार कर दिया है। अपने नफा-नुकसान को देखते हुए आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने यह कहने या करने का साहस नहीं दिखाया कि अगर उनकी पार्टी का नेता उन्हें छोड़ने के कुछ दिनों बाद अगर वापसी की चाह रखता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। क्या राजनीतिक दलों में इतनी नैतिकता या शुचिता नहीं है कि वह इधर-से-उधर उछल-कूद करने वालों को अपनी पार्टी में नहीं घुसने देंगे। एक बात तो साफ है कि नियम चाहे कितने भी कड़े बना लीजिए, अगर नेताओं में नैतिकता नहीं रहेगी तो सारे नियम-कायदे बेमानी हैं। देखना है, महाविकास अघाड़ी अपने वचन पर पक्का रहता है या नहीं। वैसे अगर ऐसा होगा तो राजनीति का एक अलग मिजाज जगजाहिर होगा।

हंगामा यूं ही नहीं बरपा

नीट परीक्षा-2024

विनीत नारायण

जब भी कभी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सुनते हैं, तो सबके मन में व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठते हैं। इससे पूरी व्यवस्था में फैले हुए भारी भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। सोचने वाली बात है कि इससे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? महीनों तक परीक्षा के लिए मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के मन में इस बात का डर बना रहेगा कि रसूखदार परिवारों के बच्चे पैसे के बल पर उनकी मेहनत पर पानी फेर देंगे? मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के बाद अब एक बार फिर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 'नीट परीक्षा' में हुए घोटाले पर जो बवाल मचा है, उससे तो यही लगता है कि चंद भ्रष्ट लोगों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।

साल 2016 में पहली बार मेडिकल एंट्रेंस के लिए 'नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट' यानी नीट की शुरुआत हुई। पहले तीन वर्षों में इसे सीबीएसई द्वारा संचालित किया गया परंतु साल 2019 से इन इम्तिहानों की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दी गई। जब से नीट की परीक्षा लागू हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इस परीक्षा की कटऑफ इतनी हाई गई है। यदि एनटीए की मानें तो 'नीट कटऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कटऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कंपटीटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया'। परंतु क्या यह बात सही है?

गौरतलब है कि इस बार की नीट परीक्षा में 67 ऐसे युवा हैं, जिन्हें 720 अंकों में से 720 अंक मिले हैं। ऐसे कई युवा भी हैं, जिन्हें 718 और 719 अंक प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षा पद्धति के मुताबिक असंभव है। 720 के टोटल मार्क्स वाली नीट परीक्षा में हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो 716 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया, तो उसे 715 अंक मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 किसी भी सूरत में नहीं मिल सकते। जाहिर है कि तगड़ा घोटाला हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष नीट परीक्षा दी उनसे जब यह पूछा गया कि इस बार की परीक्षा कैसी थी? तो उनका जवाब था कि इस बार की परीक्षा काफी कठिन थी, कटऑफ काफी नीचे रहेगी। एनटीए द्वारा एक और स्पष्टीकरण भी दिया गया है जिसके मुताबिक इस बार टॉप करने वाले कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। इसका कारण है कि फिजिक्स के एक प्रश्न के दो सही उत्तर हैं। ऐसा इसलिए है कि फिजिक्स की एक पुरानी किताब, जिसे 2018 में हटा दिया

गया था, अभी भी पढ़ी जा रही थी। परंतु यहां सवाल उठता है कि आजकल के युग में जहां सभी युवा एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं, या फिर जहां कोचिंग लेते हैं, वहां पर सबसे संपर्क में रहते हैं। फिर ये कैसे संभव है कि छह साल पुरानी किताब को सही नहीं कराया गया होगा?

अगला सवाल यह भी उठता है कि एनटीए द्वारा किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? जबकि मेडिकल परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के एक आदेश का संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण परीक्षार्थी का समय खराब हो तो किन विद्यार्थियों को किन परिस्थितियों में कितने ग्रेस मार्क्स दिय जा सकते हैं। परंतु गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का यहां उल्लेख किया जा रहा है वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के लिए था, उसी आदेश में यह साफ-साफ लिखा है कि यह आदेश मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा परंतु एनटीए ने न जाने किस आधार पर इस आदेश को संज्ञान में लिया और ग्रेस मार्क्स दे दिए? नीट परीक्षा का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, और अदालत ने नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देखना होगा कि ये दोनों कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं? परंतु जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ा है, इस पर राजनीति भी होने लग गई है, इतना ही नहीं जिस तरह एनटीए ने परीक्षा से पहले ही इसके पंजीकरण में ढील बरती है, वह सब भी सवालों के घेरे में है। टॉपर्स की लिस्ट में कम से कम 6 विद्यार्थी ऐसे हैं, जो एक ही सेंटर के हैं। इस सेंटर को इसलिए भी शक की नजर से देखा जा रहा है कि यहां विद्यार्थी देश के दूसरे कोने से परीक्षा देने आए। बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों में नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं जिन पर जांच चल रही है।

सोचने वाली बात है कि देश का भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थी, जो आगे चल कर डॉक्टर बनेंगे, यदि इस प्रकार भ्रष्ट तंत्र के चलते किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा भी लेते हैं, तो क्या भविष्य में अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे या पैसे के बल पर वहां भी पेपर लीक करवा कर 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' की तरह सिर्फ डिग्री ही हासिल करना चाहेंगे चाहे उन्हें कोई ज्ञान हो या न हो? सवाल सिर्फ नीट की परीक्षा का ही नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रांतों में होने वाली सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगातार घोटाले हो रहे हैं जिनकी खबरें आए दिन मीडिया में प्रकाशित होती रहती हैं। इससे देश के युवाओं में भारी निराशा फैल रही है। नतीजा यह हुआ है कि पिछले 40 बरसों में आज भारत में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक हो गई है।

एक मध्यमवर्गीय या निम्नवर्गीय परिवार के पास अगर खुद की जमीन-जायदाद, खेतीबाड़ी या कोई दुकान न हो तो नौकरी ही एकमात्र आय का सहारा होती है। घर के युवा को मिली नौकरी उसके मां-बाप का बुढ़ापा, बहन-भाई की पढ़ाई और शादी, सबकी जिम्मेदारी संभाल लेती है। पर अगर बरसों की मेहनत के बाद घोटालों के कारण देश के करोड़ों युवा इस तरह बार-बार धोखा खाते रहेंगे तो सोचिए कितने परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाएगा? यह बहुत गंभीर विषय है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को फौरन ध्यान देना चाहिए।

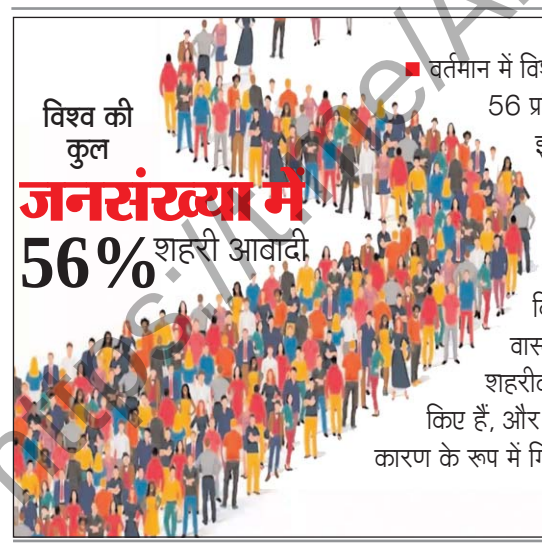

> नीट परीक्षा में 67 ऐसे युवा हैं, जिन्हें 720 अंकों में से 720 अंक मिले हैं। ऐसे युवा भी हैं, जिन्हें 718 और 719 अंक मिले। 720 के टोटल मार्क्स वाली नीट परीक्षा में सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है। जिसने सभी सवाल सही किए तो 720 में से 720 मिलेंगे। एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 अंक मिलेंगे। एक सवाल गलत हो गया तो 715 अंक मिलने चाहिए लेकिन 718 या 719 किसी सूरत में नहीं मिल सकते

■ वर्तमान में विश्व की 8.1 अरब आबादी में से करीब 56 प्रतिशत लोग शहरों या शहरीकृत इलाकों में रहते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में इससे पूर्व कभी इतने लोग शहरों में नहीं रहे

■ बढ़ते शहरीकरण को कुछ लोग विकास का पैमाना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि बढ़ते शहरीकरण ने गर्मी और लू जैसे हालात पैदा किए हैं, और शहरीकरण को अति गर्मी के एक कारण के रूप में गिनाया जाता है

(मीडिया इन्पुट्स)

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बिगाड़ का पता आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों की संख्या बढ़ने से चलता है। 2014 में ऐसे सांसद 34 प्रतिशत थे, 2019 में 43 प्रतिशत रहे और चिंताजनक यह कि 2024 में ये बढ़कर 46 प्रतिशत हो गए हैं। हमारे नागरिक बेहतर के हकदार हैं। बेहतर चुनना जरूरी है। इसके लिए अपनी राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचें।

कौशिक बसु, प्रख्यात अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

अनूठी शख्सियत के मालिक

खेल | मनोज चतुर्वेदी

समृति शेष : हरपाल सिंह बेदी

खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी एक ऐसी शख्सियत थे, जो कम ही देखने को मिलती है। वह अब हमारे बीच नहीं रहे पर उनके साथ बिताए चार दशकों की ऐसी यादें हैं, जिन्हें भुलाना संभव नहीं है। उनका 15 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बेदी साहब से जब भी मुलाकात होती थी, तो उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान होती थी, जिसमें मजा लेने वाला पुट हुआ करता था। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे पर इस अंदाज के बीच ही कई बार कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते थे, जिसका सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता था।

हमें एक किस्सा याद आ रहा है। यह बात नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहने के दिनों की है। उन दिनों एक दिन भारत के महान टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज ने राजधानी दिल्ली के सभी खेल पत्रकारों को होटल ताज मानसिंह में अपने स्युइट में बुलाया। विजय अमृतराज ने कहा कि 'मैंने भारत में खेलों की प्रगति के लिए एक योजना बनाई है, जिसे मैं प्रधानमंत्री नरसिंह राव को सौंपने जा रहा हूं।' इस संबंध में तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे पर बेदी साहब ने उनसे कहा कि कल आप अखबारों में अच्छे से छप जाएंगे। पर योजना का क्या हुआ हम किसी को मालूम भी नहीं पड़ना है, क्योंकि आप अमेरिका जा चुके होंगे। सही में, ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगले दिन सभी अखबारों में विजय अमृतराज की खेल योजना को लेकर तीन-तीन, चार-चार कॉलमों में खबर थी। पर उस योजना का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से पढ़े हरपाल सिंह बेदी की खेल पत्रकारिता में धमक होती थी। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वह वरिष्ठ खेल पत्रकारों से संपर्क में रहते ही थे पर उन्हें युवा पत्रकारों के साथ भी अक्सर मजाक करते देखा जा सकता था। वह अपनी स्टोरी को भेजने में राजधानी एक्सप्रेस जैसी तेजी में विश्वास करते थे।

हमें याद है कि 1980 के दशक में जम्मू में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। उस जमाने में यूएनआई और पीटीआई ही दो समाचार एजेंसी हुआ करती

थीं। बेदी साहब यूएनआई में थे और पीटीआई से केवी प्रसाद इस चैंपियनशिप को कवर कर रहे थे। प्रसाद के खेल संपादक ने पहले हर मैच की रिपोर्ट भेजने और फिर लीड बनाने के लिए कहा हुआ था। इस कारण प्रसाद पूरे दिन खबर बनाने में व्यस्त रहते थे। पर बेदी साहब मैच खत्म होते प्रसाद से मैचों की डिटेल लेकर चार-पांच पैरे की स्टोरी भेज देते और अगले दिन सभी अखबारों में बेदी साहब ही छपे होते। हरपाल सिंह बेदी ने आठ ओलंपिक खेलों और करीब इतने ही एशियाई खेलों को कवर किया हुआ था। इसके अलावा तमाम कॉमनवेल्थ गेम्स और हॉकी विश्व कप कवर किए हुए थे। पर बेदी साहब पर ही यूएनआई की खेलों की सारी जिम्मेदारी होने की वजह से वह मैचों में समय पर कम ही पहुंचते थे। वह आते ही अक्सर ऐसे शख्स के पास जाते थे, जिसने ज्यादातर मैचों को देखा हो। वह उसे पूरी डिटेल लेते और उस पत्रकार के स्टोरी करने के लिए दफ्तर पहुंचने से पहले उसके दफ्तर में हरपाल सिंह बेदी की स्टोरी पहुंच जाया करती थी।

एक बार तो नेहरू हॉकी में सब जूनियर टूर्नामेंट में 30-30 मिनट के हाफ हो रहे थे। पर बेदी साहब ने 35-35 मिनट के हाफ से स्टोरी बना दी। अगले दिन उनका जब इस तरफ ध्यान दिलाया गया तो उनका कहना था कि मेरी स्टोरी ज्यादातर अखबारों में छपी है और तुम एक-दो लोगों के सही छापने पर भी सब लोग सही हमें ही मानेंगे। बेदी साहब अपने बेबाक अंदाज की वजह से विभिन्न चैनलों के खेल कार्यक्रमों में भी अक्सर जाया करते थे। इन कार्यक्रमों में वह कई बार ऐसी बातें बोला करते थे, जिस बारे में साथी लोग सोचते तक नहीं थे। मैंने उन्हें किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले तैयारी करते कभी नहीं देखा। हॉकी का उनका अनुभव लाजवाब था और वह कई बार देश की हॉकी को कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा भी करते थे। वह अपनी बात कहने में गुरेज नहीं करते थे, चाहे वह आपको अच्छी लग रही है या नहीं। एक बार कुछ खेल पत्रकारों की पिटाई होने के बाद दिल्ली खेल पत्रकार संघ की बैठक में कहा गया कि इस तरह की घटनाएं प्रेस कांफ्रेंस में शराब पीने की वजह से होती हैं और कई बार लोग गिफ्ट के लालच में चले जाते हैं। इसलिए प्रेस कांफ्रेंसों में शराब पीने और गिफ्ट लेने पर रोक लगाई जाए। बेदी साहब ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब शराब पीनी नहीं है और गिफ्ट भी नहीं लेना है तो वहां जाने की जरूरत ही क्या है। आयोजकों से कहा जाए कि वे सारे अखबारों में एक हैंडआउट भेज दें। इसके बाद प्रस्ताव मजाक में उड़ गया और प्रेस कांफ्रेंसों का सिलसिला उसी तरह चलता रहा। हरपाल सिंह बेदी जैसी शख्सियत कभी कभी ही आती हैं। वह भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं पर उनके जीने के अंदाज ऐसा निराला था कि कभी भी भुलाए नहीं जा सकेंगे।

प्रतिभा परिष्कार | श्रीराम शर्मा आचार्य

मेघ मंडल जब घटाटोप बनकर उमड़ते-गरजते हैं तो कृषि कर्मियों के मन आशा-उत्साह से भर कर बल्लियों उछलने लगते हैं। इंद्र सौ-सौ बार झुक कर उनकी सलामी देता है। अंधेरा आकाश प्रकाश से भर जाता है, और मोर नाचते एवं पपीहे कूकते हैं। हरीतिमा उनकी प्रतीक्षा में मखमली चादर ओढ़े मुस्कराती पड़ी रहती है। यह मनुहार मेघों की ही क्यों होती है? खोजने पर पता चलता है कि वे संचित जलराशि समेट, अपने आपको अति विनम्र बनाकर उसे धरती पर बिखेर देते हैं। प्रतिभा परिवर्धन के उद्दंड उपाय तो अनेक हैं। उन्हें आतंकवादी-अनाचारी तक अपनाते और प्रेत पिशाचों की तरह अनेक को भयभीत कर देते हैं, किंतु स्थिरता और सराहना उन्हीं प्रतिभावानों के साथ जुड़ी रहती है, जो शालीनता अपनाते हैं, और आदर्शों के प्रति अपने वैभव को उत्सर्ग करने में चूकते नहीं। ऐसे लोग शबरी, गिलहरी, केवट स्तर के ही क्यों न हों, अपने को अजर-अमर बना लेते हैं, और अनुकरण करने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। उनकी चुंबकीय विलक्षणता न जाने क्या-क्या, कहां-कहां से बटोर लाती है और बीज को वृक्ष बनाकर खड़ा कर देती है। प्रतिभा परिष्कार का अजस्र लाभ उठाने के लिए इन दिनों स्वर्ण सुयोग आया है। युगसंधि की वेला में, जीवट वाले प्राणवानों की आवश्यकता अनुभव की गई है। अवांछनीयताओं से ऐसे ही पराक्रमी जूझते हैं, और हनुमान, अंगद जैसे अनगढ़ होते हुए भी लंका को धराशायी बनाने एवं रामराज्य का सतयुगी वातावरण बनाने के दोनों मोरचों पर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देते हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ियां सदा नहीं आतीं। जो समय को पहचानते और बिना अवसर चूके अपने साहस का परिचय देते हैं, उन्हें प्रतिभा का धनी बनने में किसी अतिरिक्त अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम और साहस का मिलन ही वरिष्ठता तक पहुंचा देता है। पुण्य और परमार्थ का राजमार्ग ऐसा है, जिसे अपनाने पर वरिष्ठता का लक्ष्य हर किसी को मिल सकता है। आत्म साधना और लोक साधना, दोनों एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं। जहां एक को सही रीति से अपनाया जाएगा, वहां दूसरा उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाएगा।

रीडर्स मेल

परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल

अभी तक तो राज्य शिक्षा परिषद् और केंद्रीय शिक्षा परिषदों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में ही नकल और अंकों की बंदरबांट की समस्या थी जो तमाम प्रयासों के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, किन्तु पिछले कुछ वर्षों से प्रतियोगितात्मक और उच्च परीक्षाओं में धांधली की खबरों ने तो परीक्षाओं को अविश्वसनीय बना दिया है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो रही जिसमें पेपर लीक या फिर रैंक की बंदरबांट की खबर न आती हो। यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें न केवल राज्य अथवा केंद्रीय सरकार दोषी है अपितु परीक्षार्थी से लेकर अभिभावक, शिक्षा माफिया और कोचिंग संस्थान तक भी पूर्णतः दोषी हैं। हाल में नीट की परीक्षा का मामला सामने है जिसमें परीक्षा समिति पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार भी संदेह के घेरे में आती है। भले ही वह इस घोटाले में लिप्त न भी हो किन्तु दोष तो व्यवस्था पर ही लगेगा। नीट की परीक्षा में भविष्य के चिकित्सक बैठते हैं, जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है। यदि इसमें अयोग्य छात्रों का चयन होगा तो सहज ही समझा जा सकता है कि समाज का स्वास्थ्य और जीवन कैसे हाथों में सौंपा जा रहा है? यह ऐसा भयंकर खेल है, जो महापाप की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अतः इन परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन, दोनों को ही कठोरतम कदम उठाने होंगे जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और योग्यता तथा प्रतिभा कुंठित न हो।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

एनटीए की साख पर बट्टा

एनटीए द्वारा दर्जनों से भी अधिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें नीट, यूजीसी नेट, कलैट, सीयूईटी, जेईई आदि की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। 2024 के मेडिकल के दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई हैं, उनको लेकर उच्चतम न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दाखिल कराई जा चुकी हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार छात्रों और अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। विभिन्न छात्र संगठन भी सड़क से लेकर मंत्रालय तक अपनी फरियाद कर चुके हैं। विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक उठाने की बात कह चुके हैं। बिहार के पटना जिले तथा हरियाणा के झज्जर जिले तथा गुजरात के गोधरा में विभिन्न तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि एनटीए की शाख को किसी भी प्रकार का बट्टा न लगे। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस विषय पर स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। वैसे तो दूसरी तरफ न्यायपालिका से भी इस संदर्भ में गुहार की जा चुकी है। मामला विचाराधीन है।

मीना धानिया, सिरसपुर

इंटरनेट के नुकसान

इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता ने आज के युवा वर्ग को एक प्रकार से पंगू सा बना दिया है। मनुष्य की शारीरिक सक्रियता घटी है। इस वजह से वह अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसके व्यापक प्रभाव देखने में आ रहे हैं। सबसे पहला तो यही है कि परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर संवाद कम हुआ है। सामाजिक मेलजोल कम हुआ है, और परिणामस्वरूप आपसी रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं।

ललित महालकरी, इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-33, अंक 304
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

जी 7 सम्मेलन
मोदी की उपस्थिति

जी 7 सम्मेलन के 'आउटरीच' सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को इटली पहुंचे। यह प्रधानमंत्री पद पर तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद नरेन्द्र मोदी की पहली विदेश यात्रा है। भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण इटली ने दिया है। सात राष्ट्रों का समूह या जी 7 दुनिया की सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं-कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन व अमेरिका का गठबंधन है जो दुनिया को संचालित करती हैं। पिछले वर्षों में भारत जी 7 देशों का एक सर्वाधिक विश्वसनीय साझीदार बन कर उभरा है। यह मंच वैश्विक आर्थिक नीतियां निर्धारित करने तथा जलवायु परिवर्तन, व्यापार एवं भू-राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संक्षेप में कहें तो यह एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति है। जी 7 सम्मेलन एक वार्षिक बैठक है जिसमें सदस्य देश इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सहयोगी समाधान तलाशते हैं। हालांकि, भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, पर उसने अपने विस्तार लेते प्रभाव तथा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जी 7 की पहलों और निर्णयों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। जी 7 की वैश्विक आर्थिक व राजनीतिक मामलों में काफी पकड़ है। सामूहिक रूप से ये देश वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, जैसे आईएमएफ व विश्व बैंक पर काफी प्रभाव रखते हैं। समूह के निर्णयों का असर विश्व बाजारों पर पड़ता है जिससे आर्थिक प्रवृत्तियां बनती हैं तथा अंतरराष्ट्रीय नीतियां प्रभावित होती हैं। लेकिन समूह को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व भू-राजनीति है। चीन के साथ आर्थिक व राजनीतिक तनाव के कारण जी 7 देशों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण अग्रणी देश है। जी 7 अक्सर

सुरक्षा मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा करता है और भारतीय दृष्टिकोण को गंभीरता से लिया जाता है। इन मुद्दों में क्षेत्रीय स्थिरता तथा आतंकवाद से मुकाबला शामिल हैं।

भारत के जी 7 देशों के साथ लंबे समय से संबंध हैं। जी 7 के साथ भारत की सहभागिता अनेक रणनीतिक राष्ट्रीय हितों के कारण है। भारत व्यापार और निवेश बढ़ा कर अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाना चाहता है। जी 7 अर्थव्यवस्थायें महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत हैं। जी 7 देशों के साथ संबंधों के कारण भारत न्यायोचित व्यापार व्यवहारों की पैरोकारी, उत्कृष्ट तकनीकों तक पहुंच तथा अपनी आर्थिक पहलों में सहायता की मांग कर सकता है। इसके साथ ही भारत वैश्विक जलवायु एजेंडे में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। एक विकासशील देश के नाते वह आर्थिक प्रगति तथा पर्यावरणीय टिकाऊपन की दुहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर जी 7 चर्चाओं में भारत की सहभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी 7 ने कार्बन तटस्थता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकासशील देशों को वित्तीय समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। इनकी हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के भारतीय लक्ष्य से संगति है। इस संवाद में भारत की सहभागिता उसके सुरक्षा सरोकारों को संबोधित करने के लिए खासकर हिंद- प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण है जहां चीन की आक्रामक गतिविधियां चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। विश्व तकनीकी केन्द्र बनने की इच्छा रखने वाले भारत जैसे देश के लिए जी 7 देशों के साथ सहयोग खोजों और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जी 7 पहलों में सहभागिता से भारत को अद्यतन तकनीकों तक पहुंच तथा शोध एवं विकास क्षेत्रों में साझेदारी के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिल सकती है।

जीवन्त भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

भारत में हालिया संसदीय चुनाव ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृढ़ता एवं परिपक्वता रेखांकित की है। चुनाव परिणाम ने भारतीय मतदाताओं की विशिष्ट पसंदों को भी प्रदर्शित किया है।

विनयशील गौतम
(लेखक, प्रबंधन विशेषज्ञ हैं)

भारत में हालिया संसदीय चुनाव ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृढ़ता एवं परिपक्वता रेखांकित की है। चुनाव परिणाम ने भारतीय मतदाताओं की विशिष्ट पसंदों को भी प्रदर्शित किया है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि सभ्य समाज बनाने के लिए नियमों, विनियमों तथा व्यवहारों की स्वीकार्यता जरूरी है। ये व्यवहार तथा नियम-विनियम ही लोगों के न्यायोचित व्यवहार की गारंटी सुनिश्चित करते हैं। भले ही ऐसे नियमों, विनियमों या व्यवहारों का दस्तावेजीकरण हुआ हो अथव वे आमतौर से प्रचलित व्यवहार माने जाते हों, पर आमतौर से सभी लोगों द्वारा इनकी स्वीकार्यता की पुष्टि जरूरी है। प्रचलित नियमों व परंपराओं का परिपालन दुनिया में अनेक देशों में स्वाभाविक रूप से होता है। इस तथ्य का उल्लेख आमतौर से ब्रिटेन के अलिखित संविधान के रूप में होता है। लेकिन अलिखित संविधान के बावजूद ब्रिटेन में स्थापित परंपराओं का पूर्णत: पालन होता है और यह काफी व्यवस्थित तरीके से कामकाज सुनिश्चित करता है। इसके लिए बड़ी सीमा तक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है।

जनता का यह व्यवहार एकसाथ काम करना सुनिश्चित करता है। यहां तक कि असहमति होने पर भी इसे व्यवस्थित रूप से ही प्रकट किया जाता है और इसके बाद परस्पर सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इससे अनेक मामलों का निपटारा व्यवस्थित रूप से सहमतियों एवं असहमतियों के बावजूद होता है। इस प्रकार जनता में विभिन्न मुद्दों पर सहमतियों एवं असहमतियों के बावजूद परस्पर सम्मान की भावना बनी रहती है। यह ब्रिटिश लोकतंत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसका पालन भारत समेत अनेक लोकतंत्रों में अलिखित परंपरा के रूप में होता है इसकी तुलना में कुछ देशों में लिखित संविधान हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको व्यवस्थित रूप में व्यवहार करने में कठिनाई होती है और अक्सर अनेक मामलों में अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। हालांकि, अदालतों में अपील करना भी टकराव के समाधान का स्वीकार्य तरीका है, भले ही अदालती फैसलों के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली व्यवस्था परस्पर सहमति से बनी व्यवस्था की तुलना में थोड़ी कम विकसित होती है। आत्म-अनुशासन, आत्म-प्रबंधन तथा असहमतियों को सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग और उनकी विरासत माना जाता है।

हालांकि, कुछ मामलों में सहभागिता से इनकार करने जैसे मामले भी सामने आते हैं, पर इनको नियम के बजाय अपवाद ही होना चाहिए। कुल मिला कर कहा जाए तो 'असहमति के लिए सहमत' होना ही लोकतंत्र का सौंदर्य है।

लेकिन इस भावना के विकास के लिए लंबे समय से चल रही लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन जरूरी है, भले ही वे अलिखित ही क्यों न हों। इसके साथ ही सभ्य भाषा का प्रयोग तथा असहमति व्यक्त करने के सभ्य तरीके भी सभ्य समाज का अंतर्निहित अंग हैं। भद्दी भाषा के प्रयोग तथा आक्रामक मुद्रा के कारण किसी को लाभ नहीं होता है और यह मानव विकास के खराब स्तर का प्रतीक भी है। सभ्य समाज ऐसी प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत में हाल में हुए संसदीय चुनाव भारतीय राजनीतिक प्रक्रियाओं की स्वास्थ्य स्थिति की कथा कहते हैं। एक ओर इनसे भारतीय चुनाव प्रक्रिया की दृढ़ता तथा उसके न्यायोचित होने का प्रमाण मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक पसंद में परिपक्वता का भी उदाहरण है। चुनाव परिणाम सचमुच मतदाताओं की सोच को अभिव्यक्त करते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से अपना दृष्टिकोण सामने रखना चाहते हैं। चुनाव परिणाम लोगों के व्यक्तिगत निर्णय और रुझान को भी प्रकट करते हैं। राजनीतिक पसंदों की इतने व्यापक पैमाने पर शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति किसी की भी सोच और प्रेक्षण में आनन्द का कारण बननी चाहिए।

लेकिन यह सब कहने और करने के बाद भी, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यों का कारण बनने वाले तथ्यों की बेहतर समझदारी भी जरूरी है। इस चुनाव प्रक्रिया में कुछ विजेताओं की पहचान थोड़ी अलग किस्म की भी है, लेकिन उन्होंने इसे कैबिनेट और आम जनता के सामने प्रकट नहीं किया है। यह भी एक प्रकार की विकृति है। किसी को भी कैबिनेट में शामिल होने का 'अधिकार' नहीं है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री को अपने अंतर्निहित विशेषाधिकार के अंतर्गत ऐसा करना ठीक नहीं लगता है तो उनको अपनी सचेतन इच्छा प्रकट करनी चाहिए। इसी प्रकार चुनाव में पराजित कुछ लोगों को कैबिनेट में शामिल करना भी उचित है, यदि यह प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार के दायरे में आता हो। इसका उदाहरण एक पूर्व कांग्रेसी हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए, पर इसके बावजूद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। एक और दिलचस्प मामला केरल में भाजपा नेता का है जो राज्य में भाजपा के महासचिव हैं। वे संसद के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं हैं, पर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। एक खास राज्य से आठ मंत्रियों का चयन किया गया, लेकिन दो वरिष्ठ लोग जो विभिन्न कालखंड में पार्टी की कैबिनेटों में शामिल रहे हैं, भले ही वे चुनाव जीते हों या नहीं, पर उनको वर्तमान कैबिनेट में स्थान नहीं मिला है।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय का कारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। ऐसे ही एक नेता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई जो निर्वतमान सरकार में मंत्री होने के बावजूद चुनाव हार गए थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये खास नेता न केवल निवर्तमान सरकार में मंत्री थे, बल्कि चुनाव भी हार गए थे। हालांकि, वे राज्यसभा के सदस्य हैं। संवैधानिक प्राविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत किसी को मंत्री बना सकते हैं, लेनि उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है नहीं तो उसकी मंत्रि परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि, ऐसे मामलों से मीडिया में नकारात्मक खबरें और टिप्पणियां आती हैं, पर इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। संसदीय पद्धति की विकृतियां तलाश करने के लिए किसी माइक्रोस्कोप के आगे टेलीस्कोप लगाया जा सकता है। कोई यह विश्वास भी कर सकता है कि किसी संसदीय व्यवस्था में इसे कैबिनेट गठन का मानक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण को निर्णय-प्रक्रिया के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत समेत लोकतंत्र की किसी भी संसदीय प्रणाली वाले देश में किसी नेता या विशिष्ट व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। सभी अपवादों के मामले में कोई भी नियम या विनियम शत-प्रतिशत लागू नहीं हो सकता है जिसका संबंध नियमों या विशेषाधिकारों से हो।

कुल मिला कर कहें तो भारत में हालिया लोकसभा चुनाव के बाद 70 से अधिक लोगों का मंत्रिमंडल गठन संतुलन एवं शक्ति की उपलब्धि है। चाहे रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, एन मुरुगन और राजीव चंद्रशेखर के कैबिनेट में शामिल करने या उससे बाहर रखने का मामला हो, ऐसे निर्णयों की आलोचना का कोई औचित्य नहीं है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के मामले का उदाहरण दिया जा सकता है जो गुजरात से भाजपा नेता हैं और मोदी की पहली और दूसरी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पर इस बार चुनाव जीतने के बाद उनको कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया है। ऐसे निर्णय बड़े उत्साह से लिए जाते हैं और इनको इसी भावना से स्वीकार भी किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह दावा जरूर किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 70 से अधिक मंत्रियों को शपथ दिलाना एक उपलब्धि है। मंत्रिमंडल के गठन में पूरी सतर्कता, सावधानी और संतुलन का परिचय दिया गया है।

यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद का गठन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है तथा राजनीतिक प्रक्रिया बहुत परिपक्व हो गई है।

मोदी की तीसरी पारी में राजनय को नई दिशा

मोदी 3.0 मजबूत कूटनीति, रणनीतिक गठबंधन और नए सिरे से राष्ट्रीय पहचान पर ध्यान केंद्रित करके भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाता है

अभिषेक प्रताप
(लेखक, दिल्ली विवि में सह प्रोफेसर हैं)

4 जून को, भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए। कई लोगों के लिए, हमारे एग्जिट पोल और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदों के बीच, ये नतीजे आश्चर्य के तत्व के साथ आए। किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बावजूद, भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। मोदी 3, जैसा कि हम इसे कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर देश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पिछले दशक में, भारत ने खुद को एक प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी सरकार की सक्रिय कूटनीति के नेतृत्व में, भारत ने एक रणनीतिक रूप से मितभाषी राज्य से वैश्विक राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। एक आकांक्षी शक्ति के रूप में, भारत ने किसी भी महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने से इनकार कर दिया है और पड़ोसी संबंधों को मजबूत करने, सॉफ्ट पावर विस्तार, मानवीय सहायता को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग बनाने, वैश्विक आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से लड़ने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। खुद प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए एक संपादकीय में, उन्होंने दोहराया कि भारत को वैश्विक दक्षिण की एक मजबूत और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

मोदी 3.0 विदेश नीति की इन निरंतरताओं और उपलब्धियों पर निर्माण करने की संभावना है। एक जटिल दुनिया में, मोदी का तीसरा कार्यकाल नई कूटनीतिक चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। गठबंधन सहयोगी नीति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रुझान एनडीए सरकार के तहत भारत की विदेश नीति को आकार देंगे।

सबसे पहले, भारत की विदेश नीति की दिशा को हमारी राष्ट्रीय पहचान के प्रश्न के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है जो हमारे प्राचीन अतीत और गौरव के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। पिछले दस वर्षों में, हमारी कूटनीति ने अपनी बौद्धिक ऊर्जा और राजनीतिक ताकत का निवेश हमारी सभ्यतागत पहचान के महत्व को अपनाने में किया है। और यह पहचान गौरवशाली हिंदू अतीत के मूल्यों और संस्कृति द्वारा अच्छी तरह से आकार लेती है। गठबंधन सहयोगियों की पृष्ठभूमि में, यह देखना दिलचस्प होगा कि सभ्यतागत पहचान के इस सवाल को सरकार में टीडीपी की पुनरुत्थानशील भारत का आह्वान हमारी मूल और एकीकृत सभ्यतागत पहचान द्वारा अच्छी तरह से आकार और परिभाषित है। दूसरा, मोदी 3 में राजनीतिक गठबंधन और आर्थिक साझेदारी बनाने के मामले में विदेश नीति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जो 2047 तक विकसित भारत (विकसित भारत) के निर्माण की दिशा में हमारे प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित हो सकती है। वैश्विक दुनिया में सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति महत्वपूर्ण है। बाजार सुधार, मुक्त व्यापार समझौते, डिजिटल बुनियादी ढांचे का उन्नयन और ऊर्जा सुरक्षा हमारे आर्थिक लचीलेपन और वैश्विक प्रासंगिकता के लिए आवश्यक हैं।

तीसरा, भारत की कूटनीतिक पैंतरेबाजी और महाशक्तियों के साथ जुड़ाव को देखना दिलचस्प होगा क्योंकि हम एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते रहते हैं। भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते और भी गहरे होने की संभावना है, जो चीन की मुखरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास पर चिंताओं के बीच दोनों के बीच रणनीतिक अभिसरण द्वारा आकार लेगा।

मोदी 3 मजबूत भारत-अमेरिका संबंधों, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, व्यापार, विज्ञान/तकनीक और रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत यूक्रेन और डोकलाम के मामले में आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय हितों पर जोर देगा। 'पड़ोस नीति' पर जोर देते हुए, भारत क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार में सुधार करना चाहता है, जो 2022 के संकट के दौरान श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर की सहायता से पता चलता है। चुनौतियों के बावजूद क्षेत्रीय साझेदारी को रेखांकित करते हुए एनडीए सरकार के शपथ समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

अंत में, मोदी 3 के तहत विदेश नीति के लिए चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन करना आसान नहीं होगा। भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में दोनों देशों की सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने का बहुत स्पष्ट रूप से वादा किया गया है। बढ़ते विश्वास घाटे के बीच, भारत आक्रामक और पुनरुत्थानशील चीन के संभावित खतरे को पूरी तरह से पहचानता है। चुनावी अभियान में विपक्ष द्वारा भाजपा के खिलाफ 'चीन कार्ड' का इस्तेमाल भी देखा गया। द्विपक्षीय संबंधों में इस ठहराव से कूटनीति कैसे उभरती है, यह नई सरकार के तहत एक जांच की चिंता होगी। हमें अपनी रक्षा क्षमताओं का निर्माण करते हुए और समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ रणनीतिक मजबूती देते हुए चीन के साथ अपने संबंधों में एक नया संतुलन खोजने की जरूरत है।

दिए गए परिदृश्य में, मोदी 3 के तहत कूटनीति निरंतरता और व्यापक विदेश नीति सुधारों, रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ में भारत की अग्रणी भूमिका के लिए तैयार है। इसके अलावा, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका का विस्तार और विकास होना तय है, क्योंकि भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का प्रयास करता है।

आप की बात

ईवीएम पर चुप्पी

पिछले दस वर्षों से चुनाव में जीतने वाली पार्टी के विरूद्ध हारने वाली पार्टी बिना सोचे-समझे ईवीएम के दुरुपयोग के आरोप लगा देती थी। अब लगता है कि ईवीएम सबको प्यारी हो गई क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद किसी ने इसके दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया। ईवीएम पर चुप्पी का अर्थ यह है कि हार जोन के कारण ही विपक्षी ऐसे आरोप लगाते थे। शायद उनका इरादा मतदाताओं को ईवीएम के खिलाफ भड़काना और भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना था। जब विपक्ष जीत जाता तो ईवीएम विश्वसनीय हो जाती और हारने पर खराब। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने पराजित उम्मीदवार द्वारा सात दिन के भीतर आपत्ति करने पर ईवीएम की जांच का प्राविधान रखा था और इसके लिए 54,000 फीस भी रखी थी। लेकिन यह समयावधि बीतने तक उसके पास एक भी शिकायत नहीं आई। विपक्ष की इस चुप्पी से ईवीएम की विश्वसनीयता पूर्णत: सिद्ध हो गई है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्वाचन आयोग को अब आनलाइन मतदान की ओर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर देश-विदेश में रहने वाले मतदाता और अनिवासी भारतीय भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना लोकतांत्रिक योगदान दे सकें।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

बौखलाये आतंकी

जम्मू-कश्मीर में पिछले दिनों एक के बाद एक चार आतंकी हमलों ने सुरक्षा बलों और सरकारी हलकों में चिंता जगाई है। कश्मीर में लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो जाने से आतंकवादी खिसिया गए हैं। बौखलाहट में कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में रोड़े अटकाने के लिए उन्होंने अब तीर्थ यात्रियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सरकार को एक बार फिर से कश्मीर में अधिक सुरक्षा बलों कि तैनाती करना होगी ताकि आतंकवादी चुनाव में भय व खोफ का वातावरण पैदा नहीं कर सके। पाकिस्तानी नेता भारत से दोस्ताना संबंध बनाने की बात करते है, मगर पाक-प्रायोजित आतंकी घटनाएं वस्तुस्थिति बयां कर रही है। यह मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है। पाकिस्तानी नेता चाहे कितनी ही दोस्ती की बात करें जब तक आतंकवाद नहीं रोका जाता तब तक कोई मित्रतापूर्ण बात संभव नहीं है। इन आतंकी हमलों के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का साया मंडराने लगा है। मोदी जम्मू कश्मीर में अधिकतम आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई का निर्देश दे चुके हैं। यदि पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकी गतिविधियां नहीं थमती हैं तो भारत को आक्रामक कार्रवाई करनी पड़ेगी।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

मजबूत लोकतंत्र

हाल के संसदीय चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत सशक्त और जीवंत है। ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठने पर जनता और प्रशासन ने मिलकर एक बार फिर भरोसे का प्रमाण दिया। ईवीएम सवाल और चुनाव आयोग की भूमिका पर भले ही सवाल उठे हों, पर मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाल कर इन सवालों को खारिज कर दिया। यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास अटूट है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह समय-समय पर खुद को साबित करता है। अब नेताओं और प्रशासन को चाहिए कि वे पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दे कर जनता के हित में ऐसी नीतियां बनायें जिनकी स्वीकार्यता पर कोई सवाल न उठा सके। देश की जनता ने इस बार जहां नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार सत्ता सौंपी है, वहीं विपक्ष को भी पहले की तुलना में मजबूत बनाया है। ऐसे में विपक्ष का भी दायित्व है कि वह केवल सरकार को घेरने, संसद का कामकाज बाधित करने तथा अपने दलीय स्वार्थों को आगे बढ़ाने के बजाय रचनात्मक भूमिका निभाए तथा देशहित में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का समर्थन करे।

अवनीश गुप्ता, आजमगढ़

नीट परीक्षा

हाल ही में संपन्न भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा-नीट में गड़बड़ी के अनेक प्रमाण सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कौंसिलिंग पर रोक नहीं लगाई है, पर वह मामले की सुनवाई कर रहा है। नव-नियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार परीक्षार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने परीक्षार्थियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। विपक्ष को यह मामला बैठे बैठाए मिल गया है और वह इसे दूसरा व्यापम घोटाला बता कर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। यह मामला तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए प्रथम ग्रासे मक्षिका पात: की तरह है और स्वाभाविक रूप से शिक्षा मंत्री कुछ खीझे हुए लगते हैं। सरकार को न केवल पूरे मामले में निष्पक्षता बरतनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसा करते दिखना भी चाहिए। विडंबना है कि अब तक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीआई के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नीट में गड़बड़ी से एनटीआई की पूरी कार्यपद्धति पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली पर भी समग्र और व्यापक विचार होना चाहिए।

– **अंकित सोनी,** मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/epaperpdf

• बेस्ट सेलर से सबक | जोसेफ एनगुयेन

खुश रहने की आदत डालें, काम आएगी

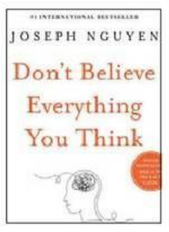

यह किताब मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारे विचार हमारे दुःखों का मूल कारण हैं। यह इस पर रोशनी डालती है कि हमें कैसे नॉन-थिंकिंग की स्थिति में आना चाहिए। इसमें इससे जुड़े अनेक बिंदु पाठकों को समझाए गए हैं।

खुशी के पांच बिंदु

सोचने का तरीका जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सोच भी उसी से बनती है और हमारा जीवन भी। अगर हमें एक सकारात्मक मनोदशा में बने रहना है और अपने सोचने के तरीके को स्वस्थ रखना है तो पांच बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला है, बिना शर्त के प्यार करें। दूसरा है, सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव विचारों और आलोचना को छोड़ दें। तीसरा, वर्तमान में रहें और सचेत रहें। चौथा, अपने साथ शांति कायम कर लें। और पांचवां, अपने से उच्चतर किसी शक्ति- चाहे उसे ईश्वर कहें या ब्रह्मांड या चेतना या दिव्य ऊर्जा- में विश्वास रखें। आपका दिमाग अकसर आपको नकारात्मक बातें बताता है। उसकी हर बात पर तुरंत विश्वास न कर लें।

प्रेम में शर्तें नहीं होतीं

सीमाएं, शर्तें, बाधाएं और हालात- ये सब प्रेम को परिभाषित नहीं करते। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है। और अगर वह शर्तों के साथ है तो प्रेम नहीं है। प्रेमपूर्ण होना जीवन में स्थिर होने और नॉन-थिंकिंग जोन में जाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है।

हैंडल करने की कला

जीवन है तो तकलीफें तो रहेंगी ही, लेकिन दुःखी रहना या नहीं रहना हमारा अपना चयन होता है। क्योंकि जीवन की घटनाएं और स्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं। लेकिन उन पर हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे और उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, इन पर जरूर हमारा वश है। एक बार हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हम तकलीफों का बेहतर तरीके से सामना करना सीख जाते हैं।

खुद से कुछ जरूरी सवाल

खुद से सवाल पूछते रहें। जैसे कि तुम क्यों काम करते हो? पैसे कमाने के लिए ना? और पैसा किसलिए? ताकि यात्राएं कर सको? यात्रा से क्या मिलेगा? नए लोग और अनुभव। इससे क्या होगा? खुशी मिलेगी। तो घुमा-फिराकर अंत में सारी चीजें खुशी मिलने पर आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने खुश होने की आदत नहीं डाली तो सबकुछ मिलने पर भी खुश नहीं हो सकेंगे।

नॉन-थिंकिंग जोन में जाना

थॉट्स नाउन यानी संज्ञा हैं और थिंकिंग वर्ब यानी क्रिया है। उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही रहने देना चाहिए। समस्या यह है कि हम सोचने में कुछ ज्यादा ही समय खर्च करते हैं। जब भी आपको नकारात्मक विचार घेरें, सजग हो जाएं। बहुत सम्भव है कि उस समय आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे होंगे। यही वह समय है, जब आपको नॉन-थिंकिंग जोन में जाने की जरूरत होगी।

कोशिशें मायने रखती हैं

अगर आप खुद को नॉन-थिंकिंग जोन में नहीं ले जा पाते हैं या छोटे-मोटे काम भी नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए खुद को दंडित न करें। हम सभी मनुष्य हैं और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप अपना बेस्ट-वर्शन ही कहलाएंगे। अंत में कोशिशें करना ही मायने रखना है, यह नहीं कि आपकी कोशिशों का क्या नतीजा निकला।

• अनंत ऊर्जा | बीके शिवानी, आध्यात्मिक वक्ता और लेखिका

लोग सच कहेंगे, बशर्ते आप उन्हें सुनें

लोग सच बोलने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे बच्चे हों या कोई और, बशर्ते हम भी सच सुनने के लिए तैयार रहें। अगर हम उनकी हर बात को संयम से सुन लेंगे तो सामने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमारे रिश्ते अपने आप मधुर और मजबूत हो जाएंगे। फिर उन्हें कोई भी बात आपसे छुपाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।

इन दिनों हर बड़े स्कूल में बच्चों के लिए परामर्शदाता या काउंसलर होते हैं। बच्चा जाकर उनसे अपनी हर बात साझा करता है, जो कि वह अपनी मम्मी-पापा से नहीं कर पाता है। क्योंकि काउंसलर निष्पक्ष होकर बच्चे की हर बात को आराम से सुनते हैं। ₹हां जी बताओ, क्या हुआ', ₹मुझे ये एडिक्शन हो गया, मुझे ये आदत हो गई...' काउंसलर बच्चे की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। काउंसलर कहता है, कोई बात नहीं, हर चीज ठीक हो सकती है, आप बैठो, ठीक करते हैं। वह बहुत ही प्यार से, बच्चे को सम्मान देकर समझता है और उसकी कमियों को दूर करने का तरीका बता देता है। इससे एक तो सम्मान बना रहता है और दूसरा, उसे अपमानित नहीं होना पड़ता है। जबकि माता-पिता का बच्चे से लगाव होता है पर वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा कहते हैं कि ₹तुमने ऐसे किया कैसे, तुम्हें इसलिए स्कूल भेजा था, इसलिए मैं इतना खर्च कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं'। इतना सारा उस बच्चे को सुना देते हैं। फिर तो बच्चा आगे की पूरी बात बताता भी नहीं है। अब जमाना बदल चुका है आज हर पैरेंट को अपने बच्चे के लिए काउंसलर बनना पड़ेगा।

काउंसलर मतलब साक्षी होकर, शांति से उसकी हर बात सुनें, उनकी बातों को स्वीकार करें, जो उन्होंने किया है, उसके लिए राय दें। अगर उस समय अपने ऊपर संयम नहीं रखा तो हम खुद ही चिंता में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर उनको अपमानित कर देते हैं। ऐसे में यह पक्का मान लें कि अगली बार वो अपनी कोई भी बात आपको बताने वाले नहीं है। जबकि होना तो यह चाहिए कि बच्चा अपनी हर बात माता-पिता के साथ साझा करें। हर बच्चे को अपने माता-पिता से स्वीकार्य ही तो चाहिए। अगर वो स्वीकार्य (एक्सेप्टेंस) उसको मम्मी-पापा से मिल गया तो वो फिर वो अपने किसी दोस्त के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। अगर मम्मी-पापा से वो स्वीकार्य नहीं मिला तो फिर वो दूसरों के पास चला जाता है। अगर उसे से अपने दोस्त से मिल गया तो वह अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। यहां तक कि वो वाली चीजें भी करने के लिए तैयार रहता है, जो उनको खुद अपनी मर्यादाओं में सही नहीं लगती है। उसको हम कहेंगे फियर प्रेशर। इसलिए हर घर में एक्सेप्टेंस मिल जाए तो कोई भी बच्चा कभी भी भय के प्रेशर में नहीं जाएगा। हमें उन बच्चों को सुरक्षित रखना है। आप अपने बच्चों को कहेंगे कि आप अपनी हर बात मुझे बता सकते हैं। यह गारंटी दी जानी चाहिए कि आप सुनाओगे तो मैं आपको डांटूगा नहीं।

मैं एक स्कूल में गई थी। उसमें कक्षा नवमीं और दसवीं के कुल 200 बच्चे जमा थे। मैंने उनसे पूछा कि आपमें से कौन-कौन अपनी हर बात मम्मी-पापा को बताते हैं। सिर्फ पांच लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा कि आप मम्मी-पापा को जाकर बोलो कि आप डांटोगे नहीं तो मैं अपनी हर बात आपको बताऊंगा। तो वो मुझ पर हंसने लगे और कहते हैं दीदी कैसी बात करती हो आप! वो कहते हैं कि पहले हमारे पैरेंट्स हमारी हर बात सुन लेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बाद में किसी भी बात पर डांटने के लिए हमारे द्वारा बताई गई बातों को ही इस्तेमाल करेंगे। हम उनको जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई और हो, लोग सच बोलने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी सच सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम उनकी हर बात को संयम से सुन लेंगे तो सामने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमारे रिश्ते अपने आप मधुर और मजबूत हो जाएंगे। फिर उन्हें कोई भी बात आपसे छुपाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अगर आपके बच्चे आकर आपसे कुछ साझा करते हैं तो आप शांति से उनकी हर बात को सुनें। उन्हें किसी भी बात के लिए दोषी न ठहराएं। वो जिस समाज में अभी बड़े हो रहे हैं और हम जिस समाज में बड़े हुए थे, दोनों में बहुत फर्क आ चुका है। तब के नॉर्मल और अब के नॉर्मल की परिभाषा बदल चुकी है। हमें प्यार से उनको राय देनी है लेकिन पहले उनकी हर बात को मानकर रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। तो आप गलत हो यह शब्द समाप्त हो जाएगा और आपस में जो मिस अंडरस्टैंडिंग शब्द है वो भी खत्म हो जाएगा। हमें अपने रिश्ते में स्वीकार्य लेकर आना है। तभी हम अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं।

हमें प्यार से बच्चों को राय देनी है, लेकिन पहले उनकी हर बात को मानकर रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। इससे आपस की मिस-अंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी।

• देश-दुनिया की सकारात्मक परंपराएं

केन्या : स्थानीय खान-पान पर गर्व, इसे प्रमोट करते हैं लोग

• ऐतिहासिक कारकों और आधुनिक जीवनशैली के कारण केन्या के पारंपरिक खानपान के भूल जाने का खतरा मंडराने लगा था। स्थानीय खानपान को गरीबी और पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन फिर साल 2007 में इसे संजोने की पहल शुरू हुई।

• वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर केन्या के 850 से ज्यादा देशी पौधे और उनके नाम को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसमें उनसे जुड़ी तमाम जानकारी के अलावा उन पौधों से बनाई जाने वाली रेसिपी को भी लिखा गया।

सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में खासी भूमिका निभाई है।

• यूनेस्को ने केन्या के सांस्कृतिक विभाग के साथ मिलकर कई पायलट प्रोजेक्ट चलाए। जागरूकता के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ करार किया गया। केन्या के अलावा इथियोपिया और बुर्किना फासो में भी इसी तरह के अभियान चलाए गए।

• केन्या में स्थानीय खान-पान को भूलने से स्वास्थ्य समस्याएं और कुपोषण का भी डर था। पर अब पारंपरिक खानपान का प्रयोग बढ़ा है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सार्वजनिक भोज में लोग केन्या के पारंपरिक खाद्य ही परोसते हैं।

• प्रेरक पत्र

हमारा संघर्ष राजनैतिक नहीं नैतिक भी है...

महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में साबरमती जेल से यह पत्र मौलाना अब्दुल बारी को लिखा था।

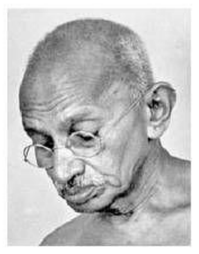

प्रिय मौलाना साहब,

आजकल तो मैं अपने ₹स्वतंत्रता-भवन' में मौज कर रहा हूं। आपकी अनुपस्थिति मुझे खल रही है, परंतु मुझे इसके कारण मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग अजमेर में काफी बातचीत कर चुके थे।

मैं बहुत गहराई से सोचने पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसी एक ही चीज है, जिसे हिंदू-मुस्लिम एकता का स्पष्ट और प्रभावकारी प्रतीक माना जा सकता है और वह है इन दोनों जातियों में चरखे का और हाथ के कते सूत से हथकरघे पर बुनी शुद्ध खादी का प्रचार। जब सभी लोग इस सिद्धांत के कायल हो जाएंगे, तभी हममें विचार की एकता हो सकती है और हमें काम का एक संयुक्त आधार मिल सकता है।

खद्दर का प्रचार तब तक व्यापक नहीं हो सकता, जब तक उसे दोनों जातियां अपना न लें। चरखे और खद्दर के व्यापक प्रचार से भारत में जागृति पैदा होगी। उससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि हम लोग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति रखते हैं। जब सभी लोग खद्दर का व्यवहार करने लग जाएंगे, तब विलायती कपड़े का बहिष्कार अपने आप हो जाएगा।

मेरे लिए तो चरखा और खद्दर विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं, क्योंकि वे उस भाईचारे की भावना के प्रतीक हैं, जो दोनों जातियों के दिलों में भूख और रोग से पीड़ित गरीब लोगों के प्रति होनी चाहिए। इसी कारण तो आज हमारा संघर्ष राजनैतिक ही नहीं, नैतिक और आर्थिक भी कहा जा सकता है।

जब तक स्वराज्य हासिल नहीं हो जाता, हरेक को अपना मजहबी फर्ज समझकर रोज चरखा चलाना चाहिए।

साबरमती जेल,
12 मार्च, 1922

© The New York Times

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

टेक्नोलॉजी

हादसों के बावजूद चीन में ड्राइवरलेस कार का सबसे बड़ा प्रयोग जारी

कीथ ब्रैडशर

बीते दिनों चीन में एक भीषण कार हादसा हुआ। एक ड्राइवरलेस कार दूसरी गाड़ी से टकराकर आग की चपेट में आ गई थी। गाड़ी में सवार तीन लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कार की मालकिन ने एक ऑनलाइन वीडियो बनाकर इंसाफ की मांग की लेकिन उनकी सारी पोस्ट हटा दी गईं। हादसे के नौ दिन बाद भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी इसलिए खुद-ब-खुद रुकने वाली उसकी तकनीक काम नहीं कर सकी। कुल मिलाकर चीन में इस मुद्दे को दबा दिया गया। अमेरिका में ऐसी ड्राइवरलेस (सेल्फ-ड्राइविंग) गाड़ियों के हादसों की जांच होती है लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ।

दरअसल तमाम घटनाओं के बावजूद चीन में ड्राइवरलेस कार की बड़े स्तर पर टेस्टिंग हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस कार का प्रयोग चीन के मध्य शहर वुहान की सड़कों पर चल रहा है, जिसमें 11 करोड़ लोग और 45 लाख कारें शामिल हैं। पूरे चीन में 16 से ज्यादा शहरों ने कंपनियों को सार्वजनिक सड़कों पर ड्राइवरलेस वाहनों का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। कम से कम 19 चीनी वाहन निर्माता और उनके मैन्युफैक्चरर्स इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडरशिप स्थापित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल कोई अन्य देश इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और जापान जैसे देश ड्राइवरलेस कार के मामले में पीछे हट रहे हैं। पिछले साल जनरल मोटर्स की क्रूज रोबोटैक्सी सेवा को अमेरिका में रोक दिया गया था, जब सैन फ्रांसिस्को में इसकी एक कार ने सड़क पर एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इसी क्रम में फोर्ड और फॉक्सवैगन ने दो साल पहले अपने रोबोट टैक्सी जॉइंट वेंचर 'आर्गो एआई' को बंद कर दिया था। पिछले साल जापान ने ड्राइवरलेस गोल्फ कार्ट के परीक्षण को रोक दिया था, जब उनमें से एक कार ने साइकिल चालक को टक्कर मार दी थी।

© The New York Times

कर्ज की चपेट में पाकिस्तान-यूक्रेन जैसे देश; 15 देश शिक्षा तो 46 देश स्वास्थ्य से ज्यादा ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहे

अर्थव्यवस्था

24 साल में सरकारी कर्ज चार गुना बढ़ा; विकासशील देशों पर 29 ट्रिलियन डॉलर कर्ज

पेट्रीसिया कोहेन

दुनियाभर के विकासशील देश अब बढ़ते कर्ज की चपेट में हैं। इन देशों में अर्जेंटीना, यूक्रेन और पाकिस्तान शामिल हैं। इस वक्त इन विकासशील देशों पर 29 ट्रिलियन डॉलर (तकरीबन 2400 लाख करोड़ रु.) का सरकारी कर्ज है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 15 देश शिक्षा पर खर्च करने से ज्यादा ब्याज के भुगतान पर खर्च कर रहे हैं। वहीं 46 देश स्वास्थ्य पर खर्च करने से ज्यादा कर्ज चुकाने में पैसा दे रहे हैं।

सरकारी कर्ज आज के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। लेकिन मौजूदा स्थिति शायद सबसे भयावह है। कुल मिलाकर दुनिया भर में सरकारी कर्ज साल 2000 के मुकाबले चार गुना ज्यादा हो गया है। यह समस्या अब वैश्विक मुद्दा बन गई है। पिछले हफ्ते ही वेटिकन सिटी में ग्लोबल डेट क्राइसिस पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस मीटिंग में वर्तमान पोप फ्रांसिस का संदेश बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बैठक में कहा कि दुनिया के सबसे गरीब देश भारी कर्ज से दबे हुए हैं और अमीर देशों को उनकी मदद के लिए और अधिक करने की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने अपने संदेश में अर्जेंटीना का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि 2001 में अर्जेंटीना के वित्तीय संकट के बीच उन्हें कार्डिनल नियुक्त किया गया था। फ्रांसिस ने खुद देखा था कि ऋण संकट कितनी तकलीफ और हिंसक दंगे पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े ऋण संकट की वजह क्या है?

सरकारी फिजूलखर्ची या कुप्रबंध एक कारण तो है ही, लेकिन वैश्विक घटनाओं ने भी ऋण संकट को बढ़ाया है। खासकर उन घटनाओं ने जिन पर अधिकांश देशों का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार लाभ और मजदूरों की आय कम हुई, लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य देखभाल और राहत लागत बढ़ी। यूक्रेन और अन्य जगहों पर हिंसक संघर्षों ने ऊर्जा और खाद्य कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया। केंद्रीय बैंकों ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरें लगातार बढ़ाईं, जिससे वैश्विक विकास धीमा हुआ है। कुल मिलाकर वजह कई हैं। लेकिन फिलहाल कोई सटीक समाधान निकलता नहीं दिख रहा।

चीन-अमेरिका के बढ़ते टकराव ने कर्ज संकटों को जटिल बनाया

दुनिया भर का सरकारी कर्ज आज न सिर्फ ज्यादा है बल्कि पहले से अलग भी है। पहले, ये कर्ज ज्यादातर पश्चिमी देशों के कुछ बड़े बैंकों और दशकों पुराने अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों के पास था। लेकिन आज उन पुराने लेनदारों के अलावा, देशों को हजारों निजी उधारदाताओं और चीन जैसे नए सरकारी लेनदारों के साथ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। समस्या यह भी है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने कर्ज संकटों को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। साथ ही, सभी लेनदारों पर अधिकार रखने वाला कोई एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी नहीं है।

अतिरिक्त शुल्क की वजह से देशों का कर्ज 50% ज्यादा बढ़ा

दूसरी ओर दुनिया की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही हैं और देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है, लेकिन आईएमएफ जैसी संस्थाओं से मिलने वाली मदद उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। मार्टिन गुजमैन अर्जेंटीना के पूर्व वित्त मंत्री हैं। वे पिछले हफ्ते वेटिकन सिटी की बैठक में थे। उनका मानना है कि आईएमएफ की मदद कभी-कभी उल्टा असर करती है। आईएमएफ कर्ज तो देता है लेकिन उस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, जिससे देशों पर पहले से ही मौजूद कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल यूक्रेन, मिस्र, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और पाकिस्तान जैसे 5 देशों ने सिर्फ सर चार्ज (अतिरिक्त शुल्क) के तौर पर ही 2 अरब डॉलर का भुगतान किया है। ये अतिरिक्त शुल्क कर्ज पर लगने वाले ब्याज के ऊपर का भार होता है। इस वजह से कर्ज लेने वाले सभी देशों के लिए कर्ज लेने की लागत औसतन करीब 50 फीसदी बढ़ गई है।

© The New York Times

युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन की 37 हजार एकड़ भूमि पर कब्जा किया

युद्ध

आंतरिक विरोध दबाने के लिए अतिक्रमण कर रहा इजराइल

बेन हबर्ड

दुनिया में सभी का ध्यान गाजा में चल रहे युद्ध पर है। जबकि अब इजराइली सैनिक वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा तेज कर रहे हैं। इजराइली मॉनिटरिंग ग्रुप के एक फील्ड रिसर्चर ड्रोर एटकेस ने अनुमान लगाया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों से 37 हजार एकड़ से अधिक भूमि हथिया ली है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इजराइल ने सबसे ज्यादा अतिक्रमण ₹तुकू' नामक क्षेत्र में किया है। इजराइल ने इधर 550 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा जमाया है। यहां इजराइल ने अपनी एक बस्ती जमाई है, जिसका नाम ₹टेकोआ' रखा है। यहां फिलिस्तीनियों की तुकू को इजराइलियों की टेकोआ से अलग करने वाला एक द्वार भी है।

सवाल है कि इजराइल अपना विस्तार तेजी से क्यों बढ़ा रहा है? दरअसल इजराइल को चिंता है कि गाजा में युद्ध के दौरान उसे वेस्ट बैंक में भी व्यापक अशांति का सामना करना पड़ सकता है या उसके सैनिकों और यहूदियों पर हमले बढ़ सकते हैं। इजराइल को यह भी डर है कि नए उग्रवादी समूहों का उदय हो रहा है। ईरान द्वारा तस्करी किए गए हथियार इन समूहों को मजबूत करेंगे और आम लोगों में अब हमास के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है। यह सभी कारण इजराइल को चिंता में डाल रही हैं।

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के बीच 5 लाख इजराइली भी रहते हैं

1967 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया है, तब से ही इजराइली सरकार ने यहूदियों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्हें भूमि, सैन्य सुरक्षा, बिजली, पानी और सड़कें प्रदान की हैं। इस क्षेत्र में अब 27 लाख फिलिस्तीनियों के बीच अब 5 लाख से अधिक बसने वाले यहूदी रहते हैं। कुछ इजराइली यहूदी धार्मिक आधार पर बसने को उचित ठहराते हैं। कई फिलिस्तीनियों को इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए क्षेत्र पर नियंत्रण को आवश्यक मानते हैं।

रोजगार पर बुरा असर पड़ा

इजराइली सेना ने फिलिस्तीनी श्रमिकों को इजराइली बस्तियों में प्रवेश करने से रोक दिया है। इससे तुकू के निवासियों के रोजगार पर भी चोट पहुंचाई है। तुकू के मेयर अल-शायर कहते हैं, 'इजराइल ने जो बंटवारे के लिए गेट बनाए हैं, उसने फिलिस्तीनी किसानों को जैतून की कटाई करने और चरवाहों को अपने पशुओं को चराने से रोक दिया है। गेट लगाए जाने के बाद स्थानीय फिलिस्तीनियों ने विरोध किया था। लेकिन जब वे गेट तोड़ने के लिए एकत्र हुए तब इजराइली सेना ने उन पर गोली चला दी, जिसमें 26 वर्षीय कार मैकेनिक ईसा जिब्रिल की मौत हो गई थी। उनके भाई मुराद कहते हैं कि ₹कुछ नहीं हुआ है। मैं किससे शिकायत कर सकता हूं? जब सेना ने ही उसे मारा है, तो क्या पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करेगी?'

© The New York Times

राजनीति

जेन-ज़ी वोटर्स को ख़ुश करने के लिए बाइडेन इंफ्लुएंसर्स से जुड़ रहे

केन बेनिंगर

जो बाइडेन का इलेक्शन कैंपेन अब जेन-ज़ी वोटर्स की ओर शिफ्ट हो रहा है। बाइडेन और उनके सहयोगी अपनी ऑनलाइन छवि को मजबूत बनाने के लिए उग्र रूप से काम कर रहे हैं। बाइडेन की टीम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भुगतान तक कर रही है, ताकि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाइडेन की प्रशंसा करें। इन इंफ्लुएंसर्स को व्हाइट हाउस और अभियान मुख्यालय के टूर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अब अगस्त में शिकागो में होने वाली डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में यह इंफ्लुएंसर्स विशेष रूम से आमंत्रित होंगे, जिसमें वीडियो बनाने की अनुमति दी जाएगी। इनमें से एक को कन्वेंशन में राष्ट्रपति के साथ इंटरव्यू का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन उनसे गाजा के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा गया है। मार्च में बाइडेन की डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी ने इंफ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को रखने के लिए डेढ़ लाख डॉलर खर्च किए। अप्रैल में बाइडेन की टीम ने कहा था कि वह सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए इंफ्लुएंसर्स को पैसे नहीं देते हैं। इसके बावजूद अपने सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम को चलाने के लिए इंफ्लुएंसर एजेंसी ₹विलेज मार्केटिंग' को उन्होंने लगभग 2 मिलियन डॉलर दिए। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने इंस्टाग्राम के कई पूर्व कर्मचारियों को नौकरी भी दी है और बाइडेन के इस अभियान ने उनके स्टाफ को बढ़ा दिया है। प्यू रिसर्च के अनुसार आधे अमेरिकी वयस्क यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से समाचार प्राप्त करते हैं। बाइडेन इन वोटर्स में संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में एनबीसी के एक सर्वेक्षण में बाइडेन उन वोटर्स में आगे थे, जो नियमित रूप से पारंपरिक समाचार पढ़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से सूचना प्राप्त करने वालों में ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से उन्हें पीछे छोड़ा। इसमें ट्रम्प 25 अंक से अधिक आगे हैं। टिकटॉक में बाइडेन-हैरिस कैंपेन के 3,75,000 फॉलोअर्स प्राप्त किए हैं। वहीं ट्रम्प के अब तक 62 लाख फॉलोअर्स हैं।

© The New York Times

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 104

जी7 में मोदी

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के चार दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 देशों की 50वीं शिखर बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचे। भारत उन 12 देशों और पांच संगठनों में शामिल था जिन्हें इटली के अपुलिया क्षेत्र में स्थित फसानो में जी7 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी ने वहां सही बातें कहीं। उनकी यह यात्रा यूरोपीय संघ के चुनावों के एक सप्ताह बाद हुई जो भारत के बाद दूसरी बड़ी चुनावी कवायद है जबकि जल्दी ही जी7 देशों- अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में चुनाव होने वाले हैं। निश्चित रूप से मोदी के भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के चुनावों के संचालन में शामिल प्रभावशाली व्यवस्थाओं पर केंद्रित था। उन्होंने भारतीय चुनावों को 'दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव' बताया। उनके भाषण में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। उन्होंने दुनिया को अधिक समतापूर्ण, लोकतांत्रिक जगह बनाने तथा तकनीक को विनाशकारी नहीं बल्कि अधिक रचनात्मक बनाने के लिए तकनीक तक पहुंच की महत्ता की बात कही।

ग्लोबल पाटर्नरशिप फॉर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य और प्रमुख के रूप में तकनीकी क्षेत्र में एकाधिकार खत्म करने की उनकी मांग दुनिया भर की सरकारों के मौजूदा मिजाज से मेल खाती है- खासतौर पर यूरोप की सरकारों के साथ क्योंकि वे बड़ी तकनीकी कंपनियों की ताकत को चुनौती दे रही हैं। 'हरित युग' को अपनाने की उनकी अपील सही है। वह इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया के अमीर और सबसे अधिक ताकतवर देश गरीब देशों पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले उपायों को अपनाने के लिए जरूरी फंडिंग कर सकें। वह यह उल्लेख करना नहीं भूले कि भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है जिन्होंने समय से पहले कॉप के तहत अपनी प्रतिबद्धता निभाई। शायद जी7 देशों को उनका सबसे सीधा संदेश ग्लोबल साउथ अथवा विकासशील देशों के बारे में था, भारत जिनका नेतृत्व करना चाहता है, जैसा कि उसने नई दिल्ली में गत वर्ष जी20 देशों की बैठक में अफ्रीका को सदस्यता देने का फैसला किया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल साउथ के देश ही वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों के सबसे अधिक शिकार हैं। उनका इशारा दरअसल गाजा में चल रही जंग की तरफ था।

कूटनीति के मामले में लाभ मिलाजुला रहा। जी20 शिखर बैठक के बाद भारत-अमेरिका के रिश्तों के तनाव में कमी आई लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। अधिकारियों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि वे कैलेंडर में तालमेल नहीं बिठा सके। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ भी हाथ मिलाया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा की धरती पर हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था और इस मुलाकात से लगता है कि दोनों देशों के बीच संवाद अभी कायम है। बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ 'बहुत अहम मुद्दों' को हल करने के लिए आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता की बात की। लेक लुसर्न के करीब स्विस शांति सम्मेलन के ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात करके मोदी ने भारत की इस स्थिति को रेखांकित किया कि रूस के साथ जंग को बातचीत और कूटनीति के जरिये हल करना ही बेहतर है। हालांकि मोदी घरेलू प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए उक्त सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। भारतके लिए सबसे ठोस लाभ शायद जी7 की उस प्रतिबद्धता से उपजा जिसमें कहा गया कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा दिया जाएगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा गत वर्ष जी20 शिखर बैठक के समय गई थी, हालांकि यह इजरायल-हमास युद्ध के हल होने पर निर्भर है। मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में जी7 बैठक एक बेहतर वैश्विक मंच साबित हुई है।

संघ और भाजपा के बीच मतभेद की वास्तविकता

आरएसएस और भाजपा का इतिहास प्रेमियों के बीच होने वाली नोकझोंक का जैसा रहा है। यह सोचना कि आरएसएस भाजपा के नेतृत्व में कोई बदलाव लाएगा सही नहीं है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के अहंकार को लेकर वक्तव्य देना शुरू किया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसी चार घटनाओं में सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के समापन अवसर पर दिया गया भाषण, संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य और आरएसएस समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार द्वारा अहंकार का विशेष जिक्र शामिल है। कुमार ने कहा कि भगवान राम ने भाजपा को 240 सीट पर सीमित करके उसे उसके अहंकार का दंड दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रामराज्य के न्याय ने यह भी सुनिश्चित किया कि 'इंडिया' गठबंधन उससे भी कम 237 सीट पर सीमित रहे क्योंकि वह राम विरोधी है।

आरएसएस के एक बुद्धिजीवी रतन शारदा अक्सर टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के पन्नों पर संगठन की विचारधारा और उसका नजरिया रखते हैं। उन्होंने खासतौर पर आलोचना करते हुए कहा कि उसने आरएसएस की आलोचना करने वाले लोगों को पार्टी में जगह देकर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को नुकसान पहुंचाया और कीमत चुकाई। चौथा है एक लेख जो आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' में प्रकाशित हुआ। इसमें महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को वजह बताया गया। इन चार घटनाओं को देखें तो बीते एक दशक में यह आरएसएस की ओर से भाजपानीत मोदी सरकार की पहली संगठित आलोचना प्रतीत होती है। भागवत ने तो अपने भाषण में यह तक कहा कि वह विरोधी पक्ष को प्रतिपक्ष कहना पसंद करेंगे। यह बात हमें अगले प्रश्न की ओर लाती है। आरएसएस क्या हासिल करना चाहता है? इसमें वे सभी शामिल हैं जो सत्ता की राजनीति में कुछ हिस्सेदारी रखते हैं या राजनीतिक बहस में जिनकी अपनी एक आवाज है।

सबसे पहले तो यकीनन वह यह देखकर आनंदित होगा कि उदारवादी धड़ा उसके हस्तक्षेप को लेकर कितना प्रसन्न है। वह समुदाय जिसने दशकों तक आरएसएस के विचार से लड़ाई लड़ी है अब उसे उसके प्रमुख की आलोचना में सहारा मिल रहा है। यह बात विडंबनापूर्ण तो है ही, हताशा को भी दर्शाती है। यहां तक कि कांग्रेस में भी कुछ लोगों ने भाजपा को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। आंशिक तौर पर उनका यह भी मानना है कि इससे नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। भागवत के बयान को उद्धृत करते हुए आलेखों और सोशल मीडिया पोस्ट की बाढ़ आ गई। इनमें कहा गया, 'हम समझते हैं कि आप (प्रधानमंत्री मोदी) हमारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन कम से कम मोहन भागवत को सुनिए।' चार जून के बाद के इस नए दौर में आरएसएस प्रमुख को मोदी-शाह की भाजपा की तुलना में थोड़ा कम उदार लेकिन अधिक स्वीकार्य माना जा रहा है।

यह हालात का अत्यधिक गलत पाठ है। तथ्य तो यह है कि आरएसएस-भाजपा के रिश्ते ऐसे ही रहे हैं। इनमें कोई उल्लेखनीय बदलाव शायद ही आया हो। यह सोचना कि नागपुर की वजह से भाजपा नेतृत्व में कोई बदलाव लाएगा, इरादे और शक्ति दोनों का गलत पाठ है।

चुनाव ने मोदी के आलोचकों को दिखाया है कि मोदी को हराया जा सकता है। बहरहाल इसके लिए अगले पांच सालों तक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। एक के बाद एक राज्य के चुनावों में ऐसा करना होगा। ऐसा आंतरिक तख्तापलट से नहीं होगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे संकेत मिले कि आरएसएस अपनी ही सरकार को अस्थिर करना चाहता है।

अगर वे गुरु हैं और मौजूदा भाजपा नेतृत्व में उनके शिष्य हैं तो इसे इस तरह देखा कि नाखुश शिक्षक अपने छात्रों को खराब प्रदर्शन के लिए झिड़क रहा है। ऐसा नहीं है कि अतीत में कभी भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद नहीं हुए। हम तीन उदाहरण देखेंगे लेकिन इस बार चुनाव के बाद जो नजर आया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ।

मौजूदा भाजपा की स्थापना 1980 में मूल भारतीय जनसंघ से हुई थी। वर्ष 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था लेकिन वह पार्टी टूट गई। तब से हम भाजपा-आरएसएस के रिश्तों को देख रहे हैं। वर्ष 1984, 2004 और 2024 के तीन उदाहरणों पर विचार कीजिए।

पहली बार 1984 में भाजपा की गलती नहीं थी। उस समय पंजाब संकट को लेकर चिंतित आरएसएस इस भावना में आ गया था कि उसे राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। संकट के उस दौर में उसने निष्कर्ष निकाला कि भारत भाजपा की हिस्सेदारी वाले किसी गठबंधन की सरकार के बजाय राजीव गांधी के अधीन अधिक सुरक्षित होगा। उस समय राजीव गांधी और सरसंघचालक बालासाहब देवरस के बीच मुलाकात की भी खबरें आई थीं।

मैंने उन चुनावों में कवरेज की थी। खासतौर पर मध्य प्रदेश और दिल्ली में और पाया था कि आरएसएस के कार्यकर्ता न केवल भाजपा के प्रचार से अनुपस्थित थे बल्कि अक्सर वे स्थिरता और राष्ट्रहित के नाम पर कांग्रेस को वोट देने की बात कहते पाए जाते थे।

आरएसएस को भाजपा से कोई शिकायत नहीं थी। बस उसका समय नहीं आया था। सन 1998 में आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनने का जश्न मनाया था। हालांकि उनका व्यक्तित्व और स्वभाव तत्कालीन सरसंघचालक के एस सुदर्शन से मेल नहीं खाता था और 2003 तक तनाव साफ नजर आने लगा था। 2004 के चुनाव में भी आरएसएस में भी बहुत अधिक रुचि नहीं ली। वाजपेयी और आडवाणी ने चुनाव को तय समय से पांच माह पहले करा लिया था। सरकार मामूली अंतर से वापसी करने में नाकाम रही थी।

सुदर्शन ने अप्रैल 2005 में एनडीटीवी के लिए एक कार्यक्रम में मेरे साथ बातचीत की थी और ऐसी अनेक बातों को रेखांकित किया था। इस साक्षात्कार के लिए सरसंघचालक के कार्यालय से अनुरोध किया गया था। मैंने इसकी मांग नहीं की थी क्योंकि आरएसएस प्रमुख अक्सर साक्षात्कार नहीं देते थे। वाजपेयी के सत्ता से जाने के बाद सुदर्शन की बातचीत का स्वर लगभग ऐसा था मानो वे कह रहे हों- यह तो होना ही था काश उन्होंने हमारी बात सुन ली होती। इस समय तक आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के रूप में एक युवा नेता के उभार को भी चिह्नित कर लिया था जो उसकी विचारधारा में अधिक आस्था रखते थे।

बीस वर्ष और आगे बढ़ें तो 2024 के चुनावों की बात आती है। अब भाजपा यह मानने लगी थी कि उसे बस मोदी के नाम पर प्रचार करना है। आरएसएस को शायद यह लगा कि उसे कुछ किनारे किया गया है। हालांकि कश्मीर में अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक का खात्मा आदि कई वैचारिक मामलों में मोदी ने आरएसएस की वैचारिक परियोजनाओं को पूरा किया था। मोदी ने भी भागवत को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पूरी प्रतिष्ठा दी थी।

विचारधारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया लेकिन स्वयंसेवक को बस यह अहसास कराया गया कि वह अपरिहार्य नहीं है। भागवत ने पिछले दिनों अपने भाषण में कहा कि आरएसएस ने इस चुनाव में वही किया जो उसने हमेशा किया है: जनता के विचारों को दुरुस्त करना। परंतु भाजपा ने खुद कहा कि उसे लगता है कि वह अपने दम पर काम कर सकती है और उसे आरएसएस के सहारे की आवश्यकता नहीं है। शायद इसी वजह से दोनों पक्षों में उदासीनता पैदा हुई।

यह चुनाव नतीजों के पहले की बात है। बात कह दी गई और मामला खत्म हो गया। यह सरकार, मोदी और शाह की ताकत दोनों आरएसएस के लिए जरूरी हैं, खासकर तब जबकि वह अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि उसकी बातें शिक्षक की ओर से छात्र को झिड़की के समान है। इससे अधिक कुछ भी सोचना गलत होगा और मोदी के प्रतिपक्ष के लिए खुशफहमी की तरह होगा। इन बातों के बीच ही भागवत गोरखपुर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भाजपा को मजबूत करने के बारे में चर्चा की।

भारत और फ्रांस के बढ़ते सामरिक संबंध

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

चार देशों के सुरक्षा गठजोड़ (क्वाड) और उसकी सैन्य कवायद- मलाबार युद्धाभ्यास को हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने में सीमित कामयाबी मिली है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सितंबर 2021 में अपने दो सबसे मजबूत और सक्षम क्षेत्रीय सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को साथ लेकर एक 'ऑकस' समूह बनाया। ऑकस ने तत्काल घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक सशस्त्र परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी बेड़ा तैयार करने में मदद की जाएगी। ऑकस के दो स्तंभ होने थे: स्तंभ एक में ऑस्ट्रेलिया को बगैर परमाणु हथियारों के परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन (प्रपल्शन) का असाधारण हस्तांतरण होना था। जबकि दूसरे स्तंभ में आठ सैन्य एवं उच्च तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना था जो थे: आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नॉलजी, नवाचार, सूचना साझेदारी, साइबर सूचना, समुद्र के भीतर की गतिविधि, हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध।

हाल ही में निकट सहयोग से जुड़ी एक अन्य घोषणा करते हुए ऑकस ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक उसके तीन सदस्य देश एक नई 'त्रिपक्षीय व्यवस्था' बनाएंगे जो उन्हें पी-8 पोसाइडन सोनोबॉय (यह उपकरण जो पानी में गतिविधियों का पता लगाता है) से सूचना साझेदारी का अवसर देगी। यह ऑकस पिलर2 की पहली तकनीक है जो सामने आ रही है।

ऑकस के सभी तीन सदस्य देश चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए बोइंग निर्मित पी-8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमानों का प्रयोग करते हैं जिन्हें दुनिया में पनडुब्बियों का पता लगाने में सबसे सक्षम विमान माना जाता है। पी-8 के काम करने के तरीके की बात करें तो वह सोनोबॉय को पानी में गिराकर पनडुब्बियों का पता लगाता है। सोनोबॉय ट्रैकिंग के आंकड़ों को साझा करना दिखाता है कि ये देश किस तरह सूचनाएं जुटा रहे हैं। आधुनिक युद्ध कला में सॉफ्टवेयर की प्रमुखता को देखते हुए यह बात ध्यान देने लायक है कि ऑकस पहले ही पिलर 2 के माध्यम से सॉफ्टवेयर क्षमता प्रदान कर रहा है। अमेरिका के पास 120 पी-8 पोसाइडन हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 12 और यूके के पास नौ। सोनोबॉय सूचना बहुत संवेदनशील होती है। यहां तक कि फाइव आई साझेदारों यानी ऑकस देशों तथा कनाडा और न्यूजीलैंड के लिहाज से भी। तीनों ऑकस देशों के पास उपलब्ध आंकड़े उनकी पहुंच तथा दायरा बढ़ाएंगे क्योंकि वे एक दूसरे के आंकड़े साझा कर सकेंगे।

सितंबर 2021 में की गई घोषणा में भारतीय नौसेना की चूक स्पष्ट रूप से देखी गई जो 12 पी-8 विमान संचालित करती है। परंतु ऑकस एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बहुत करीबी साझेदारों के बीच रहना है। अमेरिका ने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां देने का निर्णय लिया। इससे दशकों पहले एक बार उसने ब्रिटेन को कुछ परमाणु तकनीक संबंधी सहायता प्रदान की थी। कोई अन्य देश, खासकर भारत को कभी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की सहायता पेशकश अमेरिका ने नहीं की।

अमेरिका द्वारा अपनी इस सामरिक परंपरा को तोड़ना बताता है कि वह ताइवान को लेकर किसी और संकट की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की मदद को अनिवार्य मानता है। परंतु अमेरिकी सेना भारत को इन व्यवस्थाओं में शायद ही कभी अपरिहार्य माने अमेरिका मानता है कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अमेरिकी सेना के साथ लड़ेंगे। यही वजह है कि उसकी नजर में ऑस्ट्रेलियाई सेना को उच्च तकनीक और उपकरणों से लैस करना जरूरी है।

ऑस्ट्रेलिया स्वयं को एशिया में अमेरिका का सबसे विश्वसनीय सहयोगी मानता है। पहले विश्व युद्ध से ही वह हर युद्ध में अमेरिका के साथ लड़ा है। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अहम हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए सवाल यह है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा समर्थन करता है तो हम उसे कितना अधिक क्षमता संपन्न बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही बताता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई सेना को मजबूत बनाने का निर्णय क्यों लिया।

पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के अन्य संभावित साझेदारों की बात अलग है। जापान का दावा है कि वह पिलर 2 के कई क्षेत्रों में अपने दम पर अहम प्रौद्योगिकी क्षमता रखता है। इसके चलते उसे किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जापान के समक्ष सीधा सवाल चीन का है। क्या उसे चीन के विरुद्ध अमेरिकी अभियान में शामिल होना होगा? पिलर 2 के मसले पर जापानियों का कहना है कि उन्हें आमंत्रित तो किया गया है लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल होगा या कुछ गंवाना होगा?

इस बीच अमेरिका और भारत की नौसेनाएं चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने में सहयोग कर रही हैं। सवाल यह है कि यह सहयोग कितना मजबूत है? भारत के अपने पूर्वग्रह हैं। हमारे कूटनयिकों के मुताबिक भारत के पूर्वग्रह समझे जा सकते हैं क्योंकि अगर आप चीन के पड़ोसी देश हैं तो आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ न करें जिससे वह भड़के। चीन कई तरह से मुश्किल खड़ी कर सकता है।

समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना के पास सहयोग के कई विकल्प हैं क्योंकि नौसेनाएं अक्सर जमीनी सीमा से दूर काम करती हैं जहां जल्दी ध्यान नहीं जाता। इतना ही नहीं समुद्र में दो नौसेनाओं के बीच का सहयोग साफ नजर आने के बजाय छिपा अधिक होता है। अमेरिका और भारत का नौसेना सहयोग अभी संयुक्त अभ्यास के स्तर पर नहीं पहुंचा है हालांकि अमेरिका नॉर्वे और आइसलैंड समेत तमाम देशों के साथ ऐसे अभ्यास करता है। इसकी एक वजह है दोनों के बीच क्षमताओं का बड़ा अंतर। दूसरी वजह है भारत का सुर्खियों से बचने का प्रयास। भारत खामोशी से अभ्यास करना चाहता है हालांकि एक सीमा से परे ऐसा करना मुश्किल होता है।

भारत के लिए क्या सबक हैं? भारत हाशिये पर खड़ा होकर यह देखेगा कि एक परमाणु संपन्न पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है। परंतु अमेरिका कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि भारत के साथ परमाणु पनडुब्बी के मामले में सहयोग करने में भूराजनीतिक स्थितियां बाधा बन रही हैं। भू-सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से शायद अमेरिका के लिए यही बेहतर है कि वह हाशिये पर रहे और फ्रांस को यह काम करने के लिए प्रोत्साहित करे।

भारत और फ्रांस के बीच पनडुब्बियों और विमानों को लेकर होने वाले सहयोग को देखते हुए यही मानना उचित होगा कि फ्रांस आगे आए और भारत के साथ पनडुब्बी के क्षेत्र में काम करे। फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों को तकनीकी दृष्टि से बेहतरीन माना जाता है। वे हमारी पनडुब्बियों की तुलना में ये छोटी होती हैं और परिचालन के नजरिये से भी ये बेहतर होती हैं। फ्रांस की समुद्री परमाणु तकनीक को अमेरिका से उन्नत माना जाता है। अमेरिकी रिएक्टरों के उलट फ्रांस के परमाणु पनडुब्बी रिएक्टर कम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सामरिक रिश्ते के बीच समुद्री रिश्ते को रक्षा, अंतरिक्ष, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों के संरेखित करना बेहतर होगा। दोनों देशों के बीच ये रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।

आपका पक्ष

भीषण गर्मी के बीच गहराता जलसंकट

इन दिनों उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ-साथ जल संकट भी व्याप्त है। मॉनसून के केरल तट पर दस्तक के बाद दक्षिण भारत में बारिश से जहां लोगों को राहत मिल रही है, वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के बीच लोगों को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की कमी की वजह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हर साल पानी की समस्या उत्पन्न होती है लेकिन राज्य सरकार इस समस्या का आजतक स्थायी हल नहीं खोज पाई है। दिल्ली में जब भी जलसंकट आता है तो पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग होने लगती है। दिल्ली सरकार हर साल हरियाणा को ज्यादा पानी छोड़ने का दबाव बनाती है। अव्वल तो इस जलसंकट की मूल समस्या को समझने की जरूरत है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में ही जलापूर्ति की समस्या क्यों होती है। हालांकि दिल्ली सरकार पानी की समस्या के लिए अदालत की रुख करती हैं। लेकिन हर साल की कहानी वही है। दिल्ली में जलसंकट के समाधान के लिए जल विभाग को दुरुस्त करने, विभागीय ऑडिट कराने, पाइप-लाइन में लीकेज बंद करने, पानी को बरबाद होने से रोकने तथा सभी जगहों में एक समान जलापूर्ति करने की जरूरत है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली की कुछ जगहों में जलसंकट के बाद टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है

उच्च शिक्षा में छात्रों को मिले पर्याप्त अवसर

लेख 'नई दाखिला व्यवस्था' उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर सार्थक एवं सारगर्भित चर्चा की गई है। विश्वविद्यालयों की आधारभूत आवश्यकताओं, संरचना पर भी प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। अगर केवल प्रवेश परीक्षाओं तक ही विषय को सीमित रखा जाए तो उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, विधि विषयक प्रवेश परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उड़ान भरती आकांक्षाओं ने ही समानांतर कोचिंग उद्योग को ही प्रोन्नत किया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लगभग 14 लाख भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इसके दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं कि छात्रों की संख्या के अनुपात में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यालयों की बहुत कमी है और दूसरा प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के 'नीट' विवाद को देख ही रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, विधि की उच्च शिक्षा में स्कूली, बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का वेटेज, नैशनल टैलेंट हंट जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित की गई प्रतियोगिताओं, स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित प्रतिस्पर्धाओं, डिबेट, मॉडल आदि के स्कोर का विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में वेटेज नहीं दिया जाएगा, प्रतिभाशाली छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। विषय यहीं समाप्त नहीं होता है। केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के साथ उच्च शिक्षा के प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप को बदलने की बहुत आवश्यकता है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की। रविवार को आयोजित सम्मेलन में 80 देशों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया कि रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी शांति समझौते का आधार यूक्रेन की 'क्षेत्रीय अखंडता' हो। रूस को सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जल का जंजाल

भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के लोगों को पानी की कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से मानवता के आधार पर अधिक पानी देने की अपील की है। अगर हरियाणा के पास अधिक पानी है तो उसे मदद जरूर करनी चाहिए।

कोर्ट नहीं विशेषज्ञ | दिल्ली जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। हालांकि अदालत का यह कहना बिल्कुल सही है कि उसके पास पानी के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं। वैसे भी अभी यह समय फॉर्मूला निकालने का नहीं है। अभी दिल्ली को पानी चाहिए, जल्द से जल्द।

पुराने समझौते में बदलाव हो

पुराना समझौता | पानी को लेकर हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के बीच 1994 में एक MoU साइन हुआ था। हालांकि इस बात को तीन दशक बीत चुके हैं और इस दौरान दिल्ली की आबादी, उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए पुराने समझौते में बदले हुए हालात के मुताबिक बदलाव करना बेहतर होगा।

बेअसर इंतजाम | पानी की समस्या केवल दिल्ली की नहीं, देश के लगभग सभी बड़े शहर इससे जूझ रहे हैं। कुछ अरसा पहले बेंगलुरु से ऐसी खबरें आ रही थीं। मुंबई में भी इस साल BMC को पानी में कटौती करनी पड़ी। यह साफ इशारा है कि हमारा जल प्रबंधन ठीक नहीं। अभी तक जो भी इंतजाम किए हैं हमने, वे कारगर नहीं हो पा रहे हैं। वक्त है कि उनकी फिर से समीक्षा की जाए।

प्रभावी उपाय | हमारे शहर जिस संकट का सामना कर रहे हैं, वह केवल इस साल की कहानी नहीं है। जलवायु परिवर्तन का असर गहराने के साथ यह संकट भी बढ़ता जाएगा। इससे बचने के लिए प्रभावी और दूरगामी कदम उठाने होंगे। हमारी नदियों में पानी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। तमाम नदियों का पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा है। यही हाल तालाब, कुओं और दूसरे जलाशयों का भी है। कई जगह अतिक्रमण हो चुका है। इस पर एक्शन लेना होगा।

एक्शन में देरी | दिल्ली में जब संकट गहराया है तो टैंकर माफिया की बात चल निकली है। लेकिन, सोचने वाली बात है कि ये माफिया एकाएक तो इतने मजबूत हुए नहीं होंगे। इन पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? और इन्हें किनकी शह मिल रही है? इसी तरह वॉटर रीसाइक्लिंग और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज पर कितना काम हो रहा, यह भी चेक हो।

गरीबों का ध्यान | पानी जैसी बुनियादी जरूरत की किल्लत सबसे ज्यादा मार करती है गरीबों पर। अमीर तबका पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन टैंकर के पीछे दौड़ने और सार्वजनिक नलों पर धूप में लंबी लाइन लगाने वाली आम जनता कहां जाए? उसके पास कोई चारा नहीं, ऐसे में किसी भी पॉलिसी में इनका ध्यान रखना चाहिए। यह मसला अब राजनीति का नहीं रह गया है।

चक्र-व्यू

फैज़ाबाद में होम स्टे

राहुल पाण्डेय

फैजाबाद में जितने होटल हैं, उससे चौगुनी तादाद में अब होम स्टे खुल चुके हैं। फैजाबाद से अयोध्या की ओर चलें तो साहबगंज पार करते ही हर चौथे-पांचवे घर में एक होम-स्टे खुल चुका है। खुद मेरी कॉलोनी अमानीगंज में ढेरों होम स्टे चल रहे हैं। इन होम स्टे के बाहर अक्सर कोई साइन बोर्ड भी नहीं होता। कई सारे लोग ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हैं। कइयों ने बस और रेलवे स्टेशन पर अपने नाते-रिश्तेदारों की ड्यूटी लगा दी है कि जैसे ही जजमान पहचान में आएं, फटाफट पकड़ लाओ! जो लोग मकान यहां बनवाकर काम-धंधे के चक्कर में बाहर रह रहे हैं, वो भी इसी तलाश में हैं कि कोई पार्टी मिल जाए तो महीने की एक गांठ तो पक्की हो। सूरतेहाल कुछ यूं है कि समझ में नहीं आता, शहर में मकान ज्यादा टूटे हैं या डॉरमेट्रियां ज्यादा बनी हैं। कल छोटे भाई ने बताया कि बेनीगंज से पहले उनके एक परिचित 40 कमरों का होटल बनवा रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कभी उन्होंने पहले होटल चलाया है? जवाब ना में मिला। फिर पूछा, तो कभी होटल में काम तो किया ही होगा? इसका जवाब भी ना ही निकला। फिर चलाएंगे कैसे? भाई ने बताया, यही उनकी भी समस्या है कि उन्हें होटल चलाना नहीं आता। इसलिए वो पूरी बिल्डिंग ही किराए पर उठाने की सोच रहे हैं। यानी होटल तभी चलेगा, जब कोई उसे किराये पर लेगा।

पिछले हफ्ते फैजाबाद गया तो बचपन के दोस्त शहजादे मिले। बताने लगे कि साहबगंज छोड़ो, यहां तो सहादतगंज यानी फैजाबाद का वह कोना, जो अयोध्या से एकदम विपरीत छोर पर स्थित है, वहां भी लोग होम स्टे चलाने लगे हैं। जिसके घर में तीन कमरे हैं, वह भी अपना एक कमरा अलग करके उसमें रहने-खाने और निकालने का इंतजाम कर चुका है। जैसा इंतजाम, वैसा किराया। कोई 800 एक रात का ले रहा है तो कोई 1800। यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, और जवाब जानते हुए भी मैंने इन दिनों का सबसे घटिया सवाल पूछ ही लिया, फिर क्यों लोग कह रहे हैं कि फैजाबाद वालों ने सरकार को वोट नहीं दिया? शहजादे हंसने लगे। बोले, शहर में किसने वोट नहीं दिया? सबने मिलकर वोट दिया। शहजादे की बात एकदम सही थी। इसे आंकड़े भी साबित करते हैं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, फिर हार क्यों हुई? शहजादे बोले, होम स्टे शहर में चल रहे हैं। पैसा सहादतगंज से लेकर साहबगंज में आ रहा है। देवी तिवारी का पुरवा हो या श्यामलाल का, गांव तो पहले की तरह ही बर्बाद हैं। न पानी है, न बिजली है, न ही बाजार में रौनक है। यह सब बताकर शहजादे बोले,

एकदा

नन्हे चर्चिल की होशियारी

चर्चिल का जन्म इंग्लैंड के आक्सफर्डशर के ब्लेनहिम पैलेस में हुआ था। पिता रेंडोल्फ हेनरी स्पेंसर चर्चिल ब्रिटिश रईस और जाने-माने राजनीतिक थे। चर्चिल का बचपन उपेक्षित था। नर्स एवरेस्ट ने ही उनका पालन-पोषण किया। उनकी स्कूली पढ़ाई के स्तर से पिता खुश नहीं थे। एक बार इंग्लैंड के सेनापति लॉर्ड किचनर उनके घर आए। बालक को रेत और पत्थरों से युद्ध का मैदान बनाकर खेलते देखा। किचनर ने मजाक में पूछा, 'बेटा, अगर शत्रु ने पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया तो? चर्चिल बोले, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं। पश्चिम की तरफ नदी है। उसके ऊपर बने पुल को काट दिया जाएगा। 'सेना ने उत्तर दिशा से आक्रमण कर दिया तो?' चर्चिल ने कहा, 'उस रास्ते से जैसे ही सेना लौटेगी, वहां तैनात तोपें बारूद उगलना चालू कर देंगी।' इसके बाद किचनर ने चर्चिल के पिता से कहा, 'यह बालक होनहार है।' इस पर असंतोष जताते हुए चर्चिल के पिता ने कहा, 'इसकी पढ़ाई का स्तर बिलकुल संतोषजनक नहीं है।' इसके बाद सेनापति किचनर की सलाह पर पिता ने चर्चिल का करियर सेना में बनाने फैसला किया। रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश परीक्षा को पास करने में उन्हें तीन प्रयास लगे, पर एक बार वहां पहुंचने के बाद चर्चिल ने गंभीरता से अध्ययन किया। चर्चिल सेना में शामिल हो गए। काफी समय बाद किचनर ने चर्चिल के पिता को बताया कि आपका बेटा आज इंग्लैंड की सेना का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। आप उसकी प्रतिभा पहचान नहीं सके थे। विंस्टन चर्चिल आगे चलकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और कई सैन्य अभियानों को सफल बनाया। उनकी पुस्तक 'The River War' (1899) में इसका वर्णन मिलता है।

AI Image

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

चीन को रोकने वाली ताकत के रूप में हमें देखता है पश्चिम, पर भारत के लिए सबसे ऊपर हो राष्ट्रहित

भारत को G7 से चाहिए मॉडर्न टेक्नॉलजी

अमिताभ सिंह

G7 सात देशों का एक खास क्लब है, जो 70 के दशक में बना। पहले छह देश एक साथ आए थे ताकि तेल संकट से पैदा हुए मुश्किलों का सामना कर सकें। बाद में कनाडा इस ग्रुप में शामिल हो गया। फिर इसे G7, यानी औद्योगिक देशों का समूह कहा जाने लगा। 1997 में रूस इस ग्रुप का सदस्य बना, जिससे यह G8 बन गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसे ग्रुप से निकाल दिया गया।

भारत की भूमिका | दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत अपनी समझदारी, रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए दुनिया में अहम भूमिका निभा रहा है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में जो सहमति बनी थी, वह रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राइल-गाजा संघर्ष से टूट गई है। इस वजह से बहुपक्षीय और छोटे-छोटे समूहों के बीच बैठकों और शिखर सम्मेलनों पर जोर दिया जा रहा है ताकि दुनिया में शांति, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

वैश्विक चेहरा | भारत G7 के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है और 11 बैठकों में हिस्सा ले चुका है। इनमें से 5 का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत की अर्थव्यवस्था 3.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि G7 के चार देशों, यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस, कनाडा और इटली की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। भारत की अमेरिका, UK, फ्रांस, जापान और जर्मनी के साथ रणनीतिक साझेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ग्लोबल साउथ का चेहरा बन गया है। इसने G20 का नेतृत्व भी किया है, जो ग्लोबल साउथ और विकसित देशों का केंद्र है।

क्या करे भारत
- चीन से विवाद को न दी जाए हवा
- पश्चिमी देशों से मूर्त लाभ की मांग
- बातचीत में राष्ट्रहित सबसे ऊपर हो

मजबूत ग्लोबल साउथ | इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 सम्मेलन से पहले कहा कि 'ग्लोबल साउथ के साथ बातचीत को मजबूत करने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी कहा कि 'G7 अपने आप में बंद किला नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने पेश किए जाने वाले मूल्यों का प्रस्ताव है।' इस लिहाज से देखें तो भारत आदर्श राष्ट्र है।
- भारत ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण देश है। उसकी आवाज दुनिया सुनती है।
- भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है और इस दिशा में काम कर रहा है।
- पश्चिमी देशों को मजबूत और विश्वासपात्र सहयोगी की जरूरत है और भारत इसके लिए पूरी तरह से योग्य है।

लंबे अरसे से विकासशील देश G7 की आलोचना अमीर देशों के क्लब के रूप में करते रहे हैं। G7 की बैठकों का विरोध करने वाले वैश्वीकरण और पूंजीवाद-विरोधी कार्यकर्ताओं का सड़कों पर पुलिस के साथ संघर्ष पहले आम बात थी।

AFP

G7 समिट के दौरान पोप फ्रांसिस, पीएम मोदी, जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक

चीन का खतरा | दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर में चीन के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, इसलिए G7 को भारत का साथ चाहिए। इसके अलावा, पड़ोसी देशों और पश्चिम के लिए भी चीन खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए भी पश्चिमी देशों को भारत की जरूरत है। एक फिक्र चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे को लेकर भी है, जिसे पश्चिम 'ओवरप्रॉडक्शन' कहता है। पश्चिमी देशों को लगता है कि अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भी चीन विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है।

मिले ठोस लाभ | ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर विकसित देशों की तरफ से भारत को अभी तक अमूर्त लाभ ही मिल रहे हैं। भारत को इन देशों से ठोस लाभों की भी मांग करनी चाहिए। भारत को कहना चाहिए कि उसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में रिसर्च, महत्वपूर्ण और उन्नत तकनीक और उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन में निवेश की जरूरत है। चीन इसी रास्ते से दुनिया में इतना ताकतवर बना है।

बुनियादी ढांचा | भारत को G7 से कुछ लाभ हुए भी हैं। इनमें से एक है, भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEEC)। यह चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशटिव (BRI) का जवाब है। यह प्रॉजेक्ट शुरुआत में मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने के लिए था, लेकिन बाद में इसे भारत तक बढ़ा दिया गया। यह PGII (पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट) का हिस्सा है, जो बुनियादी ढांचे और परिवहन गलियारों को विकसित करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं को विकसित करने का इरादा रखता है।

साथ की बात | विदेश नीति के कई जानकार कहते हैं कि भारत को खुलकर पश्चिम का साथ देना चाहिए। मगर भारत को इससे बचना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने से ही भारत का फायदा हो सकता है। उसे पश्चिमी मीडिया और स्थानीय पश्चिमी विशेषज्ञों की इस तरह यह कहने से बचना चाहिए कि वह चीन को रोकने वाली ताकत है। यह बात सही है कि चीन के साथ भारत की अपनी समस्याएं हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। लेकिन इन्हें एक सीमा से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। हमें G7 और पश्चिम की उतनी ही जरूरत है जितनी उन्हें हमारी। राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोच्च होना चाहिए।

(लेखक JNU में असोसिएट प्रफेसर हैं)

कद ही नहीं, आपकी खुशियों का भी पैमाना है चेक

एक ब्रैंडिंग होती है simplicity वाली। इसका मतलब सादा नहीं होता, बल्कि होता है सरल, जो अपनी बात आसानी और असरदार तरीके से सामने वाले तक पहुंचा दे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि हर चीज उतनी सरल होनी चाहिए, जितनी हो सकती है। Leonardo da Vinci तो सरलता को ही सबसे बड़ी सुंदरता मानते थे। तो अगर बाजार, विज्ञान और कला को मिलाकर कोई एक चीज बनाई जाए, जो ऊपर की सारी बातों पर खरी उतरी, तो शायद उसकी शक्ल चेक जैसी होगी।

कागज का एक टुकड़ा, जो तब तक साधारण कागज ही रहता है, जब तक कि उसे भर न दिया जाए। हर उस शख्स के पास हो सकता है, जिसके पास बैंक अकाउंट है। पाना आसान है इसे और इस्तेमाल करना सरल, लेकिन है यह ताकतवर। चेक किसी की क्षमताओं का आईना हो सकता है। एक शख्स की मेहनत और हुनर को दर्शाता है। चेक ही है, जो cancelled लिखे जाने के बाद भी काम का बना रहता है।

इसे लिखा जाता है, लेकिन आम भाषा में कहते हैं कि काट दिया। तो चेक काटने में जो आनंद है, उसमें गुरुर भी मिक्स होता है थोड़ा। पैसे तो ATM से निकालकर भी दिए जा सकते हैं या Paytm भी कर सकते हैं, लेकिन जो भाव चेक से आता है, वह किसी और मीडियम से नहीं। कलम में ताकत होती है, और यह ताकत मुद्रा में कैसे बदल सकती है, यह दिखाता है चेक। इस पर लिखने का अहसास शब्दों में बयान करना जरा मुश्किल है। जब खुरदुरे कागज पर कलम चलती है, तो कागज का हर उतार-चढ़ाव निब के जरिये महसूस होता है हाथों को। कागज का रेशा-रेशा स्याही में लिपटता जाता है। जिन्हें लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, उन्हें भी अपना लिखा हुआ अच्छा लगने लगता है चेक पर। इसे काटते समय जिस तरह की एकाग्रता आ जाती है, वह भी कमाल है। हर खाने के पहले दिमाग ठहरता है एक पल। खड़े-खड़े कोट की जेब से ब्लैंक चेक निकाल कर उसे किसी को थमा देने का चमत्कार फिल्मों में ही होता है। असलियत में यह काम होता है आराम से बैठकर करने वाला।

AI Image

जीवन आनंद

पहला चेक याद रह जाता है हमेशा, पहली नौकरी और पहली सैलरी की तरह। इसे काटते हुए अधिकार का भाव आता है, आत्मविश्वास जागता है। कई लोगों के लिए उनकी सफलता का हस्ताक्षर होता है चेक। जैसे किसी को लंबाई नहीं, उसके कद से आंका जाता है, वैसे ही चेक की कीमत उसके आकार नहीं, उस पर लिखे अंकों में है। इतनी ताकत होने के बाद भी यह कभी बहकता नहीं। पाबंद है समय का, वफादार है और किस्मत की तरह मिलता उसी को है जिसका नाम लिखा हो इस पर।

इसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदियां बीत गईं। राजा-महाराजाओं के जमाने में हुंडी चला करती थी अपने देश में। बड़े-बड़े सेठ महाजन कागज पर लेन-देन का हिसाब लिख एक से दूसरी जगह बड़ी रकम पहुंचाया करते थे। अंग्रेज आए तो चेक लाए, हुंडियां तब भी खत्म नहीं हुई थीं। खैर, अंग्रेजों ने फाइनैंशल सिस्टम में चेक लाकर बदलाव किया अपनी सहूलियत के लिए, पर भारत को भी खूब फायदा हुआ। हालांकि जिस वेस्ट ने चेक को सिर आंखों पर बैठाया, वही अब इसका इस्तेमाल घटा रहा है। लेकिन, हम अब भी इसके प्यार में बंधे हुए हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन और मनी ट्रांसफर के दौर में भी अहमियत बनी हुई है इसकी। आखिर चेक काटने में जो मजा है, वह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल का बटन दबाने में कहां!

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesgroup.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

सैकड़ों साल से कायम इनका आतंक

मृत्युंजय राय

आज समुद्री डाकुओं की याद लोगों के मन में इन पर हिंदी-अंग्रेजी में बनी फिल्मों के जरिये रची-बसी है। चाहे वह 2018 में आई भारतीय फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' हो या ऐक्टर जॉनी डेप की 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' सीरीज की हॉलिवुड फिल्में। एक रूमानियत है उन्हें लेकर। ऐसा नहीं है कि लोग सोमालिया के समुद्री डाकुओं की कारगुजारियों और जुल्म से अनजान हैं। या उन्हें यह नहीं पता कि किस तरह से भारतीय नौसेना ने हाल में समुद्री डाकुओं के आतंक से कैसे कुछ जहाजों को बचाया है। फिर भी फिल्मों ने जो छवि समुद्री डाकुओं की बनाई है, वह लोगों के मन से नहीं मिटती।

क्या सच में ये डाकू वैसे ही हैं, जैसा कि इन फिल्मों में दिखाया गया है? **Enemies of All: The Rise and Fall of the Pirates** नाम की किताब में इससे परदा हटाया गया है। इसे लिखा है रिचर्ड ब्लैकमोर ने। उनका मानना है कि 17वीं सदी के आखिर से 18वीं सदी को समुद्री डाकुओं का स्वर्णकाल कहा जाना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि इन डाकुओं को किस तरह से कुछ रियासतों का संरक्षण मिला हुआ था। समुद्री डाकुओं का जबरदस्त उभार तब हुआ, जब यूरोप को लैटिन अमेरिका का पता लगा। स्पेन और पुर्तगाल के जो समुद्री जहाज वहां गए, वे वहां से सोना, चांदी और दास लेकर लौटते थे। समुद्री डाकुओं के लिए ये शानदार शिकार थे।

ये डाकू अक्सर ऐसे द्वीपों पर पनाह लेते, जहां किसी का राज नहीं चलता था। नॉर्थ-साउथ अमेरिका में वे उन किलों और इलाकों पर भी हमला करते, जो नए-नए बसे होते थे। वे जहाज पर यात्रा करने वालों को तब तक टॉर्चर करते, जब तक कि वे यह नहीं बता देते थे कि शिप पर बेशकीमती चीजें कहां रखी हैं। स्पेन और पुर्तगाल के जहाजों पर जो दास उनके हाथ लगते, वे या तो उन्हें बेच देते थे या समंदर में मरने के लिए फेंक देते थे। महिला बंदियों के साथ उनका बर्ताव और भी बुरा होता था।

समुद्री डाकुओं की कहानी में हिंद महासागर भी उस वक्त बड़ा किरदार अदा कर रहा था। ब्लैकमोर हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के एक हमले के बारे में बताते हैं। वह लिखते हैं कि इन डाकुओं ने अपने जहाज पर ब्रिटेन के झंडा लगा रखा था। उन लोगों ने एक ऐसे जहाज पर कब्जा किया, जो मुस्लिम तीर्थयात्रियों को लेकर भारत लौट रहा था। उन्होंने यात्रा करने वालों को भयानक यातनाएं दीं। महिला यात्रियों का बलात्कार किया और इस जहाज की लूट से उनके हाथ करीब 50 लाख रुपये लगे। जो उस वक्त बहुत ही बड़ी रकम थी।

AI Image

विचार विंडो

जब लैटिन अमेरिका से आने वाले जहाजों की लूट फायदेमंद नहीं रही तो ये डाकू दूसरे ठिकाने देखने लगे। फिर वे दूसरे शिपिंग रूट्स को निशाना बनाने लगे। इनमें से कुछ ने औपनिवेशिक शासकों के साथ जुड़ना पसंद किया। ऐसे ही एक डाकू थे, हेनरी मॉर्गन। उन्होंने जमैका के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किया। जब समुद्री डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया, तब यही कोई 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने इन पर लगाम लगाने का संकल्प लिया। इन देशों ने अपने-अपने समुद्री क्षेत्रों में नौसेना भेजी।

भले ही समुद्री डाकुओं का स्वर्णकाल इन देशों ने खत्म कर दिया, लेकिन पाइरेसी आज भी जारी है। ब्लैकमोर बताते हैं कि सोमालिया में आज किस तरह से इस अपराध को पनाह मिली हुई है। जहाज और क्रू को बंधक बनाकर ये अपराधी फिरौती वसूल रहे हैं और आज भी कई देशों की नौसेनाएं इन पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिनमें भारतीय नौसेना भी शामिल है।

माइंड द गैप

प्रणव प्रियदर्शी

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम की ओर से पिछले सप्ताह जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत के लिए कोई खुशी की खबर नहीं ला पाया। इसके मुताबिक, महिला-पुरुष समानता के मोर्चे पर भारत में हालात पिछले साल के मुकाबले और बदतर हुए हैं। 2023 के इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर था। इस बार वह दो स्थान और फिसलकर 146 देशों की सूची में 129वें नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान हमसे भी बुरी हालत में है। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल सरीखे हमारे बाकी पड़ोसी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। बहरहाल, मायूसी में डूबने के बजाय यह देखना मुनासिब होगा कि आखिर यह इंडेक्स है क्या और इसमें ऊपर उठने या नीचे खिसकने का वास्तव में क्या मतलब है?

AI Image

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम ने 2006 से यह इंडेक्स जारी करना शुरू किया। इसमें चार प्रमुख कसौटियों के आधार पर यह देखा जाता है कि कोई देश जेंडर बायस से उबरने में किस हद तक सफल या असफल हो रहा है। हर साल जारी किए जाने वाले इस इंडेक्स की वे चारों कसौटियां हैं– 1. आर्थिक भागीदारी और अवसर 2. शैक्षिक योग्यता 3. स्वास्थ्य और आयु 4. राजनीतिक सशक्तीकरण। जाहिर है, इन चारों कसौटियों से यह अंदाजा मिलता है कि कोई देश या समाज महिलाओं को ताकत देने, उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों को लेकर कितना गंभीर है। भारत की बात करें तो इंडेक्स के मुताबिक यहां इन चारों कसौटियों पर 2024 तक महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर को 64.1% कम किया जा सका है। आर्थिक बराबरी के मामले में भारत सबसे निचली कतार वाले देशों में आता है। राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में उसका स्थान दुनिया में 65वां है। पिछले 50 वर्षों में महिला और पुरुष राष्ट्र प्रमुखों के अनुपात के मामले में यह दसवें नंबर पर आता है। मगर संसद में महिलाओं की नुमाइंदगी बहुत कम है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के मोर्चे पर भी थोड़ी गिरावट आई है। रैंक में गिरावट के पीछे मुख्यतया यही दो कारण हैं।

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

पहले की धारणा छोड़ने पर ही होंगे परमात्मा के दर्शन

आचार्य रूपचंद्र

आज जो भी व्यक्ति सतह से थोड़ा-सा भी ऊपर उठता है, उसका लक्ष्य बदल जाता है। उसके सोचने, बोलने और जीने का तरीका और दायरा भी बदल जाता है। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाना चाहता है। वैसे है तो यह आम बात। लालसा का कोई अंत नहीं है। वह हमेशा उड़ान भरती रहती है। हर तरफ रुतबा कायम हो, यह जीने की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हो गया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान बन जाना चाहते हैं ताकि उनकी जय-जयकार हो। यह सोच धर्मगुरुओं में तो और भी ज्यादा है। स्वयंभू भगवानों की तो कतार बन गई है। सबसे आश्चर्य तो इस बात का है कि इंसान बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है।

पिछले दिनों एक लेखक की कहानी पढ़ी। उसकी शुरुआत गजब थी। उसका एक पात्र कहता है, 'मैं बुद्ध होना चाहता हूं।' मैं थोड़ा हैरान हुआ कि आधुनिक युग में ऐसा भी कोई हो सकता है जो बुद्ध बनने को आतुर हो। बाद में समझ आया कि मनचाहा जीवन नहीं जी पाने के कारण उसके मन में एक विचार आया है। यह अपने अस्तित्व से पलायन का एक संदर्भ है। वह जो है, अब होना नहीं चाहता। जो नहीं हो सकता, वह होने को आतुर है।

यह विषय अध्यात्म और दर्शन का है। भारतीय चिंतन और दर्शन में जीवन के सारे सवालों के जवाब हैं। पर याद रखें कि हमारा दर्शन शरीर की नहीं, आत्मा की बात करता है। आप कहीं भी रहें, आत्मस्थ रहें। यहां शरीर गौण हो जाता है। यहीं आत्मा है और यहीं परमात्मा है। लेकिन मुश्किल है कि हम शास्त्र पढ़-सुनकर भी सच तक नहीं पहुंच पाते।

एक प्रसंग है। स्वामी रामतीर्थ विदेश यात्रा से लौटे थे। टिहरी गढ़वाल के नरेश ने उनसे कहा कि एक सवाल का जवाब चाहिए। 20 वर्षों में अनगिनत संतों-संन्यासियों से वह सवाल पूछ चुके हैं लेकिन कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। सवाल है, 'हजारों वर्षों से लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा-उपासना कर रहे हैं। धर्मस्थान बनवा रहे हैं, फिर भी परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? अब आप कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे परमात्मा के दर्शन हो सकें।' यह सवाल आज भी पूछा जा रहा है। तब स्वामी जी ने संकेत की भाषा में कहा था कि उत्तर स्वयं में ही खोजना होगा। यानी आत्म दर्शन करना होगा। यह यात्रा हमारी है, इस पर चलना खुद को ही है।

आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा वे संस्कार हैं, जिन्हें हम अपने अंतर्मन में जमा कर बैठ जाते हैं। चाहे हमारा किसी भी परंपरा में विश्वास हो, जब तक हम पूर्व धारणाओं से ग्रस्त हैं, तब तक आत्मा और परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। उन्हीं संस्कारों के दर्शन होंगे, जिनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, यानी आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा है। अगर हम बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट के समान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस छवि से मुक्ति लेनी होगी, जिससे उनकी छवि बनी है। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी छवि गढ़नी होगी। लेकिन उसके पहले इंसान होने की पहचान स्थापित करनी होगी।

प्रस्तुति : आनंद भारती

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ स्लम पॉलिसी की ठोस नीति

स्लम पॉलिसी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी वर्षों से चले आ रही इस समस्या और अन्याय की ओर संकेत करती तो है, लेकिन न्यायालय और सरकार केवल सरकारी भूमि के संबंध में ही सोचती है। अधिकतर झोपड़ियां तो रातों-रात प्राइवेट भूमि पर भी बन जाती हैं। प्राइवेट जमीन के मालिक एक लंबी, अंतहीन कानूनी लड़ाई के सिवा कुछ नहीं कर पाते। कहने को यह न्याय की लड़ाई होती है, लेकिन इसके लिए उन्हें जीवन भर अन्याय सहने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए सरकारी हो या प्राइवेट जमीन, अवैध स्लम और इन जमीनों पर जबरन कब्ज़ा करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई अपेक्षित है।

-**चंद्रा देवत (मुंबई)**, ईमेल से

■ स्वागत योग्य फैसला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट को रेग्यूलर मोड में साल में दो बार ऐडमिशन देने की मंजूरी दी है। यह योजना एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू होगी। यह यूजीसी का स्वागत योग्य फैसला है। लाखों स्टूडेंट्स को फायदा होगा, बच्चों का एक साल बचेगा। किसी कारण जून-जुलाई सत्र के दौरान ऐडमिशन नहीं ले पाते, उन्हें जनवरी-फरवरी में अवसर मिलेगा। विदेश में कई यूनिवर्सिटीज में यह सिस्टम पहले से ही लागू है। हमारे देश में यह निर्णय बहुत देर से लिया गया है। यही सिस्टम 10+2 में भी शुरू किया जाना चाहिए।

-**सुभाष बुडावन वाला,** ईमेल से

■ नैतिकता की दुहाई

नव निर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ क्या मारा, उनके पक्षधर नैतिकता, अनुशासन व शांति की दुहाई देने लगे। महिला जवान कुलविंदर कौर की निंदा की जानी चाहिए, उन्होंने गलत किया, लेकिन सवाल यह है कि नैतिकता, अनुशासन और शांति की बातें करने वाले लोग यह तभी कहते हैं, जब उन पर कुछ बीतता है। विरोधियों व परायों पर जब जुल्म, अन्याय, ज्यादती की जाती है, तो नैतिकता, अनुशासन और शांति भूलकर वे अनर्गल तर्क- कुतर्क देने लगते हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या महिला पहलवानों का मामला, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या हाथरस कांड, चाहे मंत्री पुत्र किसानों को कुचल ही क्यों न दे, या फिर मणिपुर हिंसा व महिलाओं को नग्न घुमाए जाने की घटना, बहुत ही बेशर्मी से ये लोग सरकार का पक्ष रखते नजर आते हैं।

-**हेमा हरि उपाध्याय (मुंबई)**, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबर: पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ी!
टिप्पणी: अच्छी बात है, गधे कम से कम काम तो करेंगे।

-**संजय इंदोरिया (मुंबई)**, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जी-7 और भारत

इटली में जी-7 समूह की बैठक ऐसे समय में हुई है, जब रूस-यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तथा गाजा में इस्राइली हमले जारी हैं. ये लड़ाइयां कभी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती हैं. साथ ही, परमाणु युद्ध की आशंका भी लगातार बढ़ रही है. जी-7 समूह के सात देश- अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान- विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं तथा वैश्विक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर उनका दशकों से वर्चस्व रहा है. इस समूह में यूरोपीय संघ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है. बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यह वर्चस्व निरंतर कमजोर हो रहा है. चीन और रूस के बीच निकटता बढ़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते महत्व ने भी जी-7 समूह के समक्ष एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी है. ऐसे में भारत इन देशों तथा ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक सकारात्मक संपर्क के रूप में उभरा है. कुछ वर्षों से समूह के शिखर सम्मेलन में भारत लगातार आमंत्रित होता रहा है. अब तक भारत 11 बार इसमें शामिल हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पांच बार बैठक में शिरकत कर चुके हैं. बदलती दुनिया में अर्थव्यवस्था के अनेक केंद्र उभर रहे हैं, जिनमें भारत भी है. पश्चिम के साथ हमारे जितने अच्छे अच्छे संबंध हैं, वैसे ही संबंध रूस, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के देशों से भी है. अर्थव्यवस्था और प्रभाव के मामले में ब्रिक्स समूह जी-7 समूह से आगे निकल चुका है. भारत इसका संस्थापक सदस्य है. जी-20 की अध्यक्षता पिछले वर्ष भारत के पास थी और अभी ब्राजील इस समूह का अध्यक्ष है. अगले वर्ष यह दायित्व दक्षिण अफ्रीका के पास होगा. ये देश भी ब्रिक्स के सदस्य हैं. भारत की विश्व बंधुत्व पर आधारित स्वायत्त विदेश नीति ने भी उसके अंतरराष्ट्रीय महत्व को बढ़ाया है. विभिन्न राजनेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत निकटता ने भी भारत को विश्व मंच पर स्थापित करने में योगदान दिया है. यही कारण है कि जी-7 समूह भारत से सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार संधि के लिए वार्ता चल रही है. इटली और भारत भी रणनीतिक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं. जी-7 समूह के साथ परस्पर व्यापारिक सहयोग एवं राजनीतिक तालमेल के अलावा अफ्रीका, भूमध्यसागर तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी सहकार की बड़ी संभावनाएं हैं. पश्चिमी देश हों या जापान हो या भारत, सब चीन से बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं, पर ये देश चीन की विस्तारवादी नीति की चुनौती से भी आगाह हैं. चीन अपनी आर्थिक क्षमता का उपयोग अपने भू-राजनीतिक विस्तार के लिए भी कर रहा है. यह आयाम भी भारत के महत्व को बढ़ा देता है क्योंकि पश्चिम समेत अनेक देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावनाओं को देख रहे हैं.

कुछ वर्षों से समूह के शिखर सम्मेलन में भारत लगातार आमंत्रित होता रहा है. अब तक भारत 11 बार इसमें शामिल हो चुका है.

ब्रिटेन चुनाव में हिंदू मांगों का घोषणापत्र

शिवकांत
पूर्व संपादक, बीबीसी हिंदी
shivkant.sharma@gmail.com

ब्रिटेन के हिंदू समुदाय ने भी पहली बार चुनावी वाद-विवाद के इस समर में कूदते हुए 32 पृष्ठों का एक घोषणापत्र जारी किया है. इसमें रखी गयीं सात मांगों में ब्रिटेन में हिंदू विरोधी नफरत या हिंदूफोबिया का संज्ञान लेना और उसकी रोकथाम करना तथा हिंदू मंदिरों की सुरक्षा प्रमुख हैं. यह घोषणापत्र 'हिंदूज फॉर डेमोक्रेसी' नामक संस्था ने जारी किया है, जो ब्रिटेन में सक्रिय स्वामीनारायण संस्था, चिन्मय मिशन और विश्व हिंदू परिषद जैसे 15 हिंदू संगठनों का परिसंघ है.

ब्रिटेन में संसद की 650 सीटों के लिए चार जुलाई मतदान होना है. उम्मीदवार घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 वर्ष की सत्ता विरोधी लहर पर सवार किएर स्टॉमर की लेबर पार्टी के साथ-साथ कंजर्वेटिव पार्टी के ही धुर दक्षिणपंथी खेमे से बनी रिफॉर्म पार्टी का भी सामना करना पड़ रहा है. पार्टियां अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर रही हैं और एक-दूसरी की घोषणाओं की समीक्षा और आलोचना कर रही हैं. ब्रिटेन के हिंदू समुदाय ने भी पहली बार चुनावी वाद-विवाद के इस समर में कूदते हुए 32 पृष्ठों का एक घोषणापत्र जारी किया है. इसमें रखी गयीं सात मांगों में ब्रिटेन में हिंदू विरोधी नफरत या हिंदूफोबिया का संज्ञान लेना और उसकी रोकथाम करना तथा हिंदू मंदिरों की सुरक्षा प्रमुख हैं. यह घोषणापत्र 'हिंदूज फॉर डेमोक्रेसी' नामक संस्था ने जारी किया है, जो ब्रिटेन में सक्रिय स्वामीनारायण संस्था, चिन्मय मिशन और विश्व हिंदू परिषद जैसे 15 हिंदू संगठनों का परिसंघ है.

अभी तक ब्रिटेन का मुस्लिम समुदाय ही घोषणापत्र जारी कर अपनी राजनीतिक मांगे रखता आया है. उसकी मांगों में भी इस्लाम विरोधी नफरत या इस्लामोफोबिया का संज्ञान लेते हुए उसकी रोकथाम का संकल्प और भरोसा जीतने तथा राजनीतिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए इस्लामी समुदाय के साथ सार्थक मेल-मिलाप प्रमुख हैं. ब्रिटेन की लगभग 500 मुस्लिम संस्थाओं और मस्जिदों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश मुस्लिम परिषद की मांग है कि सभी पार्टियां इस्लामोफोबिया की उस परिभाषा को आधार बनाकर रोकथाम की नीतियां बनायें, जो 1917 की सर्वदलीय संसदीय समिति ने सुझायी थी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मोटे तौर पर इस्लामोफोबिया ऐसा नस्लवाद है, जो इस्लामियत या इस्लामियत समझी जाने वाली अभिव्यक्ति को अपना निशाना बनाता है. विपक्ष की लेबर और लिबरल पार्टियों, वेल्स की प्लाइड कुमरी पार्टी, लंदन के महापौर और कई स्थानीय निकायों ने इस पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा होने से पहले ही परिभाषा को स्वीकार कर लिया. इस जल्दबाजी का प्रमुख कारण मुसलमानों की राजनीतिक ताकत है, जो आबादी के साथ-साथ तेजी से बढ़ रही है. साठ के दशक के प्रारंभ में ब्रिटेन की मुस्लिम आबादी लगभग 50 हजार थी, जो अब लगभग 40 लाख हो चुकी है. बरमिंघम के 30 प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं और लंदन में मुस्लिम आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है. ब्रैडफर्ड के एक और बरमिंघम के दो संसदीय क्षेत्रों की आधी या उससे ज्यादा आबादी मुस्लिम हो चुकी है. ब्रिटेन के 24 संसदीय क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है और 80 संसदीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक. यह आबादी मुख्यतः लंदन तथा मध्य और उत्तरी इंग्लैंड के शहरी इलाकों में केंद्रित है, जहां उसके समर्थन के बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है.

कंजर्वेटिव पार्टी और सरकार ने अभी तक सर्वदलीय समिति की इस्लामोफोबिया की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है. सरकार का तर्क है कि यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसकी आड़ लेकर इस्लामी आतंकवादियों, बच्चियों का यौन शोषण करने वाले ग्रूमिंग गिरोहों और समलैंगिकों व औरतों के अधिकारों का विरोध करने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों का बचाव किया जा रहा है. इसे स्वीकार करना पिछले दरवाजे से ईशनिंदा कानून पारित करना होगा, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और सुधारक संस्थाओं का काम कठिन हो जायेगा. यही कारण है कि कंजर्वेटिव सांसद और पूर्व वित्त और गृहमंत्री साजिद जावेद तथा विपक्षी लेबर पार्टी के वरिष्ठतम मुस्लिम सांसद खालिद महमूद समेत लगभग 20 सामाजिक और मानवाधिकार संस्थाओं ने मिलकर सरकार से अपील की थी कि इस्लामोफोबिया की इस परिभाषा को स्वीकार न किया जाए. हिंदू घोषणापत्र में रखी गई हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की रोकथाम की मांग को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए. देश के मुस्लिम समाज को यह चिंता है कि 11 सितंबर, 2001 के हमलों, इराक और सीरिया के युद्धों और हाल में हमास के हमले से शुरू हुई गाजा की लड़ाई के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर इस्लामोफोबिया फैल रहा है. हिंदू समाज को उस हिंदूफोबिया को लेकर चिंता है, जो हिंदू उत्सवों, कारोबारों और मंदिरों पर होने वाले हमलों और स्कूलों में हिंदू बच्चों को तंग करने के रूप में दिखाई देता है. मोदी सरकार बनने के बाद से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह ब्रिटेन में भी ऐसे हमले बढ़े हैं.

हिंदू समाज को मध्य इंग्लैंड के लेस्टर शहर में दो साल पूर्व जिहादी तत्वों द्वारा की गयी मार-पीट और तोड़-फोड़ ने विशेष रूप से चिंतित और सजग किया है. ब्रिटेन में हिंदू आबादी सवा दस लाख है, जिनमें से लगभग आधे लंदन और उसके आसपास रहते हैं. लंदन का हिंदू समुदाय औसत आय की दृष्टि से यहूदियों के बाद सबसे समृद्ध है और सुशिक्षित है. पर संख्या बल में वह मुस्लिम समुदाय के एक चौथाई के बराबर ही है. स्थानीय निकायों और संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में भी वह मुस्लिम समुदाय से पीछे है. भंग हुई संसद में 19 मुस्लिम सांसद थे. हिंदू किसी पार्टी के लिए मुस्लिम समुदाय की तरह एकजुट भी नहीं होते. फिर भी, संख्या बल और अर्थ बल की दृष्टि से हिंदू समुदाय का प्रभाव इतना हो चुका है कि अब उसकी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता. इसीलिए कुछ कंजर्वेटिव सांसदों ने हिंदूफोबिया का संज्ञान लेने और उसकी रोकथाम की मांग को स्वीकार कर लिया है. सर्वेक्षणों के अनुसार लेबर पार्टी की जीत लगभग तय दिखती है और वहां दबदबा इस समय मुस्लिम नेताओं का है. कंजर्वेटिव पार्टी तीसरे स्थान पर रहती दिख रही है.

ब्रिटिश मुस्लिम परिषद में भी इस्लामी कट्टरपंथियों का वर्चस्व है, जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और पूर्वी अफ्रीकी मूल के हैं तथा जमात-ए-इस्लामी जैसी विचारधारा रखते हैं. वे अपने संख्या बल का प्रयोग राजनीति और मीडिया में प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा अपनी विचारधारा व विदेश नीति थोपने में करना चाहते हैं. वे एंटीसेमेटिक या यहूदीफोबिया की परिभाषा से सहमत नहीं होते. पर इस्लामोफोबिया की परिभाषा स्वीकार कराना चाहते हैं. हिंदूफोबिया का संज्ञान लेने और उसकी रोकथाम की मांग से मुस्लिम संगठन सहमत होंगे या नहीं, यह तो बाद की बात है. पहले राष्ट्रीय सेक्युलर सोसायटी, दलित सोलिडैरिटी नेटवर्क, जातिविरोधी संघ और साउथहॉल ब्लैक सिस्टर्स जैसी हिंदू संस्थाएं ही इसके विरोध में हैं. उनका कहना है कि हिंदूफोबिया स्वीकार कर लेने से जातिवाद और नारी शोषण जैसी हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में बाधा होगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

गर्मी के बढ़ते दिन और बढ़ती परेशानियां

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

यह समझना होगा कि मौसम के बदलते मिजाज को जानलेवा हद तक ले जाने वाली हरकतें तो इंसान ने ही की हैं. प्रकृति की किसी भी समस्या का निदान हमारे अतीत के ज्ञान में ही है, कोई भी आधुनिक विज्ञान ऐसी दिक्कतों का हल नहीं खोज सकता. आधुनिक ज्ञान के पास तात्कालिक निदान और कथित सुख के साधन तो हैं, लेकिन कुपित कायनात से जूझने में वह असहाय है.

लोगों के तन से होली के रंग छूटे भी नहीं थे कि पूरा उत्तरी भारत तीखी गर्मी की चपेट में आ गया था. कुछ जगह पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात भी हुई, पर ताप कम नहीं हुआ. देश के लगभग 60 फीसदी हिस्से में अब 35 से 45 डिग्री की गर्मी के कहर के 100 दिन हो गये हैं और चेतावनी है कि अगले दो हफ्ते मौसम ऐसा ही रहेगा. वैसे भी यदि मानसून आ भी गया, तो भले तापमान नीचे आये, लेकिन उमस गर्मी की ही तरह तंग करती रहेगी. चिंता की बात है कि इस बार गर्मी के प्रकोप ने न तो हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों को बख्शा और न ही उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को. गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की तरह तीखी गर्मी की चपेट में आ रहा है. यहां पेड़ों की पत्तियों में नमी के आकलन से पता चलता है कि आगामी दशकों में हरित प्रदेश कहलाने वाला इलाका बुंदेलखंड की तरह सूखे, पलायन व निर्वनीकरण का शिकार हो सकता है. आधा जून बीत गया, पर अभी भी शिमला और मनाली जैसे स्थानों का तापमान 30 के आसपास है. हमीरपुर में 44.5, तो कांगड़ा, चंबा, नाहन,मंडी आदि में पारा 41 से नीचे आने को तैयार नहीं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 122 साल बाद सबसे ज्यादा तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा. मुक्तेश्वर और टिहरी में ऐसी ही स्थिति है.

यह गर्मी अब इंसान के लिए संकट बन रही है. राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इसने हवा की गुणवत्ता को खराब किया है. इसके अलावा लू लगने, चक्कर आने, रक्तचाप अनियमित होने से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं. लगातार गर्मी ने पानी की मांग बढ़ायी है और संकट भी. पानी का तापमान बढ़ना तालाब-नदियों की सेहत खराब कर रहा है. एक तो वाष्पीकरण तेज हो रहा है, दूसरा पानी अधिक गरम होने से जलीय जीव-जंतु और वनस्पति मर रहे हैं. तीखी गर्मी भोजन की पौष्टिकता की भी दुश्मन है. गेंहू, चने के दाने छोटे हो रहे हैं और उनके पौष्टिक गुण घट रहे हैं. तीखी गर्मी में पका हुआ खाना जल्दी सड़ रहा है, फल-सब्जियां जल्दी खराब हो रही हैं. केमिकल लगा कर पकाये गये फल इतने उच्च तापमान में जहर बन रहे हैं. इस बार एक त्रासदी यह है कि रात का तापमान कम नहीं हो रहा, चाहे पहाड़ हो या मैदानी महानगर, बीते दो महीनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक अधिक रहा है. सुबह चार बजे भी लू का एहसास होता है और इसका कुप्रभाव यह है कि बड़ी आबादी की नींद पूरी नहीं हो पा रही. इससे लोगों की कार्य क्षमता पर तो असर हो ही रहा है, शरीर में भी कई विकार बढ़ रहे हैं.

जो लोग सोचते हैं कि वातानुकूलित संयंत्र से वे गर्मी की मार से सुरक्षित है, तो यह भ्रम है. लंबे समय तक एयर कंडीशनर वाले कमरों में रहने से शरीर की नस-नाड़ियों में संकुचन, मधुमेह और जोड़ों के दर्द का खामियाजा जिंदगी भर भोगना पड़ सकता है. इस साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत में एक लाख लोगों का सर्वे कर बताया है कि गर्मी/लू के कारण गरीब परिवारों को अमीरों की तुलना में पांच फीसदी अधिक आर्थिक नुकसान होगा. चूंकि आर्थिक रूप से संपन्न लोग बढ़ते तापमान के अनुरूप अपने कार्य को ढाल लेते हैं, पर गरीब ऐसा नहीं कर पाते. भारत के बड़े हिस्से में दूरस्थ अंचल तक 100 दिन के विस्तार में लगातार बढ़ता तापमान न केवल पर्यावरणीय संकट है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक त्रासदी तथा असमानता और संकट का कारक भी बन रहा है. सवाल यह है कि प्रकृति के इस बदलते रूप के सामने इंसान क्या करे? यह समझना होगा कि मौसम के बदलते मिजाज को जानलेवा हद तक ले जाने वाली हरकतें तो इंसान ने ही की है. प्रकृति की किसी भी समस्या का निदान हमारे अतीत के ज्ञान में ही है, कोई भी आधुनिक विज्ञान ऐसी दिक्कतों का हल नहीं खोज सकता. आधुनिक ज्ञान के पास तात्कालिक निदान और कथित सुख के साधन तो हैं, लेकिन कुपित कायनात से जूझने में वह असहाय है.

अब समय आ गया है कि इंसान बदलते मौसम के अनुकूल अपने कार्य का समय, हालात, भोजन, कपड़े आदि में बदलाव करे. उमस भरी गर्मी और उससे उपजने वाली लू की मार से बचना है, तो अधिक से अधिक पारंपरिक पेड़ों को रोपना जरूरी है. शहर के बीच बहने वाली नदियां, तालाब, जोहड़ आदि यदि निर्मल और अविरल रहेंगे, तो बढ़ी गर्मी को सोखने में ये सक्षम होंगे. खासकर बिसरा चुके कुएं और बावड़ियों को जीवित करने से जलवायु परिवर्तन की इस त्रासदी से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है. आवासीय और व्यावसायिक निर्माण की तकनीकी और सामग्री में बदलाव, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, बहुमंजिला भवनों का इको-फ्रेंडली होना, उर्जा संचयन, शहरों की तरफ पलायन रोकना, ऑर्गेनिक खेती सहित कुछ ऐसे उपाय हैं, जो बहुत कम व्यय में देश को भट्टी बनने से बचा सकते हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

ईयू चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के उभार के मायने

यूरोपीय संघ के चुनावों ने महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित कर दिया है. धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों ने अब स्वयं को राजनीति की मुख्यधारा में स्थापित कर लिया है, यह एक गंभीर परिवर्तन का संकेत है, जो आने वाले वर्षों में यूरोपीय संघ के भविष्य को संभवतः आकार देगा. बीते दशकों में, पारंपरिक पार्टियों ने सत्ता पर पकड़ बनाये रखने के लिए पर्याप्त वोट हासिल किये हैं, पर जिन मुद्दों को लेकर मतदाता चिंतित हैं- प्रवासन, अर्थव्यवस्था या सुरक्षा- उसे नजरअंदाज कर दिया गया है. वर्ष 2019 में पिछले यूरोपीय संसद चुनावों के बाद से, कई धुर दक्षिणपंथी पार्टियों की राजनीतिक दिशा में नाटकीय रूप से बदलाव आया है. नव-नाजियों को शरण देने वाली पार्टी 'द अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी)' ने अब अपने आपको राष्ट्रीय और यूरोपीय राजनीतिक क्षेत्र में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है. यह परिणाम पूरे यूरोप के व्यापक रुझानों को प्रतिबिंबित करता है, जहां धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने पारंपरिक राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ व्यापक मोहभंग का लाभ उठाया है. फ्रांस में, मरीन ली पेन की नेशनल रैली ने भी अपनी बढ़त जारी रखी है. ऑस्ट्रिया और इटली में भी ऐसे ही परिणाम आये हैं. बुल्गारिया में भी दक्षिणपंथी व पुतिन समर्थक रिवाइवल पार्टी पहली बार यूरोपीय संसद में प्रवेश करेगी. परंतु हम यहां कैसे पहुंचे? इन धुर दक्षिणपंथी आंदोलनों में जो समानता है वह है आव्रजन, राष्ट्रीय संप्रभुता और संरक्षणवाद जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सार्वजनिक असंतोष के दोहन की क्षमता. इन चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की उनकी क्षमता वैसे मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होती है जो दशकों के खोखले वादों के कारण अब पारंपरिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते हैं. और इसने ही धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को राजनीतिक रूप से बाहरी लोगों से प्रमुख खिलाड़ियों में बदल दिया है. **-थॉमस ओ फाक**

South China Morning Post

बोधि वृक्ष

पर्याप्त अवसर और समय

हमें बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है. क्योंकि आप जानवर नहीं हैं. जानवर मुख्य रूप से भौतिक संसार से संबंधित होते हैं, जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं. वे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें लगातार बाघ, शेर, भालू, हाथी, सांप, मगरमच्छ और अन्य क्रूर प्राणियों के डर का सामना करना पड़ता है. जबकि जिन जानवरों ने मनुष्यों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक मनुष्य द्वारा वध किये जाने के डर का सामना करना पड़ता है. तो यहां यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव जीवन की तुलना में पशु जीवन कम सुरक्षित है. आज की दुनिया में, मनुष्य को भौतिक दुनिया के साथ वस्तुनिष्ठ समायोजन बनाये रखने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अभी तक एक आदर्श मानव समाज का निर्माण नहीं कर पाये हैं, तो ऐसे में हमें सबसे पहले सभी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. एक बार इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद हम एक आदर्श समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे. समाज को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों को आध्यात्मिक साधना के लिए पर्याप्त अवसर और समय दिया जायेगा. व्यक्तिपरक दृष्टिकोण बी बात करें, तो इसमें पहले अपरिष्कृत मन को धीरे-धीरे बाहरी दुनिया से हटाकर सूक्ष्म मन में विलीन करना है और फिर सूक्ष्म मन को इकाई चेतना में विलीन करना है. जब इकाई चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है, तब कहा जाता है कि मनुष्य ने जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है. वर्तमान समय में विश्व में मनुष्य को अपने वस्तुनिष्ठ समायोजन को बनाये रखने में इतनी जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि वे अपने व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के लिए कोई समय नहीं दे पा रहे हैं. यह आज की सबसे बड़ी त्रासदी है.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

पिघल जायेंगे जी!

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

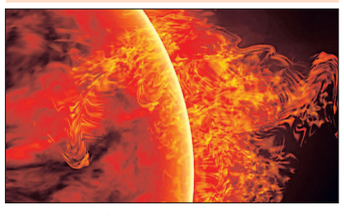

गर्मी पड़ रही है, इससे ज्यादा फालतू बयान कोई नहीं हो सकता. जून में गर्मी न पड़े, सर्दी पड़े, तो खबर बनती है. हालांकि जून हो या दिसंबर, खास खबर तो यही होती है कि फलांजी इधर से निकल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो मार्च में उधर से निकल कर इधर आये थे. गर्मी आकर जाने का नाम नहीं ले रही, पर यह खबर सबसे बड़ी खबर नहीं है. गर्मी बहुत है, पर बहुत ज्यादा टीवी चैनलों को लगती है. टीवी अगर लगातार देख ले, तो बंदा घर से बाहर निकलने से इनकार कर दे. पिघल जायेंगे, अगर घर से बाहर जायेंगे आप-टाइप खबरें चलती हैं टीवी पर. चैनल वाला तो घर से निकल कर चैनल दफ्तर आकर अपना काम रहा है, हमको डरा रहा है कि पिघल जायेंगे. अभी थोड़ी बारिश हो जाए, तो यही चैनलवाला बताने लगता है कि अभी प्रलय आयेगी और बीस मंजिल की इमारत डूब जायेगी. टीवी चैनलों का काम डराने का है. जीवन एकदम शांत लगने लगता है अगर पांच सात दिन टीवी ना देखो तो.

सरकार चल निकली है. पर सवाल भी चल निकला है कि कब तक चलेगी. जो लोग सरकार चलाने-गिराने में कोई रोल ना रखते, वो भी पूछने लगते हैं कि सरकार कब तक चलेगी. एक आलू की ठेली वाला यही पूछ रहा कि सरकार कब तक चलेगी. मैंने कहा- भाई, बीस साल से तेरी आलू की ठेली चल रही है, मस्त रह. सरकार चल जाये, तो भी तेरा आलू का शोरुम ना हो जायेगा. वो अकड़ गया और बोला- हमारी आलू की ठेली किसी भी सरकार से ज्यादा स्थिर है. यह गठबंधन की ठेली नहीं है. पर इस बार गर्मी वाकई बहुत जबरदस्त है, इसका मुझे पता तब लगा, जब कई एनजीओबाज विद्वान क्लाइमेट चेंज विषय पर सेमिनार में यूरोप गये. ऐसे एक एनजीओबाज को मैंने डपटा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी यहां पड़ रही है लद्दूखेड़ा में और तुम लंदन में सेमिनारबाजी मचा रहे हो. यहीं देखो, कैसी समस्या है जमीन पर. पर एनजीओबाज यह सुनने के लिए जमीन पर ना रुका, वह उड़ लिया.

क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार का धंधा चल निकला है. सरकारें सेमिनार कराने के लिए भर भर के ग्रांट देगी. सरकारों की यह अदा भी कमाल होती है. समस्या हल ना हो रही है, पर समस्या पर सेमिनारबाजी कराना कोई समस्या नहीं है. पानी की भीषण समस्या है, लो जी इस विषय पर पांच सेमिनार सुन लो. होशियार एनजीओबाज पहले ही ताड़ लेता है कि किस विषय की सेमिनारबाजी का सीजन है. अभी सीजन क्लाइमेट चेंज का है. पानी की समस्या पर फंड कम मिल रहा है, एक समस्या यह भी है वैसे. तो आइये, क्लाइमेट चेंज पर बहस करें.

आपके पत्र

बढ़ी महंगाई के बीच घटी क्रयशक्ति

आंकड़ों में देश की अर्थव्यवस्था भले ही ठीक दिख रही है, पर जमीन पर हालात कुछ और हैं. देश में महंगाई चरम पर है और लोगों की क्रयशक्ति घट गयी है. बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों की आमदनी घट गयी है. ग्लोबलाइजेशन के कारण बाजारों, मंडियों से लेकर छोटे-छोटे व्यवसाय में पूंजीपतियों की दखलंदाजी बढ़ गयी है. इससे माली हालत खराब हो गयी है. हालांकि, खुदरा महंगाई दर में गिरावट आयी है. इससे उम्मीद जगी थी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और खुदरा मुद्रास्फीति की दर में एक बार फिर बड़ी उछाल आ गयी.

प्रसिद्ध कुमार, बाबूचक (पटना)

बारिश नहीं होने से किसान परेशान

जून महीना आधा बीत गया है, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई है. इससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अभी धान का बिचड़ा डालने का समय है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं है. कुछ किसानों ने पटवन कर खेतों में बिचड़ा डाला है, पर कड़ी धूप के कारण खेत सूख जा रहे हैं. किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाये हुए हैं. यदि इस बार मॉनसून ने साथ नहीं दिया, तो खेती चौपट हो जायेगी. इतना ही नहीं जानवरों के चारे तक की समस्या खड़ी हो जायेगी.

संजय कुमार, मधुबनी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna @prabhatkhabar .in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो . लिपि रोमन भी हो सकती है .

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

मंगल पर यूपी-बिहार

अब मंगल पर भी दो स्थान हैं, जिनका नामकरण उत्तर प्रदेश के शहर मुरसान और बिहार के शहर हिल्सा के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) ने यह नामकरण पहले ही कर लिया था। मंगल पर इन जगहों की खोज-पड़ताल का काम साल 2021 में ही कर लिया गया था। नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) के पास प्रस्ताव पिछले महीने की शुरुआत में भेजा गया था और जिसे अनुमोदन मिल गया है। पीआरएल ने कहा है कि तीन क्रेटर या गड्ढे लाल ग्रह मंगल पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित हैं, जो मंगल के पश्चिमी गोलार्द्ध में भूमध्य रेखा के पास केंद्रित एक विशाल ज्वालामुखी पठार है। खास बात यह है कि यह क्षेत्र सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखियों के घर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे स्थान पर मुरसान और हिल्सा के साथ ही लाल नाम की जगह भी अब चर्चा में रहेगी। लाल नाम पीआरएल के प्रसिद्ध पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। वास्तव में, यह नामकरण वैज्ञानिक देवेंद्र लाल को भी सच्ची श्रद्धांजलि की तरह है।

वैसे यह अभी रोचक सवाल ही है कि मंगल पर मुरसान और हिल्सा नामकरण क्यों किया गया है? यहां यह जान लेना चाहिए कि मुरसान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित है, जबकि हिल्सा बिहार के नालंदा जिले में मौजूद है। अहमदाबाद स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज के मुताबिक, लाल क्रेटर सबसे चौड़ा है, करीब 65 किलोमीटर चौड़ा, जबकि आसपास स्थित मुरसान और हिल्सा दस-दस किलोमीटर चौड़े हैं। मंगल पर मौजूद इन गहरे गड्ढों में कभी पानी हुआ करता था, शायद ज्वालामुखी की वजह से पानी सूख गया, लेकिन वैज्ञानिक मंगल पर पानी की खोज में निरंतर लगे हुए हैं। यह तो अब साबित हो चुका है कि किसी दौर में मंगल पर पानी बहा करता था। मंगल को धरती से देखते हुए या मंगलयान से खींची गई तस्वीरों की मदद से अध्ययन काफी आगे बढ़ चुका है और वैज्ञानिक मंगल के पोर-पोर को खंगालकर अपने-अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ मंजूरी दे रहा है। मंगल के अध्ययन का काम भारत में भी तेजी से हो रहा है और 'लाल', 'मुरसान' और 'हिल्सा' जैसे नाम इसके ताजा प्रमाण हैं।

लाल ग्रह मंगल पर तीन जगहों का नामकरण भारतीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है, ये तीन शब्द हैं लाल, मुरसान और हिल्सा।

इस मुकाम पर अपने मंगलयान को जरूर याद करना चाहिए। दस साल से ज्यादा समय से यह यान अपने काम में जुटा है। साल 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था और अब मंगलयान-2 की तैयारी है। मंगलयान की सफलता अपने आप में एक मिसाल है। मंगलयान अभियान पर फिल्म बन चुकी है। वैसे यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि मंगलयान-2 में अनावश्यक रूप से देरी हुई है। मंगलयान-2 अपने साथ चार उपकरण ले जाएगा। एक उपकरण मंगल ग्रह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा, तो दूसरा उपकरण अंतरग्रहीय धूल की विवेचना करेगा। ऐसे ही एक अन्य उपकरण मंगल ग्रह पर वातावरण और पर्यावरण को खंगालेगा। मंगल से जुड़े अध्ययन में तेजी आनी चाहिए और भारतीय नामकरण से भी तेजी आएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि विज्ञान का प्रचार होता है। विज्ञान के प्रति बच्चों में दिलचस्पी बढ़ती है। इसमें क्या शक है कि उत्तर प्रदेश व बिहार में विज्ञान के और अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है!

पंजाब में पुरानी सियासत के चंद झोंके

पंजाब का पिछले कुछ दशकों का इतिहास यही बताता है कि यहां जब-जब अकाली दल राजनीतिक रूप से कमजोर होता है, तब-तब खाड़कू तत्व ताकतवर होने लगते हैं।

यहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

चर्चाएं कई बार असल तस्वीर को पीछे धकेल देती हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे पंजाब से आए हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है। सारी बातचीत या तो अपने उग्र तेवरों के लिए सुर्खियों में रहे अमृतपाल सिंह तक सिमट गई है, जिन्होंने बतौर निर्दलीय खडूर साहिब से चुनाव जीता है या फिर, फरीदकोट से चुनाव जीतने वाले सरबजीत सिंह खालसा की बात हो रही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं। इन दोनों की जीत से पंजाब की राजनीति में आया दूरगामी असर वाला बड़ा राजनीतिक बदलाव विमर्श से बाहर हो गया है। यहां तक कि इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही, जिसने भले ही पंजाब में एक भी सीट न जीती हो, लेकिन अपने आधार का विस्तार यहां सिर्फ उसी ने किया है।

पहले बात उन चरमपंथियों की करते हैं, जिनको पंजाब की भाषा में 'खाड़कू' कहा जाता है। आज चुनावी जीत को लेकर सरबजीत सिंह खालसा भले चर्चा में हों, लेकिन एक दौर वह था, जब उनकी मां विमल कौर खालसा और उनके दादा सुच्चा सिंह, दोनों ने ही लोकसभा चुनाव जीता था। भारत के लोकतंत्र और इसकी संसद की जो ताकत है, उसकी धारा चंद खाड़कुओं के जीतकर आ जाने से बाधित नहीं होती। यह उस समय भी नहीं हुई थी और अब भी इसकी कोई आशंका नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि पंजाब अचानक ही उस दौर में वापस लौटता दिख रहा है, जब विमल कौर खालसा, सुच्चा सिंह और सिमरनजीत सिंह जैसे लोग आसानी से चुनाव जीत जाते थे।

इस बार पंजाब के चुनाव में एक और बदलाव दिखाई दिया, जिसे बहुत से विश्लेषक खडूर साहिब व फरीदकोट के चुनाव नतीजों से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। हालांकि, हरसिमरत कौर बादल बठिंडा सीट से चुनाव जीतने में सफल रही हैं, लेकिन अकाली दल बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार गिरते-पड़ते हुए भी उसे 25 फीसदी से ज्यादा वोट मिल गए थे। मगर इस बार उसे मिलने वाले वोट 13 फीसदी से कुछ ही ज्यादा हैं। अगर हम बादल परिवार के गढ़ बठिंडा की सीट को अलग करके देखें, तो बाकी पंजाब में तो उसकी हालत और खराब है।

देश की इस दूसरी सबसे पुरानी पार्टी के अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने से जो चिंताएं खड़ी होती हैं, वे बहुत बड़ी हैं। अकाली दल का मूल आधार पंजाब का वह वर्ग है, जिसे पंथक वोटर माना जाता है। मगर इसके साथ ही व्यवहार में अकाली दल कुछ अलग तरह से धर्मनिरपेक्ष और उदारपंथी भी दिखाई देता रहा है। उसके विधायक दल और यहां तक कि मंत्रिमंडल में सिख व हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी जगह पाते रहे हैं। इस बार भी उसके तीन उम्मीदवार हिंदू थे। पंजाब का पिछले कुछ दशकों का इतिहास यही बताता है कि यहां जब-जब अकाली दल राजनीतिक रूप से कमजोर होता है, तब-तब खाड़कू तत्व ताकतवर होने लगते हैं।

याद कीजिए, राजीव-लोंगोवाल समझौते और उसके बाद की राजनीति को। ये अकाली ही थे, जिन्होंने उग्रवाद को जनमानस से खत्म करने में स्थानीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक वैसे ही, जैसे कभी पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के विस्तार पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नकेल कसी थी। मगर अब जो अकाली दल हमारे सामने है, उससे क्या वैसी किसी भूमिका की उम्मीद की जा सकती है? जनता पर उसका प्रभाव तो लगातार कम हो ही रहा है, उसके पास अब लोंगोवाल, तोहड़ा और प्रकाश सिंह बादल जैसे कद्दावर नेता भी नहीं हैं, जिनकी बात तब पूरा पंजाब शिद्दत से सुनता था।

लोकसभा की सात सीटें जीतने के बाद कांग्रेस भले ही पंजाब की सबसे बड़ी विजेता बन गई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले न सिर्फ उसकी एक सीट कम हुई है, बल्कि उसे मिलने वाले मतों का प्रतिशत भी 14 फीसदी गिर गया है। हालांकि, सभी संसदीय सीटों पर चतुष्कोणीय या पंचकोणीय मुकाबला होने के कारण वह 26 फीसदी वोट पाकर पहले नंबर पर है। आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस पंजाब की राजनीति में अकाली दल के खिलाफ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही है। अकाली दल के कमजोर होने के बाद उसके मजबूत होने की जो उम्मीद बांधी जा सकती थी, वह उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है। माना जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी ने अकाली दल के आधार में सेंध लगाई है, तो भाजपा ने कांग्रेस के मतदाता वर्ग को अपनी ओर खींचा है।

भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी से नेताओं का आयात किया, लेकिन उसने पंजाब में राजनीति करने का अपना पुराना मुहावरा इस बार पूरी तरह बदल दिया। पंजाब में पार्टी के 13 में से सिर्फ दो उम्मीदवार उसके पुराने परंपरागत नेता थे, बाकी सभी आयातित थे। उसने पंजाब के स्थानीय समीकरणों के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की और बड़ी संख्या में वोट भी हासिल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल करके उसने अकाली दल को बहुत पीछे छोड़ दिया।

पिछले आम चुनाव तक कहा जाता था कि मोदी का जादू भले ही पूरे देश में फैला, लेकिन उसने पंजाब के शंभू बॉर्डर को कभी पार नहीं किया। शंभू बॉर्डर अंबाला के आगे की वह सीमा है, जहां से पंजाब शुरू होता है। इस बार जब बाकी भारत में यह जादू कुछ हद तक उतार के लक्षण दिखा रहा है, तो पंजाब में उसने हल्का-फुल्का ही सही, असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि, चुनाव नतीजे यह भी बताते हैं कि पंजाब के शहरी क्षेत्रों में भाजपा ने जैसी पैठ बनाई है, वैसी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनी है।

पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को भले ही इस बार पहले जैसा समर्थन नहीं मिला, फिर भी वह दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। पंजाब की राजनीति में यह सबसे नई खिलाड़ी है और पंजाब जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें इस पार्टी की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं की अग्नि-परीक्षा अभी बाकी है। वह भी तब, जब पंजाब फिर से उसी दौर में पहुंचता दिख रहा है, जब इस राज्य का घटनाक्रम देश ही नहीं, पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
17 जून, 1949

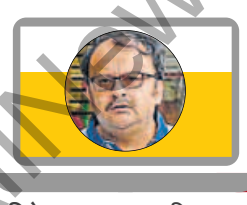

बर्मा का भविष्य

जब चीन इतना बड़ा देश गृह-युद्ध में न ठहर सका और आज वहां जमी हुई सत्ता समाप्तप्राय होकर विद्रोही कम्यूनिस्टों का प्राधान्य है, तब छोटे से देश बर्मा की जमी हुई सत्ता गृह-युद्ध का संकट पार कर जायेगी, यह दुविधा ही है। ऐसी हालत में बर्मा पार्लमेंट में प्रधानमंत्री की यह घोषणा सुखद ही मानी जायेगी कि वहां ''पासा पलट गया है और फरवरी, मार्च व अप्रैल का संकट फिर से पैदा होने की कोई संभावना नहीं है।'' यह बात नहीं कि गृह-युद्ध वहां बंद हो गया है, करेन (विद्रोहियों का) रेडियो ने बा यूगाई के नेतृत्व में विद्रोही मंत्रिमंडल के निर्माण की घोषणा भी की है, फिर भी सरकार जब विद्रोह के बावजूद अपना अस्तित्व एवं अपनी सत्ता कायम रख सकती है तो मानना चाहिए कि विद्रोहियों का जोर अपेक्षाकृत कम पड़ गया है और सरकारी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

क्या यह बर्मा सरकार ने अपने ही बूते किया है और क्या भविष्य में भी वह विद्रोह को दबाये रख सकेगी? यह प्रश्न है, जो उठे बिना नहीं रहता; लेकिन प्रधानमंत्री थाकिन नू का उपर्युक्त भाषण ही जाहिर करता है कि ऐसा तभी संभव हुआ, जब भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन ने बर्मी संकट के समय लोकतंत्र की रक्षा और देश में शीघ्रतापूर्वक शांति की पुनःस्थापना के लिए बर्मी सरकार की नैतिक एवं भौतिक सहायता की। बर्मी संकट के समय जो यह संभावना उत्पन्न हुई थी कि बर्मा को राष्ट्रमंडल के साथ रहने का फिर से निर्णय करना पड़ेगा, उसका बर्मा सरकार ने प्रतिवाद किया था; किंतु राष्ट्रमंडल के देशों से ही बर्मा को 'नैतिक एवं भौतिक' सहायता मिली, यह बात क्या इस धारणा को जन्म नहीं देती कि विधिवत राष्ट्रमंडल के साथ न रहते हुए भी बर्मा किसी न किसी रूप में उसके साथ सहयोग-संपर्क कायम कर रहा है? श्री थाकिन नू की इस घोषणा से इस बात की और पुष्टि होती है कि उनकी सरकार समान हित वाले देशों के साथ ऐसी रक्षात्मक एवं आर्थिक संधियां करने पर विचार कर रही है जो दोनों के लिए समान रूप से हितकर हों। वह कहते हैं, ''यद्यपि हमारी आजादी को एक साल से अधिक हो गया, तथापि अन्य देशों के साथ हमारी कोई ऐसी आर्थिक या रक्षा-संबंधी संबंध नहीं है जिससे आवश्यकता के समय हम लाभ उठा सकें। अनिश्चित काल तक हम इस तरह नहीं रह सकते, यह स्पष्ट है।'' संकट ने बर्मी सरकार को यह अनुभूति करा दी, यह इस बात का प्रमाण है कि बुराई में भी कोई न कोई अच्छाई छिपी रहती है।

आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू से फिर सबको बड़ी उम्मीदें

यहां स्कैन करें

विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

एन चंद्रबाबू नायडू जब बुधवार को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब राजधानी के अशोक रोड स्थित आंध्र भवन के कुछ पुराने मुलाजिम उस दिन को याद कर रहे थे, जब वह पहली बार अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यह बात 1995 की है। अपने ससुर एनटी रामाराव को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ करके नायडू ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। तब उनकी छवि बहुत उजली नहीं थी। हालांकि, वक्त गुजरने के साथ नायडू ने साबित किया कि वह एक उद्योग और प्रौद्योगिकी-समर्थक मुख्यमंत्री हैं।

बेशक, उनकी कोशिशों से जायकेदार बिरयानी और चारमीनार के लिए मशहूर हैदराबाद भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित हुआ। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मिले। उस मुलाकात के बाद हैदराबाद की किस्मत खुल गई थी। दुनिया भर की चोटी की आईटी कंपनियों ने वहां अरबों रुपयों का निवेश किया। एक इंटरव्यू में नायडू ने बिल गेट्स से हुई मुलाकात की जानकारी दी थी। बिल गेट्स किसी काम के लिए राजधानी में थे। संयोग से नायडू भी तब राजधानी में थे। आंध्र के मुख्यमंत्री की तरफ से अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से गुजारिश की गई कि उनकी बिल गेट्स से मुलाकात कराई जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि बिल गेट्स बहुत व्यस्त हैं और अगर वह उनसे मिलने को इच्छुक हैं, तो शाम को अमेरिकी दूतावास के रूजवेल्ट हाउस में आयोजित पार्टी में शामिल हो जाएं। नायडू को दूतावास का न्योता मिला और वह तय समय पर पहुंच गए। उसी पहली मुलाकात में नायडू ने लैपटॉप पर गेट्स को प्रेजेंटेशन दिया। ऐसा प्रेजेंटेशन देने वाले नायडू देश में पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिल गेट्स को समझाया कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए हैदराबाद में निवेश करना लाभ का सौदा रहेगा। उनकी बातों से बिल गेट्स काफी प्रभावित हुए और साल 1998 में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट सेंटर (माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर) स्थापित हुआ। उसके बाद तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में दर्जनों आईटी कंपनियों ने तगड़ा निवेश किया।

अब चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में जा चुका है, तो यकीनन नायडू हरचंद कोशिश करेंगे कि अपनी नई राजधानी में एक नया आईटी हब बनाएं।

चंद्रबाबू नायडू के मन में बिल गेट्स के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव है। क्या इसे संयोग माना जाए कि पिछले बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ विजयवाड़ा के आईटी पार्क में आयोजित समारोह में ली? बतौर मुख्यमंत्री नायडू जब भी दिल्ली या मुंबई जाते हैं, तो वह देश के बड़े उद्योगपतियों से अवश्य मिलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वे उनके प्रदेश में निवेश करें। अब चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में जा चुका है, तो यकीनन वह हरचंद कोशिश करेंगे कि अपनी नई राजधानी में एक नया आईटी हब बनाएं।

मौजूदा दौर की यह बड़ी सच्चाई है कि कोई भी राज्य निजी क्षेत्र के बड़े निवेश के बिना तेजी से चौतरफा विकास नहीं कर सकता। आपको अपने राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने ही होंगे, ताकि निजी निवेशकों का भरोसा जीता जा सके और वे बिना किसी संकोच के आ सकें। यह अपने आप में सुखद है कि अब अधिकतर राज्य अपने यहां निवेश लाने की पहल कर रहे हैं और इनमें इसे लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा भी है। जाहिर है, जो राज्य बेहतर कानून-व्यवस्था और औद्योगिक माहौल की दिशा में ठोस कदम उठाएगा, उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और घरेलू निवेशकों का समर्थन हासिल होगा।

चंद्रबाबू नायडू अपनी बात मनवाने में कुशल हैं। उन्हें आप तर्कों से नहीं हरा सकते। हां, विनम्रता से जरूर अपने पक्ष में कर सकते हैं। विराट बहुमत के साथ चौथी बार का शपथ ग्रहण उनके राजनीतिक कद का परिचायक है। एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनकी भूमिका सबके सामने है। अब जब केंद्र की नई सरकार में उनकी भूमिका 'किंग मेकर' की है, तो यकीनन वह आंध्र के लिए अधिकतम लाभ उठाना चाहेंगे। मगर उनके आगे चुनौती भी कम नहीं है। उन्होंने राज्य की जनता से जो वायदे किए हैं, उसके लिए काफी संसाधन चाहिए। नायडू के चौथे कार्यकाल पर आंध्र ही नहीं, समूचे देश की नजर रहेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ईद उल-अजहा और त्याग

इस्लामी साल में दो ईदें मनाई जाती हैं, ईद उल-अजहा और ईद-उल-फितर। वैसे तो हर पर्व, त्योहार से जीवन की सुखद यादें जुड़ी होती हैं, पर ईद उल-अजहा से इस्लाम धर्म के मानने वालों का खास रिश्ता है। इस्लाम का मतलब होता है ईश्वर में पूर्ण आस्था तथा ईश्वर के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण। हर मुसलमान को इस्लाम धर्म के पांच बुनियादी अरकानों को पूरा करना होता है, जिनमें हज आखिरी अरकान है। मुसलमानों के लिए अपने जीवन काल में एक बार हज करना जरूरी होता है, अगर उसके पास हज पर जाने के लिए पर्याप्त धन है। हज पूरा होने पर ईद उल-अजहा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे कुर्बानी, त्याग या बलिदान का त्योहार भी कहते हैं। इस्लाम में बलिदान या त्याग से तात्पर्य यह है कि इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च करे, मतलब नेकी और भलाई के कामों में खर्च करे। परस्पर प्रेम, सहयोग और गरीबों की सेवा करने का आनंद इस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है।

यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों ही धर्म में अल्लाह के प्रति पैगंबर हजरत इब्राहीम के त्याग और बलिदान को आज भी परंपरागत रूप से याद किया जाता है। यह त्योहार इंसान के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाता है। ईद उल-अजहा में गरीबों और यतीमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि समाज के अंदर कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसी मकसद से ईद उल-अजहा के सामान यानी कुर्बानी के सामान के तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने गरीब रिश्तेदार के लिए तथा तीसरा हिस्सा समाज में जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है, ताकि लोग भी समाज में बराबरी के एहसास के साथ अच्छा खाना खा सकें और अच्छे कपड़े पहन सकें। पूरे विश्व में लोग इस दिन मिलजुल कर खाना-पीना करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं तथा हर इंसान अपनी किसी बुरी आदत का त्याग करने का प्रण करता है।

इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब के कथनानुसार, इस्लाम के मानने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने देश, समाज और परिवार की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहे। इसका मतलब यह है कि इस्लाम व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समाज तथा अपने देश के प्रति दायित्वों को पूरी तरह निभाने पर जोर देता है। त्याग और सहयोग के बिना समाज न तो खड़ा होता है और न मजबूत होता है। यह सिर्फ बाहरी व्यवहार वाला पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से लोगों को प्रेरित करने और भलाई के लिए जगाने वाला पर्व है। यह मजहब विशेष का ही नहीं, हर इंसान का पर्व है, क्योंकि यह सबको संदेश देता है।

इस दिन यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों ही धर्म में अल्लाह के प्रति पैगंबर हजरत इब्राहीम के त्याग और बलिदान को भी याद किया जाता है। यह ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाता है।

प्रोफेसर एम जे वारसी

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

पूर्व सैनिकों, अभिभावकों और नौजवानों के कारण मैं अमेरिका के भविष्य के प्रति पूर्ण आशावादी हूं। उन्होंने अपने देश से बंदूक हिंसा पर बेहतर कदम उठाने की मांग की है। मैं उन्हें सुन रहा हूं और उनके साथ हूं।

अनुलोम-विलोम
ईवीएम

निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरी ईवीएम

चुनाव आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर कोई भी दल ईवीएम की शिकायत करने नहीं पहुंचा। इससे यही साबित होता है कि ईवीएम बेदाग है। जब ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे और चुनाव आयोग की भूमिका कठघरे में थी, तब कुछ संशय जरूर पैदा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया और रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले, वह प्रशंसनीय है। यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों का किस कदर विश्वास है। हमारे लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि इसने समय-समय पर खुद को साबित किया है। लिहाजा, हमारे नेताओं और प्रशासन को चाहिए कि वे पारदर्शिता और निष्पक्षता को हरसंभव प्राथमिकता दें। अंधेरे में रखकर उजाला ढूंढ़ना व्यर्थ है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव-प्रक्रिया इतनी पारदर्शी रहे कि उस पर किसी प्रकार का कोई संशय पैदा न हो। लोकतंत्र की नींव भी तभी मजबूत रह सकती है, जब हम मिलकर इसके सिद्धांतों का पालन करें और इसे सशक्त बनाए रखें। अपने मताधिकार का सही उपयोग और सही उम्मीदवारों का चयन हमारे लोकतंत्र की असली जीत है।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

मतपत्र से बेहतर

ईवीएम से धांधली तभी हो सकती है, जब मतदान कराने वाली सरकारी टीम धांधली पर उतर आए। इंसान के चरित्र की गारंटी नहीं ली जा सकती, मशीन की ली जा सकती है। अच्छी बात यह है कि बाहरी धांधली रोकने के मामले में ईवीएम मतपत्र से बेहतर है। याद रखें कि मनुष्य-जनित धांधली की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि कोई ईवीएम मैलफंक्शन नहीं कर सकती या खराब नहीं होती। मुझे ऐसी कोई मशीन पता नहीं है, जो खराब नहीं होती। मगर भारत में अपवाद को सामान्य नियम बताने वालों की फौज खड़ी हो चुकी है। दो-चार मशीन खराब हैं, तो सारी की सारी खराब हैं! औसतन 100 में 10 मशीन खराब निकले, तो यह चिंता की बात तो है, पर उनके निर्माण में सुधार की जरूरत है। मशीन का खराब निकलना उत्पादन की समस्या है, न कि तकनीक की। एपल के उत्पाद इसलिए खराब नहीं निकलते कि उसकी तकनीक में समस्या है, बल्कि कुछ उत्पादों का उत्पादन मानकों के अनुरूप नहीं हो पाता। याद रखें, ईश्वर के बनाए इंसान में भी खामियां हैं, तो फिर उस इंसान की बनाई कोई चीज शत-प्रतिशत दुरुस्त कैसे हो सकती है? लिहाजा सवाल यह होना चाहिए कि कौन गुणवत्ता में बेहतर है? मेरी राय में ईवीएम बेहतर है। सब कुछ सही रहा, तो भारत इसका निर्यातक देश भी बन सकता है।

रंगनाथ सिंह, टिप्पणीकार

कोई भी मशीन सौ फीसदी सुरक्षित नहीं

ईवीएम में धांधली का मतलब सौ प्रतिशत मशीनों में धांधली नहीं है। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक कहावत है कि सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का सबसे कमजोर पक्ष इंसान होता है। ईवीएम भले ही हैक न हो सकती हो, लेकिन उसके हैंडलर, यानी उसका इस्तेमाल करने वाले जरूर हैक हो सकते हैं। यह समझने की जरूरत है कि वोट में गड़बड़ी बहुत तरह से की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, फेक मशीन, सॉफ्टवेयर का हैक होना, लोगों को मिला लेना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना, आचार संहिता का उल्लंघन, मीडिया का दुरुपयोग, वोटर लिस्ट से नाम गायब, वोट देने से रोकना आदि। वैसे भी, किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए सारी ईवीएम हैक करने की जरूरत होती भी नहीं। बस कुछ महत्वपूर्ण मतदान-केंद्रों या इलाकों में धांधली की जरूरत होती है। और, यह काम करना बहुत कठिन नहीं है। अगर ईवीएम हैक नहीं हो पा रही, तो उनको गायब जरूर किया जा सकता है। उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है! एक मतदान-केंद्र पर सारे मतदान-कर्मी आपस में मिले हो सकते हैं और भ्रष्टाचार कर सकते हैं! कोई भी सॉफ्टवेयर या मशीन की सुरक्षा उसके कोड या हार्डवेयर से ज्यादा उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। ईवीएम को इस मामले में अपवाद नहीं मान सकते। यहां भी मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है।

जसवंत, टिप्पणीकार

शंका निर्मूल नहीं

ईवीएम पर शंका बिना वजह नहीं है। राजनेताओं से यदि मित्रता में पूछिए, तो वे आपको बताएंगे कि किसी न किसी मोड़ पर उनसे कोई न कोई ऐसा मिला होगा, जिसने कहा होगा कि वह ईवीएम में जोड़-तोड़ करके उन्हें चुनाव जितवा सकता है। इस घोटाले की दर होती है ढाई-तीन करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक। इसका मतलब तो यही है कि ऐसा कुछ होता है। तो, सवाल यह है कि कोई चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं आता? इस बार भी आयोग खाली हाथ क्यों रहा? उसके पास कोई शिकायत क्यों नहीं आई? इन सवालों के जवाब आसान हैं। अब आप बताइए कि आपके पास यदि सोने का अंडा देने वाली मुरगी हो, तो आप उसको मार खाएंगे या अच्छी तरह पाल-पोसकर रखेंगे, ताकि वह नियमित रूप से अंडा देती रहे? उम्मीद है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। वैसे, आपको इंटरनेट पर यह खबर भी कई जगह मिल जाएगी कि हैदराबाद के जिस सज्जन ने ईवीएम को हैक करके दिखाया, उन पर सबसे पहले ईवीएम चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था।

विनोद वर्मा, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 17 जून, 2024

दैनिक जागरण

कर्तव्य का बोध जीवन को सार्थकता प्रदान करता है

जम्मू में आतंक की चुनौती

जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक में वहां के हालात की समीक्षा करते हुए आतंक को कुचलने के जो निर्देश दिए, उन पर इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए कि आतंकियों को सिर उठाने और छिपाने का मौका न मिले। इस बैठक में गृह मंत्री ने जिस तरह यह कहा कि जैसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण पाया गया है, वैसे ही जम्मू संभाग में भी पाया जाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि जम्मू की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। यह हाल की घटनाओं से स्पष्ट भी होता है। जम्मू संभाग के रियासी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की एक बस को आतंकियों ने ठीक उस दिन निशाना बनाया जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगियों के साथ शपथ ले रहे थे। यह आतंकी हमला एक तरह से तीसरी बार सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार को दी जाने वाली सीधी चुनौती ही था। इस हमले के बाद आतंकियों ने जिस प्रकार एक के बाद एक डोडा, कठुआ आदि इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, उससे उनके दुस्साहस का ही पता चलता है।

एक लंबे समय से यह प्रकट हो रहा है कि आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू को अपने निशाने पर ले लिया है। जम्मू संभाग के वे इलाके आतंकियों के गढ़ बन गए हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इन इलाकों में आतंकियों की बढ़ी हुई गतिविधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में जुट गया है। इसकी पुष्टि पिछले दिनों कठुआ में मारे गए दो पाकिस्तानी आतंकियों से भी होती है। उनके पास से बरामद हथियार और सामग्री से यह स्पष्ट हुआ कि वे पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू में आए थे। अच्छा होता कि इन आतंकियों के नाम-पते और उनके पास से बरामद पाकिस्तानी सामग्री को देखते हुए भारत सरकार पाकिस्तान से जवाब तलब करती और प्रमाणों के साथ उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बेनकाब करती। निःसंदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ी जाए, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान को नए सिरे से यह बताया जाए कि उसे भारतीय भूभाग में आतंक फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता तो यह लगभग तय है कि वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को कुचलने के लिए कोई कसर इसलिए शेष नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का समय करीब आ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ पुराने तौर-तरीकों के बजाय नए उपाय करने की आवश्यकता रेखांकित की। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जैसे दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, उससे निपटने के लिए नए और कारगर उपाय किए जाने जरूरी हैं।

जनता की परेशानी

पंजाब में भीषण गर्मी के बीच बिजली के लंबे कट से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। धान की रोपाई शुरू होने के साथ ही बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में जब रोपाई जोर पकड़ेगी तब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में पावरकाम के लिए मांग के अनुसार आपूर्ति कर पाना आसान नहीं होगा। लुधियाना जैसे शहर में तो कुछ क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिजली कट रहा। पेयजल की सप्लाई न होने से जनता का बुरा हाल है। लुधियाना में तो कुछ फाल्ट की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो वहां भी कट लग रहे हैं। शनिवार को बिजली की मांग 15,424 मेगावाट रही, जबकि पिछले वर्ष धान की रोपाई के सीजन में अधिकतम मांग 15,300 मेगावाट रही थी। इस वर्ष जो स्थिति है उसके अनुसार सोलह हजार मेगावाट के ऊपर मांग पहुंच सकती है। पावरकाम को अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था के बारे में पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि बिजली न मिलने पर सरकार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। गत वर्षों में रोपाई के सीजन में बिजली न मिलने पर किसानों की ओर से सड़क जाम करने जैसे कदम उठाए जा चुके हैं। शहरी उपभोक्ताओं की नाराजगी भी बढ़ सकती है। सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करने या अवधि कम करने से बिजली की मांग में यदि कमी हो सकती है तो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। मांग बढ़ने का एक कारण मुफ्त में हर माह तीन सौ यूनिट बिजली देना भी है। लोगों को भी बिजली की बचत के बारे में सोचना चाहिए।

बिजली सप्लाई सुचारु करने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जब धान की रोपाई जोर पकड़ेगी तब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग और बढ़ेगी

एक आवश्यक राजनीतिक सुधार

हृदयनारायण दीक्षित

सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है और यह कई समस्याओं का समाधान साबित होगा

अवधेश राजपूत

हम भारत के लोग अक्सर चुनावी तनाव में रहते हैं। लोकसभा चुनाव अभी-अभी संपन्न हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद दिल्ली एवं बिहार आदि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। नगरीय क्षेत्रों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। लगातार चुनावी व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधक है। चुनावों के दौरान प्रशासनिक तंत्र की अलग व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी आचार संहिता के दौरान विकास कार्य भी रुक जाते हैं। अलग-अलग चुनावों में अरबों रुपये का व्यय होता है। इसलिए सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 'एक देश-एक चुनाव' का विचार व्यक्त किया था। इस संबंध में मंथन के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति भी बनी थी। समिति ने 47 राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त किए। 32 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। समिति ने 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मार्च में प्रस्तुत की थी। समिति ने चार पूर्व मुख्य न्यायधीशों, उच्च न्यायालय के 12 मुख्य न्यायधीशों, चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और आठ राज्य चुनाव आयुक्तों जैसे विशेषज्ञों से परामर्श मांगे थे। नागरिकों से 21,558 सुझाव प्राप्त हुए। विधि आयोग ने 2018 में एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब समिति ने इस प्रसंग से जुड़े सभी मसलों पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नई सरकार में कमान संभालते ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए हैं।

कोविंद समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उसने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए संविधान में संशोधनों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। एक साथ चुनाव के लिए नियत तारीख निर्दिष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-82 में संशोधन का सुझाव दिया है। एक साथ चुनाव के लिए 'नियत तारीख' के बाद जहां राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए संसद के साथ समन्वय कर लेंगे। समिति के अनुसार सब कुछ योजनाबद्ध होता है तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव 2029 में हो सकता है। यदि 2034 के चुनावों को लक्षित किया जाता है तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद नियत तारीख की पहचान होगी। तब जिन राज्यों में जून 2024 और मई 2029 के मध्य चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल 18वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद या राज्य विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव के अगले चक्र तक शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति का तर्क है कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव एक साथ चुनाव की समग्र समय सीमा को प्रभावित नहीं करता।

संसदीय चुनावों के साथ नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव का समन्वय जरूरी है। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय पंचायती क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी अंतर होते हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन कानून बनाने का परामर्श दिया है। यह कानून स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनाव समय सीमा के साथ जोड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से सभी स्तरों पर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने में सक्षम बनाएगा। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर है और स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। समिति ने दोनों की एक ही मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव दिया है।

सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है। भारत में राजनीतिक सुधारों विशेषतः चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। यह एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे संघवाद को क्षति होगी। यह कहना गलत है। सभी राज्य एक साथ-एक चुनाव में राज्यों एवं केंद्र के मुद्दे एक साथ उठाएंगे। इससे राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से जुड़ेंगे। क्षेत्रीय दलों की दृष्टि अखिल भारतीय होगी। एक साथ चुनाव के विरोधी अनावश्यक रूप से घबराए हुए हैं। साथ-साथ चुनाव से आम जनों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। वे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी देखेंगे। क्षेत्रीय दल स्थानीयता से ऊपर उठेंगे। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ने की भी भरी-पूरी संभावना है। एक साथ चुनाव से नुकसान की बात करने वाले भूल जाते हैं कि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव का सिलसिला कायम रहा।

कुछ दल कोविंद समिति की रपट को खारिज करने पर तुले हैं। कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करने से संविधान की बुनियादी संरचना में बदलाव होंगे। यह संघवाद के खिलाफ है। कांग्रेस यह न भूले कि भारतीय संघ अमेरिकी संघवाद नहीं है। यहां राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। संविधान सबको बांधकर रखता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए आशंका जताई कि इससे राज्य के मुद्दों को दबाया जा सकता है। द्रमुक की दलील है कि इसके लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता होगी। सपा ने कहा कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभावी होंगे। इनसे इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि एक साथ चुनाव का विचार संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। भाजपा, एनपीपी, अन्नाद्रमुक, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल (सोनेलाल), असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव का समर्थन कर रहे हैं। याद रहे कि कोई भी देश लगातार चुनावी मोड में नहीं रह सकता। चुनावी आरोप-प्रत्यारोप सामाजिक चेतना और तानेबाने को आहत करते हैं। एक साथ चुनाव असल में कई समस्याओं का समाधान है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

विकास पर हावी जाति की राजनीति

डा. सुशील पांडेय

नतीजे बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रवाद के साथ जाति चुनाव जीतने के लिए जरूरी है

कांग्रेस ने छेड़ा जातिगत जनगणना का राग। फाइल

इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के घोषणा पत्र और चुनावी मुद्दों के केंद्र में जाति आधारित राजनीति ही हावी रही। देखा गया कि चुनाव के पूर्व सभी राजनीतिक दलों ने अलग-अलग क्षेत्रों में जातीय संरचना को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई। देश के कई हिस्सों में जातीय संगठनों ने भी अलग-अलग राजनीतिक दलों को समर्थन देने की घोषणा की। कई जातीय संगठनों ने तो अपने जातिगत हितों के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य किया और अपनी जातीय चेतना को प्रभावी बनाने के लिए जातीय आधार पर अनेक बैठकों का आयोजन भी किया। भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवैधानिक और तार्किक रूप से जाति व्यवस्था अप्रासंगिक होने के बाद भी राजनीति में कैसे प्रभावशाली हो गई है।

इतिहास पर नजर डालें तो भारत की जटिल सामाजिक संरचना में जाति महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका में रही है। प्राचीन और मध्यकालीन समाज में तो जाति व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण का आधार थी। देश में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होने के बाद से जाति व्यवस्था नए स्वरूप में सामने आई। राजनीतिक ढांचा बदल जाने और नई न्यायिक और आर्थिक व्यवस्था ने जाति के आधार को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही सामाजिक आंदोलनों ने जाति के वैचारिक पक्ष को कमजोर कर दिया। आजादी के लिए आरंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ, जिससे जाति पर आधारित सभी प्रकार की विसंगतियां समाप्त हो गईं। गांधीजी और डा. आंबेडकर के जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के बाद भी दोनों जननेता जातिगत असमानताओं को अस्वीकार करते थे और लोकतंत्र को जाति उन्मूलन का सशक्त आधार मानते थे। संविधान सभा के सदस्य भी जाति व्यवस्था तोड़कर समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के पक्षधर थे।

स्वतंत्रता के बाद जब देश ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया तो संख्या बल की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अलग-अलग जातियों ने इसे अपने लिए बड़े अवसर के रूप में देखा। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का स्थानीय स्वरूप था और जातियां अपने व्यवसाय के आधार पर संगठित थीं, लेकिन आजादी के बाद जातियों ने वर्ग के रूप में स्वयं को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। एक समान व्यवसाय वाली जातियां पहले क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय आधार पर स्वयं को संगठित करने लगीं। जातियों के अखिल भारतीय संगठन बनने लगे। उत्तर भारत में प्रारंभ में सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियों का वर्चस्व रहा, लेकिन हरित क्रांति के प्रभाव के कारण जाट, यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसी जातियां धीरे-धीरे राजनीति में प्रभावी हो गईं। वहीं, दक्षिण भारत की राजनीति में कर्नाटक में लिंगायत, वोक्कालिगा, आंध्र प्रदेश में कापू, रेड्डी, कम्मा, तमिलनाडु में वेलालर, थेवर, वान्नियर, नाडर, महाराष्ट्र में मराठा, धनगर, माली, महार, राजस्थान में जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर जैसी जातियां राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं।

भारत में जाति व्यवस्था अपने सदस्यों के लिए कल्याणकारी राज्य जैसी भूमिका निभाती है जैसे अपने सदस्यों के लिए जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों, धर्मशालाओं, धार्मिक संस्थाओं और सामूहिक विवाह, भोज समारोह का आयोजन करना। इन सभी कारणों से जातीय एकजुटता आती है। ऐसी स्थिति में जातियां मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित होने लगती हैं और अन्य जातियों के प्रति आक्रामक और विरोधी भाव रखने लगती हैं। प्रत्येक जाति संगठन स्वयं को किसी महापुरुष अथवा धार्मिक व्यक्तित्व से जोड़ता है और उन्हें महिमामंडित करते हुए जाति एकजुटता को सशक्त बनाता है। संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण भी जातियों की एकता और संवाद में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे देश के कई राज्यों में जाति आधारित राजनीतिक दल बनने लगे और जातियां चुनाव के अवसर पर दबाव समूह के रूप में राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगें रखने लगीं।

इस बार लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही जातिगत जनगणना, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, राजनीतिक दलों द्वारा पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी गई। सभी राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे के लिए जातीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों की जाति पर जोर दिया। चुनाव के अवसर पर संविधान खतरे में है-जैसा विमर्श स्थापित करके नकारात्मक प्रचार किया गया। कई राज्यों में जातीय संगठनों ने खुलकर कुछ राजनीतिक दलों का विरोध किया। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रवाद के साथ-साथ जातीय समीकरण चुनाव जीतने के लिए आवश्यक हैं। औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर नवनिर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रस्तुत किया था, उसे भी इन जातीय समीकरणों ने चुनौती दी है। जाति के नकारात्मक विमर्श को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के चार अमृत स्तंभों पर टिका है। देखा जाए तो ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त और सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। यह जातीय घृणा और संघर्ष को समाप्त करके आदर्श लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करेगा। याद रखें कि जाति को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता प्राप्त करना आसान है, लेकिन राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए जाति की राजनीति नकारात्मक है।

(लेखक बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्राध्यापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का लक्ष्य

विभिन्न क्षेत्रों में छोटी-छोटी उपलब्धियों से मिलकर एक सफल जीवन का निर्माण होता है। इसके साथ संतुष्टि का भाव भी जुड़ा होता है। हर व्यक्ति एक सफल जीवन का अधिकारी हो सकता है यदि वह कुछ सूत्रों को जीवन में धारण करे और उनका अनुसरण करे। इनमें सर्वप्रथम है जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता। इसके लिए समयसीमा में कार्य करने की आदत डालनी होती है, क्योंकि समय पर किए गए कार्य का ही महत्व होता है। कार्य को नियमित रूप से करने का अभ्यास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से करनी चाहिए।

बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर नियमित रूप से हासिल करना चाहिए। हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क अधिक उपयुक्त होता है जिससे कम परेशानी में बेहतरीन परिणाम हासिल होते हैं। लक्ष्य के संबंध में अपनी रुचि का होना भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। सफलता की राह में कई तरह के अवरोध आते रहते हैं, जो आपको लक्ष्य से विचलित कर सकते हैं। ये अवरोध मोबाइल, टीवी या इंटरनेट मीडिया से लेकर आलस्य, संशय, भ्रम तथा प्रमाद आदि के रूप में भी हो सकते हैं। इनसे पार पाने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा हो जो आपके लिए सतत आनंद का स्रोत बने न कि एक बोझिल यात्रा बन जाए। सफर को रुचिकर बनाने के लिए बीच-बीच में विश्राम के पल भी जोड़ सकते हैं। उचित समय एवं तनाव प्रबंधन, वाणी-व्यवहार का संयम तथा आपसी रिश्तों में मधुरता लाने का भी कार्य करें। नियमित रूप से आत्म विश्लेषण करते रहें। इधर-उधर की बातों पर ध्यान न देने के बजाय अंतरवाणी को सुनें। हर कदम पर मिल रहे सबक को सीखते रहें।

इन सूत्रों को अपनाने से आपके जीवन के बाहरी तथा आंतरिक सभी पक्ष सधेंगे और समय के साथ समग्र सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

अवधविहारी शुक्ल

बीमार मानसिकता की निशानी

सुनीता मिश्रा

कहीं भी थूक देना गंदी आदत है, लेकिन थूक से मसाज करना, रोटी पर थूक लगाना और भी घिनौनी हरकत है

सैलून में थूक लगाकर मसाज करने के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। आरोपित जैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों शामली में भी थूक लगाकर मसाज करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपित अमजद को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में वह एक व्यक्ति के चेहरे पर मसाज के दौरान थूक लगाते हुए दिखाई दे रहा था। वैसे इस तरह का यह न तो पहला मामला है और न आखिरी। वर्ष 2022 में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने भी ऐसी ही करतूत की थी। एक वायरल वीडियो में हबीब एक महिला के हेयर कटिंग के दौरान थूकते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि मामले पर आक्रोश बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली थी। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में ढाबों में रोटी बनाते समय थूकने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। नवंबर 2021 में भी गाजियाबाद में रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो सामने आया था। लोगों की शिकायत के बाद आरोपित को हिरासत में लिया गया था। इसके पीछे एक अजीब किस्म की मानसिकता काम करती है।

कहीं न कहीं इस तरह के मामले गंभीर बीमारियों को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51(बी) के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। कोविड महामारी को चार साल से अधिक का समय बीत गया है। संक्रमण से बचाव के उपाय और टीकाकरण ने रोग की गंभीरता तो कम की है, पर नए वैरिएंट्स के कारण जोखिम लगातार बना हुआ है। कोरोना से निपटने के लिए देश में महामारी अधिनियम भी लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत नियमों और आदेशों का उल्लंघन अपराध माना गया है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित किया था।

थूक से कई तरह के वायरल, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण फैलते हैं। थूक में मौजूद बैक्टीरिया लगभग 10 घंटे तक जीवित रहते हैं, जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इससे लोगों में बीमारियां होने की आशंका भी बनी रहती है। थूक से कोरोना के अलावा टीबी, निमोनिया, जुकाम और चर्म रोग भी फैल सकते हैं। इसलिए थूकने से पहले अन्य लोगों के बारे में भी सोचें। सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी थूक देना बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन किसी इंसान के चेहरे पर अपने थूक से मसाज करना, रोटी पर थूक लगाना और भी घिनौनी हरकत है। थूक लगाकर मसाज करने और रोटी में थूकने वालों को दंडित करना बेहद जरूरी है, ताकि फिर कोई और ऐसा करने का दुस्साहस न कर सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बढ़ती आतंकी गतिविधियां

'आतंक के नए दौर की वापसी' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी गतिविधियों की वापसी को देश के लिए खतरनाक बताया है। कश्मीर में खून-खराबा करने की हदें लांघने के बाद पाकिस्तान ने अब जम्मू में आतंकी हिंसा का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि निशाने पर हिंदू गांव और श्रद्धालु लिए जा रहे हैं। अगर समय रहते इन आतंकी हमलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका असर जम्मू से सटे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाकों पर भी पड़ सकता है। यह सही है कि जम्मू-कश्मीर की विषम भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाकर आतंकी बार-बार सिर उठा रहे हैं। वे प्रदेश में फैले जंगल में छुपे रहते हैं और मौका मिलते ही सेना और आम नागरिकों पर हमला कर देते हैं। आतंकी उन निर्दोष लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने रोजगार मुहैया कराया है। मोदी सरकार ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पहली बार हिम्मत दिखाते हुए नियंत्रण रेखा पार करके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में उनके ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद बड़े आतंकी हमलों में गिरावट देखी गई थी। आतंकवाद को पूरी तरह बंद करने के लिए हाजी पीर दर्रे और घुसपैठ के अन्य मार्गों को बंद करना समय की भी मांग है, क्योंकि इसके बिना अनुच्छेद-370 को हटाने का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आतंकी जम्मू-कश्मीर में बाहर से काम की तलाश में पहुंच रहे कामगारों की हत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे पाकिस्तान को अति गंभीर सबक सिखाए।

bhimsinghpardeshi2@gmail.com

मेलबाक्स

जनता तक पहुंचे योजनाओं के लाभ

मोदी की नई सरकार के पास योजनाओं और कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जो कि सराहनीय है। सरकार को सिर्फ नीतियों की घोषणा करने से ज्यादा, उनकी सटीक और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचे। इसके अलावा सरकार को बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। इस हेतु सरकार को एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोका जा सके। आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता पर भी बल दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार केवल आर्थिक विकास पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय पर भी ध्यान दे। अंत में अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि आम जनता का सरकार पर विश्वास बढ़े और वे सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

awanishg30@gmail.com

सरकार की सफलता की कसौटी

सरकार तो नीतियां बनाती है मगर उन नीतियों को जमीन पर उतारने का काम नौकरशाही और छोटे कर्मचारियों का है। हमारे देश में प्रशासनिक सुधार के अभाव में सरकारी कामकाज की कुशलता को नई धार नहीं मिल सकी है। लोगों में सरकारी नौकरी को जवाबदेह एवं जिम्मेदारी मुक्त आरामतलब सेवा मानने का भाव है। ऐसी धारणा सीमा से अधिक सुरक्षा कारण पैदा हुई है। दरअसल अब सरकारी सेवकों के मामले में ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि अगर वह लापरवाही से अपना काम करेंगे तो निजी क्षेत्र की तरह उनकी भी नौकरी जा सकती है। लिहाजा नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मेरे अनुसार एक व्यापक प्रशासनिक सुधार की है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

सोमवार, 17 जून, 2024 : ज्येष्ठ शुक्ल - 11 वि. 2081

कर्तव्य का बोध जीवन को सार्थकता प्रदान करता है

जम्मू में आतंक की चुनौती

जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक में वहां के हालात की समीक्षा करते हुए आतंक को कुचलने के जो निर्देश दिए, उन पर इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए कि आतंकियों को सिर उठाने और छिपाने का मौका न मिले। इस बैठक में गृह मंत्री ने जिस तरह यह कहा कि जैसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण पाया गया है, वैसे ही जम्मू संभाग में भी पाया जाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि जम्मू की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। यह हाल की घटनाओं से स्पष्ट भी होता है। जम्मू संभाग के रियासी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की एक बस को आतंकियों ने ठीक उस दिन निशाना बनाया जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगियों के साथ शपथ ले रहे थे। यह आतंकी हमला एक तरह से तीसरी बार सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार को दी जाने वाली सीधी चुनौती ही था। इस हमले के बाद आतंकियों ने जिस प्रकार एक के बाद एक डोडा, कठुआ आदि इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, उससे उनके दुस्साहस का ही पता चलता है।

एक लंबे समय से यह प्रकट हो रहा है कि आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू को अपने निशाने पर ले लिया है। जम्मू संभाग के वे इलाके आतंकियों के गढ़ बन गए हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इन इलाकों में आतंकियों की बढ़ी हुई गतिविधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में जुट गया है। इसकी पुष्टि पिछले दिनों कठुआ में मारे गए दो पाकिस्तानी आतंकियों से भी होती है। उनके पास से बरामद हथियार और सामग्री से यह स्पष्ट हुआ कि वे पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू में आए थे। अच्छा होता कि इन आतंकियों के नाम-पते और उनके पास से बरामद पाकिस्तानी सामग्री को देखते हुए भारत सरकार पाकिस्तान से जवाब तलब करती और प्रमाणों के साथ उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बेनकाब करती। निःसंदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ी जाए, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान को नए सिरे से यह बताया जाए कि उसे भारतीय भूभाग में आतंक फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता तो यह लगभग तय है कि वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को कुचलने के लिए कोई कसर इसलिए शेष नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का समय करीब आ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ पुराने तौर-तरीकों के बजाय नए उपाय करने की आवश्यकता रेखांकित की। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जैसे दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, उससे निपटने के लिए नए और कारगर उपाय किए जाने जरूरी हैं।

निगरानी जरूरी

एलजी द्वारा ग्रामोदय अभियान के तहत चल रहे कार्यों की निगरानी के लिए जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय करना सराहनीय कदम है। ठेकेदारों के लिए भी अपने किए कार्यों की पांच साल की वारंटी देने की शर्त लगाना देना अच्छा निर्णय है। गांवों का विकास करने के नाम पर पूर्व में भी अनेक योजनाएं बनी हैं, तो करोड़ों रुपये का व्यय भी हो चुका है। पर जवाबदेही के अभाव में कोई सकारात्मक बदलाव आ ही नहीं पाता। गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश जारी करना भविष्य में गांवों के जीवन में बदलाव का भी द्योतक है। जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि योजनाओं का प्रारूप तय करते हुए ग्रामीणों से भी सलाह मशविरा करें, इससे गांव वासियों की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।

> योजनाओं का प्रारूप तय करते समय अधिकारी ग्रामीणों से भी सलाह-मशविरा करेंगे, तो समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है

यह सही है कि दिल्ली देहात का अधिकांश क्षेत्र विकास से वंचित है। सड़क, सार्वजनिक परिवहन, सीवर, अस्पताल, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। कई गांव ऐसे हैं, जहां खेतों में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, जिससे वह खेती नहीं कर सकते हैं। डीटीसी की बसें भी कम पहुंचती हैं, तो मेट्रो से भी सभी गांव नहीं जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे बीमार लोगों को उपचार कराने में परेशानी होती है। उम्मीद है कि अधिकारी इस अभियान के उद्देश्य को पूरा करने में गंभीरता से काम करेंगे। लोगों की समस्याओं की पहचान कर निर्धारित समयसीमा में उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। इसके लिए आवंटित धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों को भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अपने स्तर पर समस्याओं और संभावित विकास कार्यों की सूची तैयार कर लें, जिससे कि एलजी और अधिकारियों के सामने उसे रख सकें। राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अरुंधती राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने का फैसला सही है?

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि तमाम सवालों के बाद प्रतियोगी परीक्षा नीट का फिर से आयोजन ही उचित होगा?

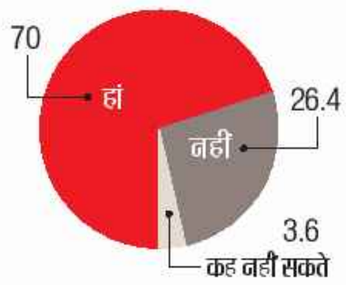

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

एक आवश्यक राजनीतिक सुधार

हृदयनारायण दीक्षित

सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है और वह कई समस्याओं का समाधान साबित होगा

हम भारत के लोग अक्सर चुनावी तनाव में रहते हैं। लोकसभा चुनाव अभी-अभी संपन्न हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद दिल्ली एवं बिहार आदि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। नगरीय क्षेत्रों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। लगातार चुनावी व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधक है। चुनावों के दौरान प्रशासनिक तंत्र की अलग व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी आचार संहिता के दौरान विकास कार्य भी रुक जाते हैं। अलग-अलग चुनावों में अरबों रुपये का व्यय होता है। इसलिए सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 'एक देश-एक चुनाव' का विचार व्यक्त किया था। इस संबंध में मंथन के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति भी बनी थी। समिति ने 47 राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त किए। 32 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। समिति ने 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मार्च में प्रस्तुत की थी। समिति ने चार पूर्व मुख्य न्यायधीशों, उच्च न्यायालय के 12 मुख्य न्यायधीशों, चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और आठ राज्य चुनाव आयुक्तों जैसे विशेषज्ञों से परामर्श मांगे थे। नागरिकों से 21,558 सुझाव प्राप्त हुए। विधि आयोग ने 2018 में एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब समिति ने इस प्रसंग से जुड़े सभी मसलों पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नई सरकार में कमान संभालते ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए हैं।

कोविंद समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उसने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए संविधान में संशोधनों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। एक साथ चुनाव के लिए नियत तारीख निर्दिष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-82 में संशोधन का सुझाव दिया है। एक साथ चुनाव के लिए 'नियत तारीख' के बाद जहां राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए संसद के साथ समन्वय कर लेंगे। समिति के अनुसार सब कुछ योजनाबद्ध होता है तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव 2029 में हो सकता है। यदि 2034 के चुनावों को लक्षित किया जाता है तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद नियत तारीख की पहचान होगी। तब जिन राज्यों में जून 2024 और मई 2029 के मध्य चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल 18वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद या राज्य विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव के अगले चक्र तक शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति का तर्क है कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव एक साथ चुनाव की समग्र समय सीमा को प्रभावित नहीं करता।

अवधेश राजपूत

संसदीय चुनावों के साथ नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव का समन्वय जरूरी है। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय पंचायती क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी अंतर होते हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन कानून बनाने का परामर्श दिया है। यह कानून स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनाव समय सीमा के साथ जोड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से सभी स्तरों पर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने में सक्षम बनाएगा। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर है और स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। समिति ने दोनों की एक ही मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव दिया है। कई बार इन सूचियों में विसंगतियां होती हैं तो सूची को प्रामाणिक बनाने का आग्रह है।

सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है। भारत में राजनीतिक सुधारों विशेषतः चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। यह एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे संघवाद को क्षति होगी। यह कहना गलत है। सभी राज्य एक साथ-एक चुनाव में राज्यों एवं केंद्र के मुद्दे एक साथ उठाएंगे। इससे राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से जुड़ेंगे। क्षेत्रीय दलों की दृष्टि अखिल भारतीय होगी। एक साथ चुनाव के विरोधी अनावश्यक रूप से घबराए हुए हैं। साथ-साथ चुनाव से आम जनों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। वे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी देखेंगे। क्षेत्रीय दल स्थानीयता से ऊपर उठेंगे। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ने की भी भरी-पूरी संभावना है। एक साथ चुनाव से नुकसान की बात करने वाले भूल जाते हैं कि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव का सिलसिला कायम रहा।

कुछ दल कोविंद समिति की रपट का अध्ययन किए बिना ही उसे खारिज करने पर तुले हैं। कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करने से संविधान की बुनियादी संरचना में बदलाव होंगे। यह संघवाद के खिलाफ है। कांग्रेस यह न भूले कि भारतीय संघ अमेरिकी संघवाद नहीं है। यहां राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। संविधान सबको बांधकर रखता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए आशंका जताई कि इससे राज्य के मुद्दों को दबाया जा सकता है। द्रमुक की दलील है कि इसके लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता होगी। सपा ने कहा कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभावी होंगे। इनसे इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि एक साथ चुनाव का विचार संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। भाजपा, एनपीपी, अन्नाद्रमुक, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल (सोनेलाल), असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव का समर्थन कर रहे हैं। याद रहे कि कोई भी देश लगातार चुनावी मोड में नहीं रह सकता। चुनावी आरोप-प्रत्यारोप सामाजिक चेतना और तानेबाने को आहत करते हैं। एक साथ चुनाव असल में कई समस्याओं का समाधान है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

विकास पर हावी जाति की राजनीति

डा. सुशील पांडेय

नतीजे बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रवाद के साथ जाति चुनाव जीतने के लिए जरूरी है

कांग्रेस ने छेड़ा जातिगत जनगणना का राग ● फाइल

इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के घोषणा पत्र और चुनावी मुद्दों के केंद्र में जाति आधारित राजनीति ही हावी रही। देखा गया कि चुनाव के पूर्व सभी राजनीतिक दलों ने अलग-अलग क्षेत्रों में जातीय संरचना को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई। देश के कई हिस्सों में जातीय संगठनों ने भी अलग-अलग राजनीतिक दलों को समर्थन देने की घोषणा की। कई जातीय संगठनों ने तो अपने जातिगत हितों के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य किया और अपनी जातीय चेतना को प्रभावी बनाने के लिए जातीय आधार पर अनेक बैठकों का आयोजन भी किया। भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवैधानिक और तार्किक रूप से जाति व्यवस्था अप्रासंगिक होने के बाद भी राजनीति में कैसे प्रभावशाली हो गई है

इतिहास पर नजर डालें तो भारत की जटिल सामाजिक संरचना में जाति महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका में रही है। प्राचीन और मध्यकालीन समाज में तो जाति व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण का आधार थी। देश में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होने के बाद से जाति व्यवस्था नए स्वरूप में सामने आई। राजनीतिक ढांचा बदल जाने और नई न्यायिक और आर्थिक व्यवस्था ने जाति के आधार को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही सामाजिक आंदोलनों ने जाति के वैचारिक पक्ष को कमजोर कर दिया। आजादी के लिए आरंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ, जिससे जाति पर आधारित सभी प्रकार की विसंगतियां समाप्त हो गईं। गांधीजी और डा. आंबेडकर के जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के बाद भी दोनों जननेता जातिगत असमानताओं को अस्वीकार करते थे और लोकतंत्र को जाति उन्मूलन का सशक्त आधार मानते थे। संविधान सभा के सदस्य भी जाति व्यवस्था तोड़कर समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के पक्षधर थे।

स्वतंत्रता के बाद जब देश ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया तो संख्या बल की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अलग-अलग जातियों ने इसे अपने लिए बड़े अवसर के रूप में देखा। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का स्थानीय स्वरूप था और जातियां अपने व्यवसाय के आधार पर संगठित थीं, लेकिन आजादी के बाद जातियों ने वर्ग के रूप में स्वयं को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। एक समान व्यवसाय वाली जातियां पहले क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय आधार पर स्वयं को संगठित करने लगीं। जातियों के अखिल भारतीय संगठन बनने लगे। उत्तर भारत में प्रारंभ में सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियों का वर्चस्व रहा, लेकिन हरित क्रांति के प्रभाव के कारण जाट, यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसी जातियां धीरे-धीरे राजनीति में प्रभावी हो गईं। वहीं, दक्षिण भारत की राजनीति में कर्नाटक में लिंगायत, वोक्कालिगा, आंध्र प्रदेश में कापू, रेड्डी, कम्मा, तमिलनाडु में वेलालर, थेवर, वानियर, नाडर, महाराष्ट्र में मराठा, धनगर, माली, महार, राजस्थान में जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर जैसी जातियां राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं।

भारत में जाति व्यवस्था अपने सदस्यों के लिए कल्याणकारी राज्य जैसी भूमिका निभाती है जैसे अपने सदस्यों के लिए जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों, धर्मशालाओं, धार्मिक संस्थाओं और सामूहिक विवाह, भोज समारोह का आयोजन करना। इन सभी कारणों से जातीय एकजुटता आती है। ऐसी स्थिति में जातियां मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित होने लगती हैं और अन्य जातियों के प्रति आक्रामक और विरोधी भाव रखने लगती हैं। प्रत्येक जाति संगठन स्वयं को किसी महापुरुष अथवा धार्मिक व्यक्तित्व से भी जोड़ता है और उन्हें महिमामंडित करते हुए जाति एकजुटता को सशक्त बनाता है। संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण भी जातियों की एकता और संवाद में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे देश के कई राज्यों में जाति आधारित राजनीतिक दल बनने लगे और जातियां चुनाव के अवसर पर दबाव समूह के रूप में राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगें रखने लगीं।

इस बार लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही जातिगत जनगणना, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, राजनीतिक दलों द्वारा पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी गई। सभी राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे के लिए जातीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों की जाति पर जोर दिया। चुनाव के अवसर पर संविधान खतरे में है-जैसा विमर्श स्थापित करके नकारात्मक प्रचार किया गया। कई राज्यों में जातीय संगठनों ने खुलकर कुछ राजनीतिक दलों का विरोध किया। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रवाद के साथ-साथ जातीय समीकरण चुनाव जीतने के लिए आवश्यक हैं। औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर नवनिर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रस्तुत किया था, उसे भी इन जातीय समीकरणों ने चुनौती दी है। जाति के नकारात्मक विमर्श को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के चार अमृत स्तंभों पर टिका है। देखा जाए तो ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त और सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। यह जातीय घृणा और संघर्ष को समाप्त करके आदर्श लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करेगा। याद रखें कि जाति को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता प्राप्त करना आसान है, लेकिन राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए जाति की राजनीति नकारात्मक है।

(लेखक बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्राध्यापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का लक्ष्य

विभिन्न क्षेत्रों में छोटी-छोटी उपलब्धियों से मिलकर एक सफल जीवन का निर्माण होता है। इसके साथ जीवन में संतुष्टि का भाव भी जुड़ा होता है। हर व्यक्ति एक सफल जीवन का अधिकारी हो सकता है यदि वह कुछ सूत्रों को जीवन में धारण करे और उनका अनुसरण करे। इनमें सर्वप्रथम है जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता। इसके लिए समयसीमा में कार्य करने की आदत डालनी होती है, क्योंकि समय पर किए गए कार्य का ही महत्व होता है। कार्य को नियमित रूप से करने का अभ्यास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से करनी चाहिए।

बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर नियमित रूप से हासिल करना चाहिए। हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क अधिक उपयुक्त होता है जिससे कम परेशानी में बेहतरीन परिणाम हासिल होते हैं। लक्ष्य के संबंध में अपनी रुचि का होना भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। सफलता की राह में कई तरह के अवरोध आते रहते हैं, जो आपको लक्ष्य से विचलित कर सकते हैं। ये अवरोध मोबाइल, टीवी या इंटरनेट मीडिया से लेकर आलस्य, संशय, भ्रम तथा प्रमाद आदि के रूप में भी हो सकते हैं। इनसे पार पाने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा हो जो आपके लिए सतत आनंद का स्रोत बने न कि एक बोझिल यात्रा बन जाए। सफर को रुचिकर बनाने के लिए बीच-बीच में विश्राम के पल भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ उचित समय एवं तनाव प्रबंधन, वाणी-व्यवहार का संयम तथा आपसी रिश्तों में मधुरता लाने का भी कार्य करें। नियमित रूप से आत्म विश्लेषण करते रहें। इधर-उधर की बातों पर ध्यान न देने के बजाय अंतरवाणी को सुनें। हर कदम पर मिल रहे सबक को सीखते रहें।

इन सूत्रों को अपनाने से आपके जीवन के बाहरी तथा आंतरिक सभी पक्ष सधेंगे और समय के साथ समग्र सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होगा। फिर एक दिन उस परम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी।

अवधविहारी शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बढ़ती आतंकी गतिविधियां

'आतंक के नए दौर की वापसी' शीर्षक से लिखे आलेख में दिव्य कुमार सोती ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी गतिविधियों की वापसी को देश के लिए खतरनाक बताया है। कश्मीर में खून-खराबा करने की हदें लांघने के बाद पाकिस्तान ने अब जम्मू में आतंकी हिंसा का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि निशाने पर हिंदू गांव और श्रद्धालु लिए जा रहे हैं। अगर समय रहते इन आतंकी हमलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका असर जम्मू से सटे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाकों पर भी पड़ सकता है। यह सही है कि जम्मू-कश्मीर की विषम भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाकर आतंकी बार-बार सिर उठा रहे हैं। वे प्रदेश में फैले जंगल में छुपे रहते हैं और मौका मिलते ही सेना और आम नागरिकों पर हमला कर देते हैं। आतंकी उन निर्दोष लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने रोजगार मुहैया कराया है। मोदी सरकार ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पहली बार हिम्मत दिखाते हुए नियंत्रण रेखा पार करके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में उनके ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद बड़े आतंकी हमलों में गिरावट देखी गई थी। आतंकवाद को पूरी तरह बंद करने के लिए हाजी पीर दर्रे और घुसपैठ के अन्य मार्गों को बंद करना समय की भी मांग है, क्योंकि इसके बिना अनुच्छेद-370 को हटाने का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आतंकी जम्मू-कश्मीर में बाहर से काम की तलाश में पहुंच रहे कामगारों की हत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे पाकिस्तान को अति गंभीर सबक सिखाए।

bhimsinghpardeshi2@gmail.com

नई सरकार के वादों का यथार्थ

मोदी सरकार के पास योजनाओं और कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जोकि सराहनीय है। लेकिन, सवाल यह उठता है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में जमीन पर उतारी जा रही हैं या सिर्फ कागजों पर ही सीमित हैं? 'हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और' वाली कहावत यहां सटीक बैठती है। सरकार को सिर्फ नीतियों की घोषणा करने से ज्यादा, उनके सटीक और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचे। इसके अलावा सरकार को बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोका जा सके। आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता पर भी बल दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार केवल आर्थिक विकास पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय पर भी ध्यान दे। अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र विकसित करना चाहिए

- अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

नीट पर गहराता विवाद

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विवाद गहराता जा रहा है। छात्रों में रोष भी बढ़ रहा है। पुलिस जांच भी पेपर लीक अपराधों की नई-नई परतें खोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों से समस्या के सुलझने की संभावना कम ही है। इसमें छात्रों का एक वर्ष व्यर्थ हो सकता है। मेडिकल कालेजों का एक एकेडेमिक वर्ष भी खराब हो सकता है। पटना, गोधरा व झज्जर में पेपर लीक के समाचारों और 1563 ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा से विवाद गहराएगा, क्योंकि एक ही प्रवेश प्रक्रिया के लिए दो अलग-अलग परीक्षाओं का औचित्य नहीं हैं। यह पारदर्शी भी नहीं हो सकती। केंद्र सरकार को इस विवाद से अलग होकर पूरी प्रवेश परीक्षा दोबारा करने का आदेश देना चाहिए। उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं के वर्तमान स्वरूप ने ही असंगठित और बेलगाम कोचिंग उद्योग को रुपये 5,8000 करोड़ तक पहुंचा दिया है, जो अगले चार वर्षों में रुपये 1.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। जब तक विश्विद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, विधि की उच्च शिक्षा में स्कूली, बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का वेटेज, नेशनल टैलेंट हंट जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित की गईं प्रतियोगिताओं, स्कूलों और कालेजों में समय-समय पर आयोजित प्रतिस्पर्धाओं, डिबेट, माडल के स्कोर का विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में वेटेज नहीं दिया जाएगा, प्रतिभाशाली छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा।

-विनोद जौहरी, दिल्ली

पोस्ट

जार्ज सोरोस के बाद कांग्रेसी इकोसिस्टम को एलन मस्क के रूप में एक नया 'मसीहा' मिल गया है।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

भाजपा नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल इस समय रसातल में है। अगर यही सिलसिला कायम रहा तो अगले दस वर्षों के दौरान बंगाल में भाजपा गायब भी हो सकती है।

तथागत राय@tathagata2

केंद्र से लेकर राज्यों तक की सभी सरकारें प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि देश में तमाम भर्ती परीक्षाएं समय पर संपन्न हों। पारदर्शिता और शुचिता के साथ हों तथा आवेदन से नियुक्ति तक की संपूर्ण प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी हो।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

कभी भारतीय पेस आक्रमण को औपचारिकता कहा जाता था। इस टी-20 विश्व कप में बुमराह और अर्शदीप को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी माना जा रहा है। विराट, रोहित और सूर्यकुमार के बल्ले की दादागीरी नहीं, तेज गेंदबाजी मैच जिता रही। वनडे विश्व कप की तरह भारत अब तक अपराजित है। यह आइसीसी ट्राफी जीतने का दुर्लभ मौका है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जनपथ

ईवीएम पर फिर शुरू होता दिखे विवाद,
भाई एलन मस्क जी देते पानी-खाद।
देते पानी-खाद यहीं आ जाओ भ्राता,
करो शौक से जांच मिलेगा पूरा डाटा।
दुनिया में कुछ लोग मनाते दिखते हैं गम,
निष्कलंक इस बार रही कैसे ईवीएम!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नीना ए जीक्यूटि व चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय संपादक-प्रदीप कुमार शुक्ल*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तर दायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 34 अंक 334

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ सोमवार, 17 जून 2024

आप जो काम आज कर सकते हैं, उसे कल पर न टालें। टालमटोल करना समय की बर्बादी है। -चार्ल्स डिकेंस

महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड परियोजना के पूरे होने से निश्चित रूप से पहाड़ी रास्ते ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल जरूरी है कि प्रशासन व बीआरओ कुछ वैकल्पिक उपाय जरूर करें, ताकि रुद्रप्रयाग जैसे हादसों की आवृत्ति या कम से कम इससे होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके।

खतरनाक मोड़

उत्तराखंड के ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास रैंतोली में बीते शनिवार को हुए हादसे की तस्वीरें वाकई बेहद दर्दनाक व हृदयविदारक हैं। दरअसल, शुक्रवार की रात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तेईस युवाओं का एक दल चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था। लेकिन शनिवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे यात्री वाहन अनियंत्रित होकर तेज बहती अलकनंदा नदी के किनारे करीब ढाई सौ फुट गहरी खाई में गिर गया। यात्री वाहन में दो ड्राइवर व एक हेल्पर समेत कुल छब्बीस लोग थे, जिनमें से दस लोगों ने मौके पर, तो चार लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में चालक समेत चार लोग उत्तर प्रदेश के थे। चूंकि पिछले दिनों पहाड़ी जिलों में ऐसे कई सड़क हादसे सामने आए हैं, ऐसे में, जरूरी है कि इनके कारणों की पड़ताल हो, ताकि इनकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रथमदृष्टया, बदरीनाथ हाइवे पर हुआ हादसा मानवीय लापरवाहियों का नतीजा ही दिखता है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ऐसे हादसे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क-सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। दुर्घटना का प्राथमिक कारण चालक को झपकी आना और उसे पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव न होना बताया जा रहा है। हालांकि वाहन में क्षमता से ज्यादा लोगों का सवार होना और वाहन की तेज गति भी इस हादसे की वजह हो सकती हैं। हैरत की बात है कि हादसे से पहले वाहन को जांच के लिए रोका भी गया था। चूंकि वाहन चारधाम यात्रा पर नहीं था और इसलिए वाहन का ट्रिपकार्ड तो नहीं ही बना था, यात्रियों का चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी नहीं था। ऐसे में, वाहन को बगैर इसकी जांच किए कि कहीं उसमें क्षमता से ज्यादा लोग तो सवार नहीं है, आगे जाने की अनुमति दी गई। दूसरी तरफ, परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पहाड़ी सड़कों पर तेज ढलान तो होती ही है, इस जगह पर सड़क भी काफी संकरी है और

खतरनाक मोड़ है, सो अलग। दरअसल, चमोली, नैनीताल, देवप्रयाग इत्यादि पहाड़ी जिलों से पिछले कुछ समय से सड़क हादसों की जो खबरें आई हैं, उनसे सड़कों की सुरक्षा का मुद्दा केंद्रीय महत्व का बनना ही चाहिए। 825 किलोमीटर लंबी चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड परियोजना, जो अपने अंतिम दौर में है, के पूरे होने से निश्चित रूप से पहाड़ी रास्ते ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। फिलहाल जरूरी है कि प्रशासन व बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन कुछ वैकल्पिक उपाय जरूर करें, ताकि रुद्रप्रयाग जैसे हादसों की आवृत्ति या कम से कम इससे होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके।

नीट परीक्षा कैसे होगी क्लीन

अमेरिका की तरह हम भी नीट में परीक्षा पर निर्भरता को कम कर और इसे अधिक पारदर्शी बनाकर कई समस्याएं दूर कर सकते हैं। इसमें राज्यों की भागीदारी, ग्रामीण विद्यार्थियों की जरूरत, स्कूलों में चिकित्सा शिक्षा पर बल और कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर इसकी विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं।

इस साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट परीक्षा) कुछ गलत कारणों से सुर्खियों में आ गई है। 'नीट ऐंड क्लीन' वैसे तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या नीट परीक्षा क्लीन हो सकेगी? देश भर में विद्यार्थी सड़कों पर हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, और केंद्र की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है।

इसका कारण यह है कि इस बार की परीक्षा में कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें हुई हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं। एक तो इसका परिणाम नियत तिथि से 10 दिन पहले, यानी जिस दिन लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो रहे थे, ठीक उसी दिन सियासी गहमागहमी के बीच चुपके से घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, पेपर लीक होने, इक्का-दुक्का की तुलना में 67 टॉपर्स होने, असंभव स्कोर होने, करीब 1,500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने, कट-ऑफ अधिक होने, एक ही कोचिंग सेंटर से आठ विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में शामिल होने आदि के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-नीट) भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों (एमबीबीएस और बीडीएस) में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रव्यापी परीक्षा है। यह परीक्षा भारत के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों के लिए एकमात्र प्रवेश परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। इनमें सरकारी और निजी, दोनों तरह के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं और सीटों की संख्या लगभग एक लाख है।

राजेश कुमार
एनआईओएस के पूर्व निदेशक

साल में एक बार आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठते हैं, यानी एक सीट के लिए लगभग 24 विद्यार्थी अपना भाग्य आजमाते हैं। इससे पता चलता है कि ये दाखिले कितने आकर्षक और लाभदायक माने जाते हैं। विद्यार्थी इसके लिए कड़ी मेहनत

करते हैं, कोचिंग करते हैं, और कुछ विद्यार्थी एवं उनके माता-पिता इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं, और ठीक यहीं से समस्या शुरू होती है। यह परीक्षा बहुविकल्पी (मल्टीपल-चॉइस) प्रश्नों के आधार पर ली जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) शीट पर उत्तर अंकित करने होते हैं। यह परीक्षा की विश्वसनीयता स्थापित करने और शीघ्रता से परीक्षा परिणाम घोषित करने में मदद करता है। तो फिर समस्याएं क्यों हो जाती हैं?

सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक होने की है। चूंकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश केवल परीक्षा के स्कोर पर ही निर्भर होता है, इसलिए भ्रष्टाचारी लोग इसमें आसान कमाई का रास्ता ढूंढ लेते हैं, खासकर तब, जब कुछ माता-पिता इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस की तुलना में यह कीमत फिर भी काफी कम रहती है। और कम खर्चे वाले सरकारी कॉलेजों में प्रवेश इसी परीक्षा के माध्यम से संभव होता है। इसके बाद एनटीए को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है।

तो क्या यह सब इसी तरह से चलता रहेगा, और हम हाथ-पर-हाथ धरकर बस देखते रहेंगे? आइए, देखते हैं कि कुछ दूसरे देश इस काम को किस तरह हमसे बेहतर विश्वसनीयता के साथ करते हैं, और क्या हम उनसे कुछ सबक ले सकते हैं? अमेरिका में इसके लिए मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट (एमसीएटी) आयोजित किया जाता है। इस टेस्ट की तीन मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं–प्रवेश के अनेक घटक, सुरक्षा और पारदर्शिता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अमेरिका में दाखिले के लिए केवल परीक्षा पर ही निर्भर नहीं रहा जाता। इसमें इसके अलावा तीन घटक और शामिल हैं। इसके लिए आवेदक को समग्र आवेदन पैकेज जमा करना होता है, जिसमें शामिल हैं-(1) निजी कथनः इसमें आवेदक अपनी अभिप्रेरणाओं, अनुभवों और गुणों को स्पष्ट करते हैं, जो उन्हें दाखिले के लिए उपयुक्त सिद्ध करें। (2) अनुशंसा पत्रः अध्यापक या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आवेदक के शैक्षिक निष्पादन, कार्य नैतिकता और सफल विद्यार्थी होने की संभावना के बारे में जानकारी देते हैं। (3) साक्षात्कारः इससे मेडिकल कॉलेज आवेदक के संप्रेषण कौशलों, पारस्परिक कौशलों, और पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्तता का आकलन कर सकते हैं।

परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए अमेरिका में कड़े प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। इसमें सुरक्षित परीक्षा केंद्र स्थापित करना, नियंत्रित परीक्षा परिवेश और परीक्षा सामग्री तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के उपाय शामिल हैं। मानकीकृत स्कोरिंग प्रणाली सभी परीक्षार्थियों का निष्पक्ष और सुसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। इससे पेपर लीक होने और परीक्षा संस्थान को प्रभावित करने की समस्याएं दूर हो जाती हैं।

एमसीएटी संगठन विषय-वस्तु क्षेत्रों, स्कोरिंग और तैयारी के संसाधनों पर विस्तृत जानकारी के साथ समग्र परीक्षण गाइड भी देता है। एमसीएटी विषय-वस्तु और फॉर्मेट की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उसे चिकित्सा शिक्षा की उभरती जरूरतों को शामिल करने के लिए अपडेट किया जाता है, ताकि भ्रम की गुंजाइश न रहे और ग्रेस मार्क्स देने की नौबत न आए। एमसीएटी संगठन संभावित पूर्वाग्रहों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डाटा का विश्लेषण करता है और फीडबैक प्राप्त करता है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और न्यायसंगत बनी रहे।

संभवतः हम भी नीट में परीक्षा पर निर्भरता को कम करके और इसे अधिक पारदर्शी और मानक बनाकर बहुत-सी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें राज्यों की भागीदारी रखकर, ग्रामीण विद्यार्थियों की जरूरतों पर ध्यान देकर, स्कूलों में चिकित्सा शिक्षा पर बल देकर, कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर, और इसकी प्रक्रिया में निरंतर सुधार करके इस परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सके, तो न केवल प्रतिभावान छात्रों के साथ न्याय कर पाएंगे, बल्कि परीक्षा में कदाचार रोकने में सफल होंगे एवं भ्रष्ट तरीकों से कमाई करने वाले आपराधिक तत्वों पर भी अंकुश लगा पाएंगे। संस्थानों की विश्वसनीयता को बनाए रखना मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयां भी आती हैं और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है, जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो।

जीवन को समझने के लिए खोलें मन की परतें

भावनाएं मानव मन का हिस्सा हैं। मन में इच्छाएं, प्रेम, ईर्ष्या जैसी भावनाएं शामिल हैं। इसके विपरीत विश्वास, दोहरा मन और वह सब भी इसमें शामिल है, जिसे हम समझते और महसूस करते हैं। लेकिन जो अलग है, वह है इसकी अभिव्यक्ति। समस्या सही या गलत महसूस करने की नहीं है, क्योंकि मनुष्य महसूस तो करेगा। जरूरत जिस चीज को बदलने की है, वह है बहुत-सी चीजों को पा लेने, हासिल कर लेने का लोभ, लालच। लोग जीवन की अच्छी चीजें चाहते हैं और फिर भी संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। मगर ऐसा संभव होता नहीं है। एक वास्तविक मन में महत्त्वाकांक्षा और अधिग्रहण के लिए कोई जगह नहीं होती। आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयां भी आती हैं और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है, जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो। तब पश्चाताप, कठिनाई और दर्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

समग्रता में जीने का मतलब जीवन को खंडों या एक विचार के रूप में देखना नहीं है, बल्कि विचारों और खंडों की एक शृंखला के रूप में देखना है, और एक ही समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना है। हर पहलू में खुशियां और दुख साथ दिखेंगे। हम अपने भीतर जितने कम विभाजनकारी होंगे, उतना ही हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर पाएंगे। और ऐसा मुक्त मन से ही संभव होगा। मुक्त मन के लिए पूर्ण जागरूकता जरूरी है। मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भीतर की ओर देखे और खुद को आत्मपीड़ा से मुक्त करे। एक मन को खोजी और वैज्ञानिक होना चाहिए। पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को परत-दर-परत उजागर करना चाहिए। हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। कार्य के दौरान हम एक व्यक्ति होते हैं, दोस्तों के बीच दूसरे और घर-परिवार के बीच एक अलग रूप में। एक खंडित मन कभी भी चेतना के बारे में जागरूक नहीं हो सकता। एक-एक करके टुकड़ों को समझने के लिए मन की परतों को खोलना जरूरी है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सप्ताह से लेकर महीनों और वर्षों तक लग सकते हैं। हमारे जीवन का हर अनुभव हमारे मन में गहराई से अंकित होता है। इसकी ताकत सुख और दुख में बदलती रहती है और बाद में हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आती रहती है। यह फ्रायड की कल्पना की तरह ही लगता है, जिन्होंने कहा था कि बचपन के हमारे अनुभव हमारे वयस्क होने और जीवन के साथ हमारे समायोजन का आधार बनते हैं। लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। हम जब नियंत्रित विचारों के पिंजरे को नष्ट कर देते हैं, तो मनुष्य को एक नई आजादी मिलती है, जो दर्दनाक अनुभवों से आजादी नहीं है, बल्कि इन अनुभवों के मन पर छोड़े गए निशान से मुक्ति है।

आदत से मुक्ति

सूत्र

हम जिस क्रिया को भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वह आदत बन जाती है और एक स्वतंत्र मन को विकसित नहीं होने देती। कभी-कभी दुख हमारी आदतों पर आधारित होता है और जब हम एक आदत पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरी आदत बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आदतों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे मुक्ति पाना है।

दूसरा पहलू

न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में 1924 में शुरू हुई टोन्नो'स पिजेरिया नाम की दुकान बिकने वाली है, जिसकी हर जगह चर्चा है।

परिवार, सौ साल की दुकान और कोयले की आंच में पिज्जा

न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में सौ साल पुरानी पिज्जा की दुकान अगर बिकने वाली है, तो यह एक खबर भर नहीं है। वर्ष 1924 में इटली के नेपल्स से आए एंटोनियो पैरो ने टोन्नो'स पिजेरिया नाम की जो दुकान खोली थी, वह न सिर्फ आज भी उसी परिवार के पास है, बल्कि अब भी पुराने चूल्हे में कोयले की आंच में एक सदी पुरानी रेसिपी से तैयार पिज्जा को न्यूयॉर्क सिटी में सबसे स्वादिष्ट बताया जाता है। लगभग दो साल पहले तक भी यह दुकान सिर्फ नकदी ही लेती थी, लेकिन कोविड के समय से मालिकों ने क्रेडिट कार्ड स्वीकारना शुरू किया। बूढ़े हो चुके दो भाई और एक बहन, जो इस दुकान के मालिक हैं, इसे इसलिए बेचना चाहते हैं, क्योंकि इसे चलाने के लिए उनके पास अब लोग नहीं हैं। लेकिन उनकी शर्त है कि जो यह दुकान खरीदेगा, उसे पुराने तरीके से ही पिज्जा तैयार करना पड़ेगा।

पेटे वेल्स

दुकान चलाने के लिए उसके मालिकों के पास अब लोग नहीं हैं। लेकिन शर्त है कि जो यह दुकान खरीदेगा, उसे पुराने तरीके से ही पिज्जा तैयार करना पड़ेगा।

दुकान की मालकिन मिसेज सिमिनिएरी कहती हैं कि उनके चाचा के पिता एंटोनियो पैरो मैनहटन के स्पिंग स्ट्रीट के एक पिजेरिया में पिज्जा बनाते थे। वे पिज्जा कागजों में लपेटकर प्रवासी इतालवियों को बेचने जाते थे।

दुकान की मालकिन मिसेज सिमिनिएरी कहती हैं कि उनके चाचा के पिता एंटोनियो पैरो 1903 में अमेरिका आने के बाद मैनहटन के स्पिंग स्ट्रीट के एक पिजेरिया में पिज्जा बनाते थे। वे पिज्जा कागजों में लपेटकर प्रवासी इतालवियों को बेचने जाते थे, जो पास की ही बस्तियों में रहते थे। पिज्जा के इतिहास के जानकार और *पिज्जा टुडे* मैगजीन में कॉलम लिखने वाले स्कॉट वायनर कहते हैं, 'टोन्नो'स पिजेरिया अमेरिका में पिज्जा की शुरुआती दुकानों में से तो है ही, अमेरिका में ऐसा और कोई परिवार नहीं है, जिसके पास पिज्जा बनाने का सौ साल पुराना इतिहास हो।'

कोनी आइलैंड में चीजें उस तेजी से नहीं बदलतीं, जिस रफ्तार से वे मैनहटन में बदलती हैं। इस लिहाज से टोन्नो'स पिजेरिया में पिज्जा आज भी उसी तरह तैयार होते हैं, जिस तरह एंटोनियो पैरो वर्ष 1903 में बनाते थे। जब पुराने चूल्हे की ईंटें टूट गईं, तो उन्हें हटा दिया गया। पुराने उपकरणों को भी तब बदला गया, जब उनकी मरम्मत संभव नहीं थी। मैनुअल कैश रजिस्टर, पुराने तराजू और पनीरकस के बेकार हो जाने के बाद फेंकने के बजाय उन्हें सामने की खिड़की पर सजाकर रखा गया। ऐसे ही, सबसे पुराने रेफ्रिजरेटर को पीछे के दो छोटे-छोटे कमरों वाले पुराने घर में रखा गया है, जहां कभी एंटोनियो पैरो ने पत्नी के साथ मिलकर अपने चार बच्चों को पाला था। स्कॉट वायनर का मानना है कि टोन्नो'स पिजेरिया के मालिक बदल जाने से पिज्जा का स्वाद तो बदल ही जाएगा, सौ साल पुरानी परंपरा भी शायद खत्म हो जाएगी।

©The New York Times 2024

आंकड़े

चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार

भारत हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अब उससे आगे अमेरिका, चीन और जापान हैं।

नोट : आंकड़े ट्रिलियन डॉलर में हैं। | स्रोत : IANS

एक बार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में चर्चा हुई कि सत्संग और तपस्या में किसकी महिमा अधिक है। इसके निर्णय के लिए दोनों शेषनाग के पास पहुंचे।

सत्संग की महिमा

अंतर्यात्रा
संकलित

पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आप पृथ्वी पर जाकर सूर्यवंश के राजाओं के यहां पुरोहित का काम कीजिए। इस पर वशिष्ठ ने अनिच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि आगे चलकर इसी वंश में पुरुषोत्तम श्रीराम का पूर्ण अवतार होने वाला है, तो वह सहर्ष पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र, दोनों ही श्रीराम के गुरु थे।

एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र शेषनाग के पास पहुंचे कि सत्संग और तपस्या में कौन बड़ा है? शेषनाग बोले कि मेरे ऊपर पृथ्वी का भार है। यदि आप इस पृथ्वी को संभाल लें, तो मैं आपकी बात का कुछ निर्णय करूं। विश्वामित्र ने अपनी दस हजार वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर रखने का प्रयास किया, लेकिन धरती डगमगाने लगी। शेषनाग ने वशिष्ठ से कहा कि आप प्रयास कीजिए। वशिष्ठ ने सत्संग के आधे क्षण का संकल्प किया और पृथ्वी को लंबे समय तक अपने सिर पर धारण किया। इसके बाद शेषनाग ने फिर पृथ्वी अपने सिर पर धारण कर ली। विश्वामित्र ने पूछा कि बताइए सत्संग व तपस्या में किसकी महिमा ज्यादा है।

शेषनाग ने कहा कि निर्णय तो हो गया, आपने तपस्या का पूरा फल लगा दिया, तब भी पृथ्वी को संभाल नहीं सके, जबकि वशिष्ठ ने आधे सत्संग के संकल्प से ही पृथ्वी को धारण कर लिया। दोनों ऋषियों ने यह सब सत्संग की महिमा साबित करने के लिए किया था।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 नवंबर, 1950

नेपाल में हुए परिवर्तन को भारत सरकार मान्यता न देगी

नेपाल के नैतिक परिवर्तन को भारत सरकार मान्यता न देगी

भारत के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नेपाल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और प्रधानमंत्री ने तीन साल के बच्चे ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया है, भारत सरकार उसे मान्यता न देगी। नेपाल के कानून का अध्ययन किया जाएगा।

अमेरिका में भारत-पाकिस्तान बीसमबीस

क्रिकेट के आनंद को उन देशों में ले जाया जा रहा है, जहां इस खेल को खेलने की कोई लगन, लगाव और लौ नहीं रही है।

संदीप जोशी

टी-20 विश्वकप

आखिर न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच बीसमबीस विश्व कप में क्रिकेट का मैच ही हुआ। एक को ही जीतना था, सो भारत जीत भी गया। चिर प्रतिद्वंद्वी के बीच मैच कांटे का होना था, सो भी हुआ। क्रिकेट खेलने वाले पारंपरिक देशों से अलग, यह बीसमबीस विश्वकप अमेरिका और उसके आसपास के छोटे-छोटे वेस्टइंडीज द्वीपों में खेला जा रहा है। क्रिकेट की लोकप्रियता को भुनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी), खेल के पारंपरिक देशों से अलग उसे दूसरे देशों में ले जाने में लगा है।

21वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट के पांच दिवसीय टेस्ट मैच प्रारूप को बचाने की कवायद चल रही थी। टेस्ट मैच को समय और खर्च की बर्बादी माना जा रहा था और बदलाव की बातें उठ रही थीं। कम समय में कैसे भरपूर मनोरंजन दिया जाए? कैसे बाजार में क्रिकेट के प्रति उम्मीदें जगाई जाएं? बीसमबीस या

इससे जुड़ी कम ओवर की क्रिकेट इंग्लैंड की गर्मियों में पिछली शताब्दी के आखिर में खेली जाने लगी थी। इंग्लैंड की गर्मी में दिन खासे लंबे हो जाते हैं, इसलिए काम के बाद शाम को कम समय की क्रिकेट लोकप्रिय होने लगी थी। सन नब्बे के आखिर में अपन ने भी बीसमबीस खेलने का उत्साह और आनंद इंग्लैंड में देख-समझ लिया था। आईसीसी ने लोगों के उत्साह व बाजार का ध्यान रखते हुए विश्व स्तर की बीसमबीस स्पर्धा कराने का खाका बनाया। पहला टी-20 विश्वकप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें भारत विजेता बना। विश्वकप में जीत से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने अपने खेल के जुनून से विश्व क्रिकेट की आर्थिकी ही बदल दी। फिर आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग हो गई। अब हर दो साल में बीसमबीस और विश्व टेस्ट मैच स्पर्धा होने लगी है। एकदिवसीय विश्वकप हर चार साल में ही हो रहा है। यानी बीसमबीस की लोकप्रियता ने भी टेस्ट क्रिकेट में वही जोश, उत्साह और रोमांच भर दिया, जो सत्तर के दशक में एकदिवसीय क्रिकेट ने भरा था।

वेस्टइंडीज में होने वाले विश्वकप को इस बार ज्यादा देशों में ले जाकर अमेरिका में भी मैच कराने का सोचा गया। अमेरिका में रह रहे प्रवासी उपमहाद्वीप के क्रिकेट प्रेम को भुनाने की कोशिश की गई। शुरुआती मैच अमेरिका में हुए। अमेरिका की जिस टीम ने पाकिस्तान को हराया, उसमें छह भारत व दो पाकिस्तान के खिलाड़ी एच-1बी वीजा पर वहां रह रहे हैं। अमेरिका से कुछ घंटों की ही हवाई दूरी पर वेस्टइंडीज के द्वीपों में अंतिम आठ देश विश्वकप विजेता होने के लिए खेलेंगे। खेल के इस प्रारूप की लोकप्रियता ने क्रिकेट के प्रचार-प्रसार की संभावनाओं का आकाश खोल दिया है।

अमेरिका में बीसमबीस विश्वकप मैच कराने के लिए कुछ जरूरी साजो-सामान जुटाने थे। सबसे जरूरी पिच, दर्शकों के बैठकर मजा लेने की सुविधाएं और दुनिया भर में टीवी पर मैच दिखाए जाने की समय-सारणी। विशेषज्ञ के कहने पर ऑस्ट्रेलिया से कच्चा माल मंगाया गया। क्रिकेट की दस 'ड्रॉप-इन' पिच कुछ ही महीनों में तैयार की गई। हालांकि पिचों की वजह से अमेरिका में हुए सभी मैच में जो मजा किरकिरा हुआ, उसका कारण बिना मिट्टी-घास जमने का समय दिए, ड्रॉप की गई पिच रहीं। जो बीसमबीस खेल के चौके-छक्कों के लिए अनुकूल नहीं थीं।

तेजी में दर्शकों के बैठने की सुविधाएं बनाना तो अमेरिका में मुश्किल नहीं था, लेकिन पिच के अलावा मैदान की घास को भी जमने में समय लगना ही था। इसलिए आउटफील्ड धीमी और कुछ जगह ऊबड़-खाबड़ भी रही। मगर अमेरिकियों की भी कमर तोड़ने वाली तो विश्वकप मैच के टिकट और गाड़ियों की पार्किंग थी। इन मैचों को देखने वाले तो प्रवासी भारतीय या उपमहाद्वीप के लोग थे। मुद्दा मैच के टीवी प्रसारण के समय का था। उपमहाद्वीप में शाम को दिखाया जाने वाला मैच अमेरिका में सुबह कराना पड़ा। इस असुविधा से अमेरिकियों को गुजरना ही था। खैर, क्रिकेट का दुनिया के सबसे धनी और बड़े लोकतंत्र में पैर पसारना ही शुभ शुरुआत है। अमेरिका ही वह देश है, जहां समय को पैसे से तौला जाता है। इसलिए बीसमबीस से समय बचाते हुए क्रिकेट से पैसा कमाया जाएगा। उस पैसे के बदले में क्रिकेट के आनंद को उन देशों में ले जाया जा रहा है, जहां उस खेल को खेलने की कोई लगन, लगाव और लौ नहीं रही है।

युद्ध शुरू करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि मनुष्य का जीवन अनमोल है।

– बर्ट्रेंड रसेल

खुलती राहें

आत्याधुनिक अर्थव्यवस्था वाले सात देशों के समूह जी-7 के शिखर सम्मेलन में भारत की विशेष उपस्थिति इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत का ही प्रमाण है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, मगर हर वर्ष इसे विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाने लगा है। हालांकि इस बार इटली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारह विकासशील देशों के नेताओं को भी निमंत्रित किया गया था, पर भारत को खास तवज्जो दी गई। दरअसल, यह सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध और हमास-इजराइल संघर्ष जारी है। पूरी दुनिया अभी मंदी की चपेट में है। यहां तक कि जी-7 के सदस्य देश अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जापान भी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आ रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। जी-7 के मंच से प्रधानमंत्री ने फिर अपना संकल्प दोहराया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। उधर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर जी-7 देशों की भागीदारी लगातार घट रही है। वे विश्व जीडीपी में साठ फीसद की भागीदारी से चालीस फीसद पर पहुंच गए हैं।

भारत लगातार विकसित देशों के समांतर एक ताकतवर समूह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी रणनीति के तहत जी-20 सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को भी समूह में शामिल किया गया। इस तरह भारत वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मंच पर लाकर एक नया आर्थिक मंच बनाना चाहता है। जी-7 के सदस्य देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सहित वैश्विक दक्षिण एक विशाल बाजार है, वहां सस्ते श्रम की उपलब्धता भी भरपूर है। हालांकि इस बार के शिखर सम्मेलन में प्रमुख रूप से दुनिया भर में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने, वैश्विक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी रणनीतियां बनाने पर जोर रहा, पर रूस और चीन की वजह से बढ़ते तनाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जी-7 समूह के सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और उनके साथ व्यापार-वाणिज्य संबंधी गतिविधियां निरंतर बढ़ रही हैं। जी-7 का जोर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर है, इस तरह भारत इसमें मजबूत कड़ी साबित होगा।

भारत के सामने फिलहाल कड़ी चुनौती चीन की तरफ से है। चीन को लेकर जी-7 देश भी वक्र दृष्टि रखते हैं। इस दौर में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कमजोर होता गया है और जी-7 देश वैश्विक मामलों में निर्णायक साबित हो रहे हैं, वे भारत को विशेष रूप से अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, तो निश्चय ही यह चीन के लिए चिंता का विषय होगा। रूस-यूक्रेन संघर्ष में भी भारत की मध्यस्थता को अहम माना जा रहा है, जबकि इन दिनों रूस की नजदीकी चीन से बढ़ी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जी-7 के मंच से यह संकल्प दोहराया कि वे पड़ोसी देशों से रिश्ते मधुर बनाने पर जोर देंगे, ताकि वे चीन की गिरफ्त से बाहर निकल सकें, यह भी चीन के लिए रणनीतिक रूप से परेशान करने वाली बात है। जी-7 के इस शिखर सम्मेलन से भारत के लिए नई राहें खुलती नजर आती हैं।

परीक्षा में धांधली

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित इस बार की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठते सवाल गहरे कर दिए हैं। कुछ केंद्रों पर गलत पर्चा बंटने के बाद से ही विद्यार्थी आरोप लगाते रहे कि प्रश्नपत्र पहले ही बाहर निकल चुके हैं, मगर राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए लगातार उस आरोप को खारिज करती रही। फिर नतीजे आए तो उसमें कई विसंगतियां देखी गईं। सड़सठ विद्यार्थियों को पूरे सात सौ बीस अंक मिले थे। करीब सोलह सौ विद्यार्थियों को कृपांक दिए गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो उसने स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मगर फिर भी एनटीए और सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता रहा कि परीक्षा का पर्चा बाहर नहीं गया, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कुछ त्रुटि हो सकती है। उसके लिए एक जांच समिति गठित कर दी गई। सोलह सौ विद्यार्थियों को दुबारा परीक्षा में बैठने की सहूलियत दी गई। मगर अब सबूत सामने आने लगे हैं कि प्रश्नपत्र पहले ही बाहर हो गया था।

इससे एक बार फिर एनटीए की साख धूमिल हुई है। इस संस्था का गठन ही इस मकसद से किया गया था कि यह पूरी पारदर्शिता के साथ और चौक-चौबंद तरीके से प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इससे नकल माफिया पर अंकुश लगेगा। जिस तरह पूरे देश में नकल माफिया का जाल फैल चुका है और वे सख्त से सख्त पहरे में भी सेंधमारी करने में माहिर हो चुके हैं, उससे पार पाने में एनटीए को एक कारगर तंत्र माना जा रहा था। मगर वह भी विफल हो चुका है। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे फोड़ने में सबसे अधिक कोचिंग संस्थानों का हाथ देखा गया है। राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं तक में वे सेंध लगाते पाए गए हैं। उन पर नकेल कसने का अभी तक कोई पुख्ता तंत्र नहीं बन पाया है। परीक्षाओं में धांधली होनहार विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ और व्यवस्था में औसत तथा अयोग्य लोगों की फौज जमा करते जाने की कोशिश है। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना मुश्किल है।

बदलाव से ही बदलेगी तस्वीर

हम अपने देश की दस्तकारी और कला-कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें, रुपया अपने आप मजबूत होगा, कमजोर होने से बचेगा। सरकार को इसके लिए बनावटी बंदिशें नहीं लगानी पड़ेंगी।

सुरेश सेठ

देश के कर्णधारों को यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के चमकते आंकड़ों से कहीं अधिक आम आदमी की समस्याओं का समाधान जरूरी है। ये समस्याएं हैं- हर काम योग्य व्यक्ति को उसके काम की गारंटी, देश के हर नागरिक को उचित सेहत की सुरक्षा और नई पीढ़ी को दी जाने वाली वह शिक्षा, जो उन्हें दुनिया की श्रम मंडियों में एक बिकने वाली वस्तु नहीं, बल्कि अपने ही देश में एक ऐसी शक्ति बनाए जिसकी सहायता से हम अपने देश में एक नए युग का सृजन कर सकें, जिसे कायाकल्प कहते हैं। आज तक इन समस्याओं के समाधान की जगह अगर उन्हें आंकड़ों से बहलाने की कोशिश की जाती रही है, तो उसी का नतीजा है यह मोहभंग की अवस्था, जो आज देश की आम जनता से आंखें मिलाकर खड़ी हो गई है और जिसने पूरे देश में यह भावना पैदा की है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब इस युग में एक नई कार्यदीक्षा से ही बात बनेगी। चिंतन और कारगुजारी में एक नया तेवर लाने से ही बात बनेगी।

आम आदमी ने आज एक नया सच सामने रख दिया है कि भाषणों, दावों, अधूरे आंकड़ों और लंबित परियोजनाओं से नहीं, प्रगति और विकास की विश्व रैंकिंग की सीढ़ियां चढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले इस देश में काम करने योग्य युवकों की संख्या सर्वाधिक है और वे अपने लिए इज्जत की रोटी चाहते हैं। अनुकंपाओं और उदारता की राजनीति अब उनको दिलासा नहीं देती। अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा 2029 तक बढ़ाकर उन्हें भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन न तो उसका प्रशासन आम लोगों की खुशहाली का जामिन बन सका और न ही उनकी सेहत सुरक्षा का आश्वासन दे सका। देश के कुपोषित नौजवान ही नहीं, नौनिहाल भी उचित पोषण न पाने के कारण एक ऐसी आबादी बन रहे हैं, जो जिंदा तो है, लेकिन सेहत के प्रतिमानों पर पूरा नहीं उतरती।

यहां शिक्षा के माडल की बहुत बात होती है, लेकिन देश को डिजिटल बना देने और कृत्रिम मेधा के संसार में अपना झंडा गाड़ देने के बावजूद हमारे देश के अधिकांश युवा ऐसे हैं, जिनकी व्यावहारिक योग्यता स्नातक की डिग्रियां लेने के बाद भी प्राथमिक स्तर की है। नौजवान आज भी इन शिक्षा परिसरों में परंपरावादी कला और विज्ञान की डिग्रियों के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि जमाना उनसे कृत्रिम मेधा और रोबोट युग में उतरने के साथ डीपफेक के संकटों का मुकाबला करने की चुनौती देता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे की इस शिक्षा के साथ देश में सस्ते उपचार के माडलों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन निजी चिकित्सा इतनी महंगी है कि उसमें अपने परिवार का भविष्य संकट में डालने की जगह लोग नीम हकीमों के उपचार को शिरोधार्य करके मौत को गले लगाना अधिक पसंद करते हैं।

सरकार ने तो कह दिया कि सत्तर वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन आयुष्मान योजना

का अनुभव बताता है कि इसके पहले सीमित क्षेत्र में भी पांच लाख की आय तक के नागरिकों को उचित उपचार नहीं मिलता था। निजी चिकित्सा क्षेत्र ने सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र का साथ देने का वादा कभी निभाया नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र में उचित दवाओं से लेकर डाक्टरों का अभाव

> देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। इसे बनाने के लिए अपने रुपए का विनिमय महत्त्व भी डालर, पाउंड और यूरो के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपए से विदेशों में निवेश करने की इजाजत होगी। बड़ी दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते, तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपए की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है।

मरीजों के रोगी हो जाने का दुर्भाग्य उद्घाटित करता रहा। भारत में इसी कारण औसत आयु कम हो रही है कि न उचित कमाई है, न उचित शिक्षा और न उचित चिकित्सा। अशिक्षा के अंधेरों में अपराध पलता है।

देश की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की सकल घरेलू आय में उसका योगदान घटते-घटते पंद्रह फीसद क्यों हो गया? हमने घोषणा तो की थी कि हम अपनी प्रगतिशील नीतियों और कृषि क्रांति के साथ कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वह आज भी अपनी फसल की उचित कीमत के लिए तरसते हुए महाजनों और साहूकारों से समझौते करते नजर आते हैं। जो लोग कृषि से उखड़ कर महानगरों में अपना वैकल्पिक आर्थिक जीवन ढूंढ़ने के लिए आए, उन्हें यहां कोई आधार नहीं मिला। कोविड महामारी ने उन्हें फिर गांव की ओर लौटा दिया। अब नई चुनौती यह है कि इस श्रमबल को वैकल्पिक जीवन कैसे दिया जाए? यह वैकल्पिक जीवन कस्बों और गांवों में ही विनिवेश करने से संभव होगा। इसके लिए लघु और कुटीर इकाइयों का जाल पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बिछ जाना चाहिए, जहां कार्ययोग्य नौजवानों को उचित नौकरियां मिल सकें। उनका कमाया हुआ वेतन उन्हें वह आत्मसम्मान देगा, जिससे वे नए भारत के निर्माण में पूरे सम्मान के साथ जुड़ सकें।

देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। इसे बनाने के लिए अपने रुपए का विनिमय महत्त्व भी डालर, पाउंड और यूरो के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपए से विदेशों में निवेश करने की इजाजत होगी। बड़ी दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते, तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपए की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है। आरबीआइ ने इस सच को स्वीकार कर लिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के एजंडे में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता रखा है। यानी भारतीय रुपए को विदेश भेजने से या विदेशी मुद्रा को देश में लाने की कोई रोकटोक नहीं होगी।

दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की कीमत बाजार के तत्त्व तय करेंगे और उसको तय करेगा हमारे निर्यात का प्रोत्साहन। हम अपने देश की दस्तकारी और कला-कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें, रुपया अपने आप मजबूत होगा, कमजोर होने से बचेगा। सरकार को इसके लिए बनावटी बंदिशें नहीं लगानी पड़ेंगी। भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपए लगाने की उतनी ही छूट होनी चाहिए, जितनी छूट हमने विदेशी निवेशकों को अपने देश में दे रखी है कि वे अपनी मुद्रा में निवेश कर सकते हैं। अगर बराबरी के स्तर पर व्यापार चलेगा तो बात बनेगी। बराबरी का आधार आत्मनिर्भरता होता है। आत्मनिर्भरता देश के युवा बल को बदलती डिजिटल और इंटरनेट दुनिया का पूर्ण प्रशिक्षण देने से ही पैदा होगी। लेकिन अगर यहां के नौजवान पलायन का रास्ता पकड़ विदेशी मंडियों में अपनी योग्यता देखते रहेंगे तो आत्मनिर्भरता हासिल करने में अभी बहुत समय लगेगा। जितना ही समय लगेगा, उतना ही देश की राजनीति में अनावश्यक उतार-चढ़ाव और देश की अर्थव्यवस्था में वंचितों का क्रंदन जारी रहेगा।

अपने और अपनों से दूर

मुग्धा

आज के समय में तेज, तेज और तेज भागना ही जीवन का मंत्र बन चुका है। कहीं आना-जाना हो तो सबसे तेज रफ्तार गाड़ी चाहिए, किसी से बात करनी हो तो सबसे तेज नेटवर्क का फोन चाहिए और कुछ जानना हो तो रंगीन या श्वेत-श्याम पन्नों वाली कोई अच्छी-सी किताब नहीं चाहिए, बल्कि सबसे तेज चलने वाला फोन या लैपटाप चाहिए। अगर कोई इस बात की चर्चा करने लगे कि मुश्किल से तीन-चार दशक पहले तक हजारों गांवों और कस्बों में बैलगाड़ी से आना-जाना भी आनंद देता था, तो शायद आज के किशोर इस पर यकीन न करें और सयाने लोग कहेंगे कि कैसा इंसान है कि विज्ञान की उन्नति के विरुद्ध बात करता है। जल्दी, जल्दी, और जल्दी ने शरीर को वाहन का इतना आदी बना दिया है कि थोड़ी दूर भी पैदल चलना बोझ लगने लगा है। मन भी इस हड़बड़ी के जंजाल में फंस गया है। तरह-तरह के 'टैबलेट' और कंप्यूटर आज सब कुछ जल्दी-जल्दी और घर बैठे उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो एक क्लिक पर तरह-तरह का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ खाना-पीना है, तब भी बीस मिनट के भीतर किसी को खाने-पीने की चीजें या पेय पदार्थ, चूरन, मिठाई, सब कुछ हाथ पर मिल रहे हैं। हमारा रुपया बैठे-बैठे एक बटन दबाते ही हमारी चाहत के अनुसार इधर-उधर जा सकता है। कपड़े-लत्ते, जूते-चप्पल- जो भी खरीदना है, बस एक बटन दबाते ही हमारे सामने पूरी दुकान खुल जाती है।

निजी स्वतंत्रता का दर्शन सप्रमाण आज की तकनीक ने उपलब्ध करा दिया है। हमको कुछ देखना है, तो अकेले देख लें, कोई दखल नहीं देता। कुछ खाना है तो मंगाते ही दरवाजे पर हाजिर। कुछ सुनना है, तो कान में इयरफोन लगाएं और अकेले-अकेले सुनें। निजी स्वतंत्रता के इस आभास में निजता का अधिकार कहां है, कुछ नहीं पता!

एक जमाना था, जब गांव-गांव, देहात और शहर की कालोनी में भी रामलीला, प्रहसन, नौटंकी कंपनी के रंग-बिरंगे कार्यक्रम, कठपुतली के खेल या सर्कस या जादू के खेल सामूहिक रूप से देखे जाते थे। इन सबका काम भी पेशेवर ही था। मनोरंजन करना और धन कमाना। मगर इन सबका एक बेहद खूबसूरत योगदान था कि सब लोग मिलकर इनका आनंद उठाते थे। समूह के समूह संग ताली बजाते और हंसते थे। इस तरह का भोग भी एक उत्सव बन जाता है। इसमें एक शानदार रंगत होती है। अब तो हाल यह है कि एक ही परिवार के चार लोग खाने की मेज पर अगर कभी एक साथ बैठते हैं, तो भी अलग-अलग खा रहे होते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है। उस पर कोई वेब सीरीज देख रहा है, तो कोई लूडो और कोई जुआ खेल रहा है। तकनीक का दखल कुछ परिवारों में इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग न तो अपने लोगों के साथ गपशप करते हैं, न उनके पास बैठना पसंद करते हैं।

जीवन की कुछ जरूरतें पूरी करने वाले 'उपकरण' जिंदगी पर ही हावी हो गए हैं। सब आनलाइन है। अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इन सोशल मीडिया उपकरणों से दुनिया भर के साथ संपर्क साधना आसान होता जा रहा है। इसलिए इनके गुलाम बनकर हम और भी सीमाएं तोड़कर आगे जा रहे हैं। मतलब परिवार, समाज, रिश्ते की सीमा तोड़ कर आगे जा रहे हैं। अपने परंपरागत तौर-तरीके की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में किसी फिल्म का एक संवाद भी बहुत सटीक था कि पहले जो गंदी और खराब बातें सड़क किनारे के शौचालय में लिखी रहती थीं, अब वह सोशल मीडिया के मंचों पर खुलेआम लिखी जा रही हैं।

इन दिनों फेसबुक और इस्टाग्राम में बेकार की बातों और बेकार की पोस्ट से लोग आपस में कलह-क्लेश भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक हजार मित्र हैं, मगर सामाजिक और भावनात्मक रूप से अकेलापन बढ़ रहा है। यह एक भयानक सच्चाई है। सारी दुनिया का तो पता है, मगर अपने पड़ोस और मुहल्ले की कोई खबर नहीं। आभासी जुड़ाव और सच से दूरी। अब हम आदमी की नहीं, एप की दुनिया में रहने के आदी हो रहे हैं। बस इसी से जीवन का रूप बिगड़ने लगता है। दरअसल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आज से डेढ़ दशक पहले जब एप्पल कंपनी का आइपैड जारी हुआ था, तब कुछ उत्सुक तकनीक प्रेमियों ने उसके मुखिया स्टीव जाब्स से पूछा कि 'उनका परिवार और खासकर उनके बच्चे इसे कितना पसंद करते है?' तब उनका जवाब था, 'मेरे बच्चों ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं यंत्रों से अपने बच्चों को बचाकर ही रखता हूं।' हाल में एक खबर थी कि यूरोप और अमेरिका में अवसाद और उदासी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये सख्त नियम बनाए जा रहे हैं कि पंद्रह वर्ष तक के बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटाप से दूर ही रहें। इसी दशक ने तकनीक के कारण ये बुरे दिन भी देखे हैं कि सुख, संतोष और आनंद सामाजिक नहीं, एकदम निजी होकर रह गए हैं।

कई बच्चे आलसी और थुलथुल हो रहे हैं। वे पार्क में नहीं जाते, कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, खेलकूद, पर्वतारोहण नहीं करते, कुछ साझा नहीं करते। एक और नकारात्मक प्रभाव कि अनगिनत किशोर और युवा सेल्फी लेने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठे। दरअसल, इंसान ने ही ये उपकरण बनाए हैं। आत्ममुग्धता ही इंसान की कमजोरी है। इसी कमजोरी का लाभ यह तकनीक उठा रही है। असली दुनिया से दूर रहकर कल्पना में खोए रहना। जरा-सी मेहनत करके लोकप्रिय होना। यही सब तो हासिल हो रहा है इन यंत्रों से।

दुनिया मेरे आगे

> तकनीक का दखल कुछ परिवारों में इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग न तो अपने लोगों के साथ गपशप करते हैं, न उनके पास बैठना पसंद करते हैं। जीवन की कुछ जरूरतें पूरी करने वाले 'उपकरण' जिंदगी पर ही हावी हो गए हैं।

महंगाई बनाम क्रयशक्ति

बढ़ती महंगाई और लोगों की घटती क्रयशक्ति से बाजार में मंदी के साथ ही चूल्हे-चौके ठंडे पड़ गए हैं। पिछले करीब तीन वर्षों के दौरान कुछ अप्रत्याशित झटकों से उबरने के बाद अब अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन इसके समांतर साधारण लोगों के सामने आज भी आमदनी के बरक्स जरूरत की वस्तुओं की कीमतें एक चुनौती बनी हुई हैं। लंबे समय बाद बीते वर्ष दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में खासी गिरावट हुई थी और वह 5.72 फीसद पर चली गई थी। तब यह उम्मीद की गई थी कि अब देश शायद मुश्किल दौर से उबर रहा है और बाजार आम लोगों के लिए भी अनुकूल होने की राह पर है। मगर बाजार की यह गति देर तक कायम नहीं रह सकी। सिर्फ एक महीने बाद खुदरा मुद्रास्फीति 6.52 फीसद पर पहुंच गई। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का भी असर ज्यादा कायम नहीं रह सका। यह अलग सवाल है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई मौद्रिक नीतियां किस स्तर तक कामयाब हो पाती हैं।

– प्रसिद्ध कुमार, बाबूचक, पटना

यूक्रेन शांति सम्मेलन

रूस-यूक्रेन युद्ध मानवता को शर्मसार कर रहा है। इस युद्ध में हजारों निर्दोष लोगों की बलि चढ़ गई। इस युद्ध को रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हुए, क्योंकि शुरू से ही अमेरिका इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ गई है। पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची है। अभी तक इस युद्ध में हार-जीत का निर्णय नहीं हो सका है। भारत शुरू से ही शांति बहाल करने की अपील करता रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यूक्रेन और पश्चिमी यूरोपीय देशों की अगुआई में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपने स्थान पर विदेश सचिव को भेज रहे हैं। भारत के विदेश सचिव के पास युद्ध रोकने का एक अवसर है, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

सुरक्षा में सेंध

जम्मू-कश्मीर में फिर आतंकियों ने सिर उठाया है। अब नए शांत इलाके में उन्होंने अपनी आतंकी गतिविधियां चलाई और लोगों को शिकार बनाया है। आतंकी पुनः सक्रिय न होने पाएं, इसके लिए सरकार को विशेष सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। सीमा पर चौकसी बढ़ानी चाहिए, ताकि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ न होने पाए। यों तो सरकार सजग है और विशेष कदम उठा रही है, फिर भी उसे और चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिर क्या गुनाह है उन श्रद्धालुओं का, जो बेवजह आतंकवाद का शिकार हो गए? कुवैत में भी अचानक ऐसी बिल्डिंग में आग लगी, जहां अधिकतर भारतीय थे और वे ही आग के शिकार हुए। भारत के विरुद्ध कहीं देश और विदेश में कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है, इसका पता हमारी गुप्तचर एजंसियां लगाएं और सरकार उचित कदम उठाएं, ताकि घर और बाहर हमारे देशवासी किसी षड्यंत्र का शिकार न होने पाएं।

– महेश नेनावा, इंदौर

अन्न की बर्बादी

आज एक तरफ लाखों लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा, भुखमरी के समाचार आते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अन्न की बर्बादी करने से बाज नहीं आते। अनाज के उचित रखरखाव और भंडारण हेतु अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध न होना भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। भारत में अन्न को बर्बाद करना या जूठा छोड़ना गलत माना जाता है। मगर शादियों, उत्सवों आदि मौकों पर आवश्यकता से अधिक भोजन थाली में लेकर उसे आधा-अधूरा खाकर छोड़ना फैशन बन गया है। अब वक्त आ गया है कि हर हाल में हम अन्न का दुरुपयोग रोकें, क्योंकि आने वाले समय में अन्न की कमी एक विकराल समस्या बनकर उभर सकती है। हर इंसान भोजन की बर्बादी रोकने का प्रयास करे। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए सामाजिक चेतना लानी होगी, वरना भविष्य में हमारे सामने एक बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

https://t.me/AllNewspaperPdf

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

महंगाई पर अंकुश के लिए प्रभावी नीतियों की दरकार

महंगाई पर लगाम कब कसेगी? यह सवाल अबूझ पहेली सा बन गया है। हाल ही वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय ने मई में महंगाई के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनसे एक और पहेली उभरी है कि क्या एक ही समय थोक महंगाई ज्यादा और खुदरा महंगाई कम हो सकती है? आमतौर पर जब चीजों के थोक भाव बढ़ते हैं तो खुदरा भाव भी बढ़ जाते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों पर भरोसा करें तो मई में थोक महंगाई 15 महीनों के उच्च स्तर (2.61%) पर पहुंच गई, जबकि खुदरा महंगाई घटकर इस साल के सबसे निचले स्तर (4.75%) पर आ गई।

आंकड़ों का यह मायाजाल महंगाई से लगातार जूझ रहे आम आदमी की समझ से परे है। खास तौर से ऐसे वक्त में जब सब्जियों की बढ़ती कीमतें उसकी थाली पर भारी पड़ रही हैं। बाजार भाव का थाली पर सीधा असर पड़ता है। महंगी सब्जियों ने मध्यम वर्ग के साथ समाज के उस वर्ग की दुश्वारियां बढ़ा रखी हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार या दिहाड़ी के सहारे रोजी-रोटी चलाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार आठवीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। यानी पिछले साल फरवरी से यही रेपो रेट चल रही है। फिर भी पिछले 16 महीनों में महंगाई लगातार बढ़ती गई। रेपो रेट में बदलाव नहीं करने के बावजूद हालात 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की' वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में नई मौद्रिक नीति के ऐलान के दौरान आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी माना कि महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार हैं। फिलहाल महंगाई का रुख अनिश्चित बना रहेगा। दरअसल, रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा रखी है। सप्लाई चेन बाधित होने से दुनियाभर में आम उपभोक्ता चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पहले कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से इन चीजों के दाम उछलते थे। अब सप्लाई चेन की रुकावट महंगाई का एक कारण बनी हुई है। इस दौर में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों को काबू में रखने की जरूरत है। ऐसी नीतियों की दरकार है, जिनसे मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों को चौतरफा महंगाई की मार से बचाया जा सके। पिछले कुछ साल में इन दोनों वर्गों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है और वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

आम लोगों को खाने-पीने के सामान की खरीदारी को लेकर भी सोचना पड़े तो साफ है कि महंगाई के मामले में पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर महंगाई पर काबू पाने की कार्ययोजना तैयार कर इस पर अमल भी जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए।

सीमा सुरक्षा : चीन की मानचित्रण और नाम बदलने की कूटनीति का जवाब देने की भारत की कोशिश

'जैसे को तैसा' की रणनीति पर काम, रंग लाएगा तिब्बत के कई स्थानों के नाम बदलने का अभियान

चीन के खिलाफ आखिरकार भारत को भी 'जैसे को तैसा' की रणनीति अपनानी पड़ी है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने को भारत ने गंभीरता से लिया है। आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारत इसका जवाब तिब्बत में देने की रणनीति बना रहा है। चीन द्वारा जबरन कब्जा किए गए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारत दो दर्जन से अधिक स्थानों का नाम बदलने के अभियान की योजना पर काम कर रहा है।

सीमा विवाद के मसले पर चीन लम्बे समय से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी सैन्य झड़प को चार साल बीत चुके हैं। लेकिन कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बावजूद चीन की हठधर्मिता के कारण अभी तक तनाव कम नहीं हो पाया है। हिंद महासागर में तो भारत और उसके सहयोगी देशों के पास अनेक अंतर्निहित क्षमताएं हैं, लेकिन जमीन पर मामला थोड़ा उलझा हुआ है। भारत के अधिकांश इंडो-पैसिफिक साझेदार अपना ध्यान फिलहाल चीन की समुद्री चुनौती पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे भारत को जमीनी सीमा पर अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है।

चीन द्वारा खासकर अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े प्रांत पर चीन के झूठे संप्रभुता दावे को मजबूत करना है। चीन इसे 'दक्षिणी तिब्बत' का नाम देता है। अरुणाचल प्रदेश में बदले गए भारतीय इलाकों के नामों पर चीन के दावों की हवा निकालने के भारतीय प्रयासों ने अब तेजी पकड़ ली हैं। यही नहीं, चीन के कब्जे वाले तिब्बत के अनेक स्थानों की एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुनः प्राप्त करते हुए नए नाम दिए जाएंगे। इस वैश्विक अभियान की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि चीन का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। इसी मार्च में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ 30 स्थानों का नाम बदल दिया था जिनमें आवासीय क्षेत्र, पहाड़, नदियां, झील, पहाड़ी दर्रा शामिल हैं। स्मरण रहे कि पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर लम्बे समय से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है।

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ
@patrika.com

चीन के कब्जे वाले तिब्बत के अनेक स्थानों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुनः प्राप्त करते हुए नए नाम दिए जाएंगे।

भारत के परम्परागत रुख के विपरीत चीन, मैकमहोन रेखा को 'साम्राज्यवादी विरासत' के रूप में खारिज करता है। हाल ही के सालों में यह चौथा अवसर है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का एकतरफा नाम बदलने का भड़काऊ काम किया है। इससे पहले कथित नए नामों की सूची 2017, 2021 और 2023 में चीन द्वारा जारी की गई थी जिसे भारत ने बार-बार नकारा है। यह रेखांकित करते हुए कि फर्जी नामकरण से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता, विदेश मंत्री एस. जयशंकर दो टूक कह चुके हैं कि 'अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा।' शी जिनपिंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपनी सीमाओं का हर तरफ और हम कीमत पर विस्तार करना चाह रही है। चीन अपने कई पड़ोसी देशों के खिलाफ क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और संप्रभुता पर असहमति का कोई मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने की स्थिति में उन दावों के लिए सबूत बनाने के लिए इन स्थानों का नाम बदल रहा है। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और भारत पिछले एक दशक से चीन के झूठे संप्रभुता दावों को झेल रहे हैं। मई 2024 में उपग्रह चित्रों से तो यह भी पता चला है कि भूटान के भीतर चीनी बस्तियों का तेजी से विस्तार हो रहा है।

जमीन हड़पने के लिए चीन द्वारा की जा रही ये हरकतें इतिहास के पुनर्लेखन का निर्लज्ज प्रयास हैं। वैसे भी चीन कभी भरोसेमंद देश नहीं रहा क्योंकि उसने समय-समय पर कई देशों की पीठ में छुरा घोंपा है। देखा गया है कि चीन केवल उन्हीं देशों के सामने घुटने टेकता है जो ताकत का जवाब ताकत से देते हैं।

अब भारतीय सूची जारी होने से अरुणाचल प्रदेश और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीन के झूठे दावों का मजबूती से जवाब मिलेगा। चूंकि नए नाम व्यापक ऐतिहासिक शोध के आधार पर रखे जा रहे हैं, इसलिए भारत के 'जैसे को तैसा' अभियान की विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी। इससे भी ज्यादा इसका दूरगामी मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होगा कि पिछले पांच दशक में पहली बार भारत द्वारा तिब्बत के प्रश्न को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से उठाया जाएगा। इससे निश्चित रूप से चीन पर दबाव पड़ेगा, लेकिन इतिहास को देखते हुए उससे सावधान भी रहना होगा और सीमा पर सतर्कता बरतनी होगी।

एक अच्छे पड़ोसी के रूप में भारत ने हमेशा तिब्बत को लेकर कोई विवाद पैदा नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन की मानचित्रण और नामकरण वाली कूटनीति की आक्रामकता की धार कम करने के लिए भारत सरकार ने भी कमर कस ली है। भारतीय सेना ने कई विवादित इलाकों में चीन के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। भारत का लक्ष्य वैश्विक मीडिया के माध्यम से विवादित सीमा पर भारत के पक्ष को आगे बढ़ाना है, जो ठोस ऐतिहासिक शोध पर आधारित है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेन्द्र मोदी ने एक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल आरंभ किया है और शासन के लिए उन्हें सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी। इस बदली हुई आंतरिक राजनीतिक परिस्थिति के बावजूद भारत की विदेश नीति में कोई खास बदलाव की गुंजाइश नहीं है। देश के तमाम राजनीतिक दल इस बात पर एकजुट हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी वैश्विक शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

नेतृत्व

सार्वभौमिक मूल्यों पर रहता है ध्यान

यह तय है कि कार्यस्थल आध्यात्मिकता आधुनिक संगठनात्मक रणनीतियों को आकार दे रही है और आगे भी देगी।

किसी भी संस्थान में कर्मचारियों द्वारा सार्थक कार्य किया जाना, सभी में एक समुदाय होने का भाव और संगठन या संस्थान के मूल्यों के साथ व्यक्तिगत संरेखण - ये तीन घटक कार्यस्थल आध्यात्मिकता के लिहाज से महत्त्वपूर्ण होते हैं। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो पारंपरिक कार्य करने की सीमाओं से परे, ऑफिस में व्यक्तिगत तत्वों को शामिल करती है। यह एक कर्मचारी की संतुष्टि और कल्याण में योगदान करती है। हालांकि यह जानना भी आवश्यक है कि कार्यस्थल आध्यात्मिकता क्या नहीं है।

कार्यस्थल आध्यात्मिकता के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि इसमें पंथ विशेष प्रथाएं शामिल हैं या संगठन के भीतर पंथविशेष मान्यताओं को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह किसी भी अनुष्ठान या सिद्धांत को निर्धारित या उसका समर्थन नहीं करती है। इसके विपरीत, यह अखंडता, विचारशीलता और करुणा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका उद्देश्य कार्य के माध्यम से मानवीय भावना को बढ़ाना है। कार्यस्थल आध्यात्मिकता को केवल एक प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि कर्मचारी संतुष्टि और संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण संगठन के पेशेवर उद्देश्यों से विचलित नहीं होता है, बल्कि यह कार्य अनुभव को समृद्ध करता है। इस प्रकार, कार्यस्थल आध्यात्मिकता एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो पेशेवर प्रयासों के साथ व्यक्तिगत महत्व की खोज को एकीकृत करती है।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक,
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

पिछले कुछ वर्षों में कार्यस्थल आध्यात्मिकता का विकास कई कारकों से प्रेरित रहा है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था और कार्यबल में बढ़ती विविधता ने कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने और समग्र व समावेशी तरीके से इसका प्रबंधन करने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में बढ़ती रुचि, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के बारे में अधिक जागरूकता ने भी कार्यस्थल पर आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, कार्यबल में प्रवेश करने वाली नई युवा पीढ़ी ने ऐसे कार्यस्थलों के प्रति स्पष्ट प्राथमिकता दिखाई है जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों और सार्थक जुड़ाव के अवसर प्रदान करें। संगठनों ने यह स्वीकारना शुरू कर दिया है कि अपने कर्मचारियों की भावना का पोषण करना व्यावसायिक उत्कृष्टता और स्थिरता प्राप्त करने से जुड़ा है। इस प्रकार, कार्यस्थल आध्यात्मिकता आधुनिक संगठनात्मक रणनीतियों को आकार दे रही है और आगे भी देगी। इससे अधिक संवेदनशील और उद्देश्य-संचालित बिजनेस मॉडल बन सकेंगे।

डरावने पुतले : कबाड़ में तब्दील होती अमरीका के पूर्व राष्ट्रपतियों की प्रतिमाएं

अमरीका के वर्जीनिया में एक स्थान पर जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक 43 अमरीकी राष्ट्रपतियों की जीर्णशीर्ष प्रतिमाएं देखकर एक बार डर का अहसास होता है। 18 से 20 फीट की कुछ प्रतिमाओं की नाक टूटी हुई है, तो कई प्रतिमाओं की आंखों से आंसू जैसे दाग गिर रहे हैं। सभी के सिर कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हैं। कभी इनको विलियम्सबर्ग के पास यार्क काउंट के प्रेसिडेंट्स पार्क में प्रदर्शित किया गया था। प्रेसिडेंट्स पार्क 2004 में विलियम्सबर्ग में खोला गया था, जो स्थानीय जमींदार एवरेट हेली न्यूमैन और ह्यूस्टन के मूर्तिकार डेविड एडिकेस के दिमाग की उपज था। दर्शकों की कमी से यह पार्क 2010 में पार्क बंद हुआ और इसे बेचने का विचार आगे बढ़ा। यहीं पर पार्क बनाने में मदद करने वाले हैंकिंस की भूमिका सामने आती है। जमीन की नीलामी से पहले, न्यूमैन ने उनसे प्रतिमाओं को नष्ट करने के लिए कहा। लेकिन हैंकिंस को यह सही नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने इन प्रतिमाओं को अपने 400 एकड़ के खेत में ले जाने की पेशकश की, जिस पर सहमति बन गई। दूसरे स्थान पर ले जाते समय ये प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गईं।

अब सुननी होगी विपक्ष की बात

ओम नारायण खन्ना

इस बार लोकसभा चुनावों के परिणामों ने सभी को चौंकाया है। मतदाताओं की परिपक्वता की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम ही है। इन परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में न तो तानाशाही कोई जगह बना सकती है और न ही लोकतंत्र को किसी तरह का खतरा है। मतदाताओं ने बीजेपी को अकेले बहुमत से दूर रखा, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में ही एनडीए को सत्ता सौंप कर अपना संदेश दे दिया।

इस बार प्राप्त चुनाव परिणामों से देश की जनता के कुछ स्पष्ट निर्देश जरूर दृष्टिगोचर हुए हैं और इन निर्देशों पर हर राजनीतिक दलों व नेताओं को मंथन करना ही होगा। जनता को अब लुभाया नहीं जा सकता। वह झूठे आश्वासनों और वादों को सुनते-सुनते ऊब गई है। सत्ता पाने के लिए दिए जाने वाले प्रलोभनों और वादों को समझने लगी है। कोई भी दल या नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो लेकिन उसे विनम्र बना रहना चाहिए। एक तबका यह मान रहा है कि बीजेपी के नेताओं के अहंकार के कारण ही लोकसभा चुनावों के परिणाम ऐसे आए हैं। 2014 और 2019 में विपक्ष एकजुट नहीं हुआ। अलग-अलग चुनाव लड़ने के कारण भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाया। इस सच्चाई को समझकर इस बार विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे और भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करने में कामयाब हो गए। जिस तरह एकजुटता दिखाकर विपक्ष ने चुनौती दी है, उससे विपक्ष की आवाज को अब आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इससे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका नजर आएगी। भाजपा को बहुमत नहीं मिलने के कारण अब पूर्व की भांति कड़े निर्णय आसान नहीं हो पाएंगे। मोदी सरकार को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में कुछ देरी संभव है। कुल मिलाकर इस बार जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, उससे देश में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा।

(ईमेल पर प्राप्त आलेख)

सामयिक : दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक मेक्सिको सिटी में पेयजल किल्लत

शहरी विस्तार से बढ़ा जल संकट, मेक्सिको सिटी भी चपेट में

विश्व के विभिन्न देशों में शहरी विस्तार और जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। मेक्सिको सिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। झीलों को सुखा दिया गया ताकि शहर के लोगों के लिए भूमि मिल सके। भूमि पर कंक्रीट के जाल बिछा दिए गए जिससे बरसात के पानी को सोखने की धरती क्षमता कम हो गई। पूर्व-कोलंबियाई नहरों और तटबंधों को इस आधार पर खत्म कर दिया गया क्योंकि यह माना गया कि उनकी मौजूदगी शहर के भीतर थी। नदियों के प्रवाह में दखल दिया गया। बेशक, शहर की बढ़ती आबादी के लिए पानी की आवश्यकता थी। योजनाकारों को पानी की जरूरत महसूस हुई। बड़े पैमाने पर, उन्होंने इसका हल भूमिगत स्रोत के रूप मे तलाशा। पानी का दोहन रिचार्ज करने की क्षमता से ज्यादा किया गया।

शहर में भूजल स्तर काफी गिर गया और आज हालत यह है कि मेक्सिको सिटी और उसके आसपास होने वाली बारिश का ज्यादातर पानी ड्रेनेज के जरिए बह जाता है। झीलों का पारिस्थितिकी तंत्र जो कभी लगभग 600 वर्ग मील को कवर करता था, आज बहुत कम है। यह शहर आज हर साल पुनर्भरण की तुलना में दो गुना पानी का दोहन करता है। ऐसी समस्या जो ताजा कठिनाई की वजह बनी है, वह है तीन साल के सूखे के कारण बांधों की जल आपूर्ति क्षमता अब बमुश्किल 27 फीसदी है। पहले शहर को लगभग एक चौथाई पानी 100 मील दूर के बांधों से मिलता था। ऐसा अनुमान है कि शहरीकरण में एक हेक्टेयर की बढ़ोतरी से हर साल लगभग 6,60,000 गैलेन भूमिगत जल कम हो जाता है। शहर का विस्तार हर साल 3 फीसदी ज्यादा की दर से हो रहा है। भूमि धंसने से पाइप फट रहे हैं और लगभग 40 फीसदी पानी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है। पुरानी नहरों को बहाल करने और पुरानी नदियों के बहाव को पाइपों से निकालकर उन्हें फिर से पुराने स्वरूप में लाने के बारे में मैंने कई प्रस्तावों के बारे में सुना है। वर्षा जल पुनर्भरण का चलन बहुत बढ़ गया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने छिद्रयुक्त फुटपाथ बनाने का तरीका ईजाद किया था जो बारिश के पानी को नदी में बहने के बजाय सड़क से रिसने देगा। संरक्षणवादियों का एक ऐसा वर्ग है जो यह चाहता है कि शहर सिकुड़ जाएं - बोलचाल की भाषा में कहें तो उनके विस्तार में कमी आए। प्रकृति पर अपने वर्चस्व की मानसिकता के चलते हम ईमानदारी से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास नहीं करते। हालत यह है कि मेक्सिको सिटी में रहने के लिए आए मुझे अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं और मेरे अपार्टमेंट की पानी आपूर्ति कम से कम तीन बार बंद हो चुकी है। मेरी मां सोच रही हैं कि मेक्सिको में बारिश के देवता माने जाने वाले 'ट्लालोक' के नाम पर सामने के आंगन में स्थित टैंक में एक गैजेट स्थापित कर लिया जाए ताकि वर्षा जल को समेटा, फिल्टर और स्टोर किया जा सके। पानी से भरे टैंकरों की सड़कों पर काफी आवाजाही होती है। ये टैंकर पश्चिम की ढलानों से मेरे चारों ओर की इमारतों, जिसमें रहने वाले लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तक पानी ले जाते हैं। यह जल संकट की गंभीरता को उजागर करता है। कथित तौर पर हम सभी 'डे जीरो' (जब नल के जरिए स्वच्छ पानी तक पहुंच लगभग असंभव हो जाएगी) के मोड़ पर हैं। एक स्थानीय समुदाय की जानकारी के अनुसार, कुछ समय बाद शहर अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

मैं उस समय किशोर वय का भी नहीं था जब तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया (1970 से 1976 तक मैक्सिको के राष्ट्रपति रहे) ने डीप ड्रेनेज सिस्टम (जल निकासी प्रणाली का उद्घाटन किया था, जिसका मुख्य कार्य न केवल सतही जल बल्कि भूजल को भी समेटना था। यह विशाल सुरंगों का 40 मील का नेटवर्क था जिसे सतह के नीचे 200 मीटर तक व्यवस्थित किया गया था। इसे नियमित रूप से आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। बरसात के मौसम में शहर के सबसे निचले इलाकों में काफी मात्रा में कचरा आ जाता था। बरसों पहले मेक्सिको सिटी में पानी की कमी के संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके से पर्याप्त उपाय किए गए थे। यह इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना था। मेक्सिको के औपनिवेशिक शासकों ने एज्टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोच्टिटलान (जिसे अब मेक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है) बनाने का फैसला किया था, जो झीलों वाले एक द्वीप पर केंद्रित थी। ये झीलें आसपास के पहाड़ों से मैक्सिको की घाटी में बहने वाली नदियों के नेटवर्क का अंतिम पड़ाव थीं। अमरीका में कोलंबस के आगमन से पहले, मेक्सिको के लोग ऊंचाई पर पक्की सड़कों और तटबंधों का निर्माण करते थे ताकि झीलों से बहकर आने वाले जल स्तर को व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने दक्षिण में बड़े तैरते द्वीपों पर फसलों के उत्पादन के लिए एक प्रणाली विकसित की थी। बरसात के दिनों में अतिरिक्त पानी उत्तर में वेटलैंड की ओर बह जाता था। अब यहां के हालात लगातार विकट हो रहे हैं।

एडुआर्डो पोर्टर
स्तंभकार और कई पुस्तकों के लेखक
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

एक ऐसा वर्ग है जो यह चाहता है कि शहर सिकुड़ जाएं - बोलचाल की भाषा कहें तो उनके विस्तार में कमी आए। प्रकृति पर अपने वर्चस्व की मानसिकता के चलते हम ईमानदारी से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास नहीं करते और खुद भी संकट में फंस रहे हैं।

सहयोग की जरूरत

कार्यस्थल पर अपना पूरा समय देने के बाद महिलाएं घर की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पातीं। इसलिए दोनों में समन्वय नहीं हो पाता। इसके लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लचीला रुख अपनाना चाहिए। साथ ही घर संभालने में भी परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

-सुनीता उदयवाल, कोटा

आपकी बात

आत्मनिर्भर बनाया जाए

महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाए। महिलाओं के शोषण और भेदभाव पर अंकुश लगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए, जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण भी होगा।

-सतीश उपाध्याय, मनेंद्रगढ़ एमसीबी, छत्तीसगढ़

आज का सवाल

शहरों के विस्तार के कारण किस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता कैसे दूर हो सकती है?' कई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

इसे स्कैन करें

rb.gy/g9hefp

चिंतन

ईवीएम की प्रमाणिकता को लेकर बहस बंद हो

भारतीय ईवीएम पर राजनीतिक बहस खत्म होनी चाहिए। भारतीय स्वदेशी तकनीक पर सबको भरोसा होना चाहिए। ईवीएम की सत्यता, प्रमाणिकता और तकनीकता को लेकर किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ईवीएम की तकनीक को लेकर अनेक बार प्रमाणिक सफाई दे चुका है, आरोप लगाने वाले दलों को अपने आरोपों को तकनीकी रूप से सिद्ध करने का अवसर दे चुका है। सुप्रीम अदालत में ईवीएम-वीवीपैट मामले पर तार्किक जिरह हो चुकी है, इसके बावजूद देश में हर चुनाव के वक्त विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाना एक ट्रेंड बन गया है, चाहे फैसला जो भी हो। ईवीएम पर विवाद करना अपनी स्वदेशी तकनीकी उपलब्धि पर संदेह जताना है। अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क ने एआई से ईवीएम को हैक करने को लेकर जो भी बयान दिया है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ईवीएम किसी भी बाहरी तकनीक से कंट्रोल्ड नहीं है, इसलिए इंटरनेट आधारित किसी भी तकनीक से ईवीएम को न हैक किया जा सकता है, न संचालित और न नियंत्रित किया जा सकता है। ईवीएम एक सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर है, जो किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है, किसी से कनेक्ट नहीं है, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट से जुड़ा नहीं है। यानी हैक या नियंत्रण को कोई रास्ता ही नहीं है। ईवीएम फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर है, जिसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह सुरक्षित है। चुनाव आयोग ने एलन मस्क के बयान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व सपा सांसद अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी भी अन्य डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहता है। इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर की मामली वोटों से जीत के बाद उनके रिश्तेदार के खिलाफ मोबाइल मतगणना केंद्र पर पहुंचाने व संदिग्ध स्थिति में रखने के आरोप को लेकर केस दर्ज किया गया है, जिसकी महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद चुनाव आयोग भी जांच करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में होना है, वहां इंटरनेट आधारित ईवीएम को लेकर बहस जारी है, अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होता है। उन्होंने अमेरिकी सरकार को मत पत्र से ही चुनाव कराने की सलाह दी है और इसी संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से ईवीएम के हैक व कंट्रोल्ड करना संभव है, जैसा बयान दिया हो, उन्हें डर हो कि कहीं अमेरिका भारतीय ईवीएम के जरिये न चुनाव कराने का विचार करे। दूसरा कारण भी हो सकता है, पश्चिम ने कभी भी भारतीय तकनीक को दिल से नहीं स्वीकारा है। ईवीएम भारत में जेनरेटेड है, यह एक फुलप्रूफ तकनीक है, इसकी गुणवत्ता को पश्चिम के लिए स्वीकारना मुश्किल रहता है। ईवीएम पर एलन मस्क के बयान को इन दोनों ही संदर्भ में देखा जा सकता है। चिंता तब होती है, जब किसी पश्चिमी विदेशी के द्वारा भारतीय ज्ञान या उपलब्धि या व्यवस्था के खिलाफ अनर्गल आलाप किया जाता है तो हमारे देश के विपक्षी नेता बिना परीक्षण किए, उसके मकसद को समझे सुर में सुर मिलाने लगते हैं। राहुल गांधी व अखिलेश यादव को तथ्यात्मक रूप से सही बातें ही कहनी चाहिए। ईवीएम पर विवाद का अंत होना चाहिए, भारतीय को अपनी तकनीक पर भरोसा होना चाहिए।

मौद्रिक समीक्षा
सतीश सिंह

महंगाई-विकास में संतुलन की पहल

महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने के लिए ताजा मौद्रिक समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के दर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। रिजर्व बैंक रेपो दर में बढ़ोतरी करके महंगाई से लड़ने की कोशिश करता है। जब रेपो दर अधिक होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके कारण बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है और लोगों की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से वस्तुओं की मांग में कमी आती है और वस्तुओं व उत्पादों की कीमत अधिक होने के कारण इनकी बिक्री में कमी आती है, जिससे महंगाई में गिरावट दर्ज की जाती है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में नरमी रहने पर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है और रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर कर्ज मिले और सस्ती दर पर कर्ज मिलने के बाद बैंक भी ग्राहकों को सस्ती दर पर कर्ज दे।

मौजूदा समय में महंगाई दर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केयर एज रेटिंग के अनुसार कर्ज दर के नरम नहीं होने के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि दर 16 प्रतिशत के आसपास रही है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 14 से 14.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही सकारात्मक है। हालांकि, इसे अपवाद वाली स्थिति कहा जा सकता है। बहरहाल,कर्ज देने की रफ्तार में तेजी बनी रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों और विकास दर दोनों में तेजी आ रही है। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत रही थी। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है यानी रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत लगाया था। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन से आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में माइनस 2.2 प्रतिशत रही थी। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9 प्रतिशत रही थी। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खुदरा महंगाई अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है और अनुमान है कि गर्मियों में खुदरा महंगाई में बहुत ज्यादा नरमी नहीं आएगी। वैसे, सर्दी के मौसम में इसमें कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का

अनुमान जताया है, लेकिन यह स्तर विकास के लिए निर्णायक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मई महीने में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि फरवरी 2023 में यह 3.85 रही थी। वहीं,अप्रैल 2024 में यह 1.26 प्रतिशत रही, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। मार्च 2024 में यह 0.53 रही और फरवरी महीने में 0.20 प्रतिशत। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 जून 2024 को खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी किया था, जिसके अनुसार मई महीने में खुदरा महंगाई 4.75 प्रतिशत रही, जो 12 महीने का निचला स्तर था। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी आई थी, लेकिन वह मई महीने से थोड़ी अधिक 4.83 प्रतिशत के स्तर पर थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई 4.81 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई 2023 में यह 4.44 प्रतिशत रही थी।

महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6 प्रतिशत है, तो अर्जित किए गए 100 रुपये का मूल्य सिर्फ 94 रुपये होगा, इसलिए महंगाई के स्तर के अनुरूप निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रतिफल कम मिलेगा। महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे और ज्यादा उत्पाद खरीदने से मांग बढ़ेगी और मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं होने पर उत्पादों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह, बाजार महंगाई के दुष्चक्र में फंस जाएगा। बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या उत्पाद की कमी महंगाई का कारण बनता है। वहीं,अगर मांग कम होगी और आपूर्ति ज्यादा होगी तो महंगाई कम होगी। ग्राहक खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं और बाजार में मौजूद उत्पादों की कीमत में हुए बदलाव को मापने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) करता है। उत्पाद और सेवाओं के लिए जो औसत मूल्य चुकाया जाता है,सीपीआई उसी को मापता है।कच्चे तेल, उत्पादों की कीमतों, निर्माण की लागत के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जो खुदरा महंगाई दर को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में लगभग 300 उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है। इस तरह, किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे व्यक्ति की खरीदारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम होती है। फिर,उनकी बिक्री कम हो जाती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और विकास की गति बाधित होती है।

विगत कुछ महीनों से उधारी ब्याज दर के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद भी ऋण वितरण में तेजी आ रही है और विकास दर की रफ्तार भी तेज बनी हुई है। वैसे, ऐसी स्थिति अपवाद वाली है। एचएसबीसी इंडिया का पीएमआई आंकड़ा मई 2024 में 57.5 पॉइंट रहा, जो अप्रैल महीने में 58.8 प्वाइंट रहा था, वहीं, कंपोजिट पीएमआई मई 2024 में 60.50 पॉइंट था, जो अप्रैल 2024 में 61.50 प्वाइंट रहा था। आंकड़ों से साफ आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है।

भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है,ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।

(लेखक बैंक अधिकारी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने के लिए ताजा मौद्रिक समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6 .5 प्रतिशत के दर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। रिजर्व बैंक रेपो दर में बढ़ोतरी करके महंगाई से लड़ने की कोशिश करता है। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई पर केंद्रीय बैंक संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है।

सारा संसार

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित रॉकफोर्ट उच्ची पिल्लयार कोइल मंदिर एक और ऐसा प्रसिद्ध गणेश मंदिर है जो पहाड़ी की चोटी पर विराजित है और हिन्दुओं के बीच काफी महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान
डॉ. मोनिका शर्मा

प्रकृति संरक्षण की मुहिम

मरुस्थल बनती धरती पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उजड़ती हरियाली से न केवल तपिश बढ़ रही है,बल्कि बढ़ते प्रदूषण ने भी जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में पेड़ लगाना और सहेजना ही धरती के रंग और इंसानों का जीवन बचा सकता है। हवा में घुलते जहर, बढ़ते तापमान और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटते वृक्षों से पैदा हो रहे पर्यावरण असंतुलन से मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही है। हाल ही में देशवासियों से अपने ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान देने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरुआत की है। इस मुहिम का व्यावहारिक पक्ष यह है कि यह पेड़ लगाने की औपचारिकता पूरी करने भर से नहीं बल्कि रोपे गए पौधे को पोसने के भाव से भी जुड़ी है। हर साल बड़ी संख्या में वृक्षारोपण के बावजूद पालने-पोसने के प्रति गंभीरता न रखने के कारण बहुत से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में वृक्षारोपण अभियान के साथ भावनात्मक जुड़ाव का भाव होना पेड़ लगाने के बाद उसे बचाने में भी मददगार साबित होगा। इसी भाव को बल देने वाली मुहिम को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि 'मैंने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवनशैली अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप भी हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।' विचारणीय है कि वृक्षारोपण के सामूहिक प्रयास सदा से अहम रहे हैं पर वृक्षारोपण का सद्विचार ही काफी नहीं है। समस्या लगाए गए पेड़-पौधों की देखभाल के प्रति गंभीर न रहने की ज्यादा है। कभी रोपे गए पौधे सिंचाई के अभाव में या तो सूख जाते हैं तो कभी मवेशी खा जाते हैं। संबन्धित विभागों की लापरवाही के कारण बाकायदा अभियान चलाकर रोपे गए पेड़ भी सूख जाते हैं, जबकि वन क्षेत्रों में नहीं गांवों-शहरों में भी निर्माण कार्यों के कारण पेड़ों की कटाई निरंतर जारी है। एक ओर बढ़ती आबादी के कारण शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है तो दूसरी ओर गांवों-कस्बों में भी जमीनी जीवनशैली में बदलाव आया है। ध्यातव्य है कि वन विभाग की ओर से हर वर्ष नर्सरी तैयार कर वन क्षेत्रों में पौधे रोपे जाते हैं, पर लक्ष्य से दोगुनी संख्या में पौधे रोपने बावजूद काटे जा रहे पेड़ों की तुलना में नए पेड़ कम ही लग पाते हैं, जिसके कारण वन क्षेत्र संरक्षित करना भी आसान नहीं है, पर भारत में वन हानि रोकने के प्रयास गंभीरता से किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस अभियान जुड़कर लोग शहरी क्षेत्रों में बची खाली जगहों, उद्यानों और अपने घर के आंगन को हराभरा बनाकर प्रकृति संरक्षण में भागीदार बन सकते हैं। असल में प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण खत्म हो रही हरियाली को पोसने के मोर्चे पर पौधरोपण संग निजी जुड़ाव और जवाबदेही का यह भाव वाकई सहायक सिद्ध हो सकता है। अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने को प्रेरित करने वाला यह अभियान वृक्षों को बचाने वाली व्यावहारिक और प्रेरणादायी पहल है। धरती माता के आंगन को हराभरा रखने वाली संवेदनासिक्त मुहिम है। समझना मुश्किल नहीं कि अपनी माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में वृक्ष रोपने वाला हर इंसान उसे सहेजने के भी पूरे प्रयास करेगा। यह मानवीय मन का बहुत व्यावहारिक सा पक्ष है कि व्यक्तिगत जुड़ाव के बाद संरक्षण का भाव और प्रबल हो जाता है। यही जुड़ाव प्रकृति को संरक्षित करने वाले भाव-चाव का कभी ना डिगने वाला आधार बन सकता है।

(लेखिका फ्रीलांसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पूजा वह है, जो परिपूर्णता से उत्पन्न हो

संकलित
दर्शन

यजमान को देश-काल के सातत्य में उसके जन्म के नक्षत्र, जन्म राशि, पैतृक वंश, गोत्र, पूरा नाम, पिता का नाम आदि द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। इसके बाद यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। वस्तुतः संकल्प कभी लिया नहीं जाता, बल्कि उसे छोड़ दिया जाता है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। जब यजमान पूर्ण विश्वास के साथ अपना संकल्प देवत्व के चरणों में छोड़ देता है कि जो भी उसके लिए सही होगा, वह अवश्य होगा, वह पूजा में बैठने के योग्य हो जाता है। पूजा वह है, जो परिपूर्णता से उत्पन्न होती है। जब आप अपनी सभी इच्छाओं, सभी परेशानियों और शिकायतों को दिव्यता के चरणों में छोड़ देते हैं, तभी आप परिपूर्ण प्रतीत कर सकते हैं। तभी आप पूजा में बैठने लायक बन सकेंगे। तभी आप पूजा का हिस्सा बन सकते हैं। रुद्र पूजा में शिव-तत्व का उसकी पूरी भव्यता के साथ आह्वान किया जाता है। भक्त मंत्रों की तरंगों में डूब जाते हैं। मन ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। संपूर्ण वातावरण शिव-तत्व से आवेशित हो जाता है। भक्त शिव-तत्व के साथ एक हो जाते हैं। शिव वह परोपकारी ऊर्जा हैं, जो परिवर्तन करती है और बाधाओं को दूर करती है। संकल्प आसानी से सर्वव्यापी दिव्यता तक संप्रेषित हो जाते हैं और उस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान दिव्यता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सभी हितकारी मनोरथ फलदायी होते हैं। सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन गतिमान होता है।

जमींदार और मजदूर के कर्म का फल

संकलित
प्रेरणा

एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हुई। दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहाः आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहाः अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहां रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहाः भगवन, आप ने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूं। प्रतिदिन मंदिर जाता था। देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें दान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछाः तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहाः भगवन, मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहां से जितना मिलता था, उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल होता तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने-जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। धर्मराज ने जमींदार से कहाः आपने सुन ली न मजदूर की बात? भगवान धन-दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

विवादों में नीट परीक्षा परिणाम

इस साल नीट परीक्षा विवादों में है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार और नीट आयोजित करने वाली संस्था पर घोटाले और गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। अब इस पर भी सियासत होने लगी है। वहीं जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को गलत बताया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है और इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई भी होगी, लेकिन इसे राजनीतिक विवाद का विषय बनाना गलत है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विषय में क्या कदम उठाती है ताकि भविष्य में छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और पढ़ाई से उनका ध्यान न भटके। *-विपिन नागरे, रायगढ़*

ट्रेंड

स्वास्थ्य संकट पर चिंतित

वेस्ट बैंक, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ वहां के बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बारे में चिंतित है, जहां स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर हमले और आंदोलन पर बढ़ते प्रतिबंध स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधा डाल रहे हैं।

-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

ट्रैक पर रहना होगा

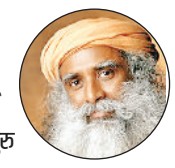

यदि आप सचेत हैं कि आप नश्वर हैं, तो कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने का समय नहीं है। आपको ट्रैक पर रहना होगा। आध्यात्मिक पथ का सबसे बुनियादी पहलू अपने आप से सौ प्रतिशत सीधा होना है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

नागरिकता का मार्ग मिला

आज से बारह साल पहले, मेरे प्रशासन ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम या डीएसीए की घोषणा की थी, जिससे बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों को, जिन्हें बचपन में इस देश में लाया गया था, नागरिकता का मार्ग मिल गया।

-बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

फिर भी बहुत अधिक

हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम, हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है।

-एलन मस्क, उद्योगपति

करंट अफेयर

भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आत्मचिंतन का समय

भारत में हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों के परिणामों पर निराशा व्यक्त करते हुए एक प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी ने शनिवार को कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के लिए आत्मचिंतन का समय है न कि जीत का जश्न मनाने का। 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा यूएसए' द्वारा आयोजित विजय समारोह के दौरान डॉ. भरत बरई ने पार्टी के सदस्यों से कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने भारत में जो काम किया है उसके लिए उन्हें 400 सीट मिलनी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब सवाल यह है कि क्या हमें आत्मचिंतन करने की कोशिश करनी चाहिए, यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ?' उन्होंने कहा, 'अगर हम सिर्फ जश्न मनाते रहेंगे तो अगली बार यह सुनने को मिलेगा कि महाराष्ट्र से भाजपा बाहर हो चुकी है। इसलिए, हमारे लिए यह आत्ममंथन करना बेहद जरूरी है कि 400 सीट मिलने के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सिर्फ 292 सीट ही क्यों मिलीं? और पिछले चुनावों में जब भाजपा पूर्ण बहुमत में थी तो इस बार 240 सीट ही क्यों मिलीं?' डॉ. बरई ने कहा, 'इसलिए हमें अब बधाई देने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए और इससे हमें यह रणनीति बनाने में मदद मिलेगी कि अगली बार हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए।'

ऑफ बीट

मीठे पानी के स्त्रोत कर रहे संकट का सामना

मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक दुनिया की जीवनरेखा हैं, फिर भी वह संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि 1970 के बाद से वैश्विक मीठे पानी की कशेरुकी आबादी में 83 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जो किसी भी अन्य आवास की तुलना में कहीं अधिक है। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपसमूह हैं। इनमें झीलें, तालाब, नदियां, धाराएं, झरने, दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं। उनकी तुलना समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों से की जा सकती है, जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। मीठे पानी के आवासों को तापमान, पोषक तत्वों और वनस्पति सहित विभिन्न कारकों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति के क्षरण का स्तर चिंताजनक है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जटिल है। साथ ही मानवीय गतिविधियों के प्रभाव भी जटिल हैं। हमारे शोध से पता चलता है कि पर्यावरणीय डीएनए (ईडीएनए) का विश्लेषण करके मीठे पानी की धाराओं, नदियों और झीलों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। इससे इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की अधिक कुशल निगरानी की उम्मीद जगती है। मछलियां और पक्षी आमतौर पर सुर्खियों में रहते हैं। उन पर दशकों से निगरानी रखी जा रही है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com